44वीं वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं
नीति संस्थान

44वीं वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली

1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020

मुद्रण एवं प्रकाशन
सचिव

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान)
18/2, सत्संग विहार मार्ग,
स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू)
नई दिल्ली 110067
दूरभाष : 011 26569303, 26569780, 26569784
फैक्स : 91-11-26852548
ईमेल : nipfp@nipfp.org.in वेबसाइट: www.nipfp.org.in

सम्पादन : अमिता मनहास
डिजाइन एवं कवर आर्ट : रोहित दत्ता

मुद्रक : निखिल ऑफसेट
ईमेल : nikhil223@yahoo.com
दूरभाष : 9811950040

विषय सूची

प्रस्तावना 4

अनुसंधान क्रियाकलाप 9

निष्पादित अध्ययन 9

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए की गयी शोध गतिविधियां.....9

वित्त मंत्रालय के लिए की गयी शोध गतिविधियां 10

अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के लिए की गयी शोध गतिविधियां.....12

चल रही परियोजनाएं.....15

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए चल रही शोध गतिविधियां.....15

वित्त मंत्रालय के लिए चल रही शोध गतिविधियां 18

अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के लिए चल रही शोध गतिविधियां 19

नयी परियोजनाओं की पहल 24

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए प्रारंभ शोध गतिविधियां.....24

वित्त मंत्रालय के लिए प्रारंभ गतिविधियां.....25

अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के लिए प्रारंभ शोध गतिविधियां.....25

कार्यशालाएं, बैठकें तथा सम्मेलन 26

प्रशिक्षण कार्यक्रम 28

प्रकाशन एवं संचार 29

पुस्तकालय तथा सूचना केंद्र 30

ई-संसाधन 32

पुस्तकालय :कर्मचारी गतिविधियां **(2019-20)** **35**

कमप्यूटर सेंटर.....**36**

संकाय क्रियाकलापों के मुख्यअंश.....**37**

अनुलंग्नक.....**72**

अनुलंग्नक– **I** अध्ययनों की सूची **2017-18**.....**73**

निष्पादित परियोजनाएं 73

चल रही परियोजनाएं.....76

नयी परियोजनाओं की पहल.....81

अनुलंग्नक – **II** रा लो वि नी सं कार्यशील पेपर श्रृंखला.....**82**

अनुलंग्नक – **III** आंतरिक सेमिनार श्रृंखला.....**85**

अनुलंग्नक– **IV** शासी निकाय के सदस्यों की सूची **86**

अनुलंग्नक –**V** मूल्य अंकित प्रकाशनों की सूची.....**91**

अनुलंग्नक – **VI** रा लो वि नी सं संकाय सदस्यों की प्रकाशित सामग्री **96**

अनुलंग्नक –**VII** स्टाफ सदस्यों की सूची *(*दिनांक **31.3.2020** तक*)*.....**106**

अनुलंग्नक –**VIII** प्रायोजकों, कारपोरेट, स्थाई एवं साधारण सदस्यों की सूची *(*दिनांक ***31.3.2020*** तक*)*.....**112**

अनुलंग्नक – **IX** वित्त एवं लेखा **113**

प्रस्तावना

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली की 44 वीं वार्षिक रिपोर्ट संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए कार्यों तथा शासी निकाय एवं जनता के प्रति अपनी उत्तरदेयता की प्रस्तुति है। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए क्रियाकलापों का विवरण निम्न प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान तथा पूर्व वार्षिक रिपोर्टों की डिजिटल प्रति संस्थान की वेबसाइट[1] पर प्राप्त की जा सकती है।

संस्थान का परिचय

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान एक लोक अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान केन्द्र है। वर्ष 1976 में स्थापित यह संस्थान लोक अर्थशास्त्र से सम्बंद्ध अनुसंधान, नीति प्रतिपालन एवं क्षमता निर्माण के कार्य कर रहा है। इस संस्थान को सौंपे गए कार्यों में एक प्रमुख कार्य विश्लेषणात्मक आधार उपलब्ध करवाकर लोक नीतियों के निर्माण एवं उनमें सुधार के कार्य में केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय प्रशासन को सहायता प्रदान करना है। इस संस्थान की स्थापना वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, अनेक राज्य सरकारों तथा विख्यात अकादमियों के संयुक्त प्रयासों से एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है।

अपनी स्थापना के 44वें वर्ष में यह संस्थान भारत के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में उभरा है तथा इसके द्वारा सरकार में सभी स्तरों पर नीति सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के क्रियात्मक कार्यों से इसकी निकट सम्बद्धता स्थापित है तथा भारत एवं विदेश में स्थित अन्य अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थानों से भी इसका जुड़ाव बना हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान प्राप्त होने के बावजूद भी अनुसंधान एवं नीति लक्ष्य के कार्यों में एक गैर-सरकारी संस्थान की इसकी छवि बनी हुई है।

शासी निकाय

संस्थान के शासी निकाय द्वारा दिनांक 18 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में आगामी चार वर्षों अर्थात 5 अप्रैल, 2020 से 4 अप्रैल, 2024 तक की अवधि के शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया था। डॉ उर्जित पटेल शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। डा. विजय केलकर ने 22 जून 2020 को अपने पद से त्याग पत्र दिया था । श्री सुमित बोस ने उपाध्यक्ष पद से 31 जुलाई 2020 को त्याग पत्र दिया था ।

वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व श्री अजय भूषण पांडे, राजस्व सचिव; श्री तरुण बजाज, सचिव (आर्थिक कार्य); तथा श्री कृष्णामूर्ति सुब्रमणियम, मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का

[1] http://www.nipfp.org.in/publications/annual-reports/

प्रतिनिधित्व डा. राजीव रंजन, सलाहकार एवं कार्यालय प्रभारी, आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग द्वारा किया गया है। नीति आयोग का प्रतिनिधित्व सुश्री अन्ना राय, सदस्य द्वारा किया गया है।

प्रायोजक राज्यों के प्रतिनिधि निम्नांकित हैं : श्री समीर कुमार सिन्हा , आई ० ए ० एस , प्रधान सचिव , असम सरकार , श्री राजेश कुमार सिंह , आई ० ए ० एस , अपर मुख्य सचिव, केरल सरकार और श्री मनोज सॉनिक, आई ० ए ० एस , अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार. जबकि श्री शमशेर सिंह रावत, प्रधान वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार ; श्री आई.एस.एन. प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार; तथा श्रीमती स्मारकी महापात्रा, सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया है ।

श्री प्रसन्ना बी , वैश्विक प्रमुख - बाज़ार (विपणन , व्यापर एवं अनुसंधान) आईसीआईसीआई बैंक द्वारा नामित किए गए हैं, डॉ निरंजन हीरानंदानी, अध्यक्ष, एसोसिएटिड चेम्बर ऑफ कार्मस एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया से; तथा डॉ संगीता रेड्डी, अध्यक्ष, फिक्की संस्थान से नामित किए गए हैं।

शासी निकाय में दो विख्यात अर्थशास्त्री डा. शैबल गुप्ता, एशियन डेवलमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआई); तथा डॉ माला लालवाणी , प्रोफेसर , मुंबई विश्वविद्यालय शामिल हैं। डा. सुदिप्तो मंडल तथा डा. ईरोल डिसुजा, प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ने शासी निकाय मे अपनी कार्य अवधि पूरी कर ली है ।

सहयोगी संस्थानों से डा. शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर तथा सुश्री यामिनी अय्यर, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी, सेंटर फार पालिसी रिसर्च का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। सी.ए. तरूण जे. घिया, परिषद सदस्य, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को शासी निकाय में सहयोजित सदस्यता प्रदान की गई है। डॉ निर्मल्य बागची, महानिदेशक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कॉलेज ऑफ इंडिया ने शासी निकाय मे अपनी कार्य अवधि पूरी कर ली है ।

डा. रथिन रॉय, जो शासी निकाय के पदेन सदस्य थे , निदेशक पद के कार्यभार से 31 अगस्त 2020 को पद मुक्त हुए। डॉ पिनाकी चक्रबर्ती निदेशक पदेन सदस्य सचिव हैं; तथा डा आर. कविता राव, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी अपनी बारी से संकाय का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

शासी निकाय के विशेष अतिथि श्री प्रमोद चन्द्र मोदी, अध्यक्ष, सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय तथा एम अजीत कुमार, अध्यक्ष, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं। (विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है)

निष्पादित एवं जारी परियोजनाएं

गत वर्ष के दौरान हमारे अनुसंधान लक्ष्य : कराधान एवं राजस्व, लोक व्यय एवं वित्त प्रबंधन, समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे, सरकारों के मध्य वित्तीय संबंध तथा राज्य योजना एवं विकास के प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर रहे दलों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, संस्थान ने उप-राष्ट्रीय स्तर पर मांग-आधारित अनुसंधान और क्षमता-निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए राज्यों के साथ अपने जुड़ाव को व्यापक बनाया है। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और राजस्थान के साथ विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से निरंतर जुड़ाव गहरा हुआ ।

संस्थान ने लोक वित्त के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय साझेदारों में विकासशील देशों के साथ काम करने के लिए अपने क्षितिज का विस्तार किया। दक्षिण अफ्रीका के राजस्व आवंटन आयोग (सीआरए), केन्या और वित्तीय आयोग (एफएफसी), दक्षिण अफ्रीका ने लोक वित्त और राजकोषीय संघवाद में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में एनआईपीएफपी के साथ सहयोग जारी है । लोक वित्त प्रबंधन में पारस्परिक हित के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए फेडरेशन, हाउस ऑफ फेडरेशन, इथियोपिया और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, बांग्लादेश के साथ नई साझेदारी पर हस्ताक्षर किए । हमारे लोक वित्त और मानव विकास पर कार्य ने स्वास्थ्य वित्तपोषण के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और गुजरात कुछ ऐसे राज्य थे, जिनके डेटा का विश्लेषण हमारी अनुसंधान टीम ने किया ताकि इन राज्यों की राजस्व क्षमता को समझने के लिए स्वास्थ्य व्यय के लिए राजकोषीय स्थान का परिसीमन किया जा सके।

हमने अपने कार्यों के माध्यम से लिंग आधारित बजट निर्धारण एवं लिंग समानता के प्रति अपने योगदान को जारी रखा है। इसके अलावा, एनआईपीएफपी द्वारा अनेक ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों के संबंध में अनेक अध्ययन किए है जैसे खाद्य मूल्य अस्थिरता, भारत में डेटा का स्थानीयकरण, डिजीटलाइजेशन के परिणामस्वरूप उत्पन्न कर चुनौतियां, प्रवासन से संबंधित वित्तीय दबाव जिनका समाधान कड़े नीतिगत अनुसंधान से हो सकता था। हमारे प्रकाशित अध्ययन भारत में सूक्ष्म स्तरीय मूल्य निर्धारण व्यवहार, खाद्य स्फीति, ऋणों एवं न्यूनताओं के प्रति लक्ष्यबद्ध संरचित सूक्ष्म इकोमैट्रिक एप्रोच, एमटीईएफ को अंगीकार करना तथा भारतीय में बहु-परतीय बजट योजना के अनुभव जैसे विविध प्रकार के अनुसंधानों में विस्तारित किया गया है।

हमने राज्य स्तरीय वित्त प्रबंधन को सूक्ष्मता से अनुश्रवित करना जारी रखा है तथा अब हम राज्य स्तरीय वित्त डेटा बैंक, जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। राज्य वित्त के संबंध में प्रस्तुत मुद्दों पर आयोजित हमारे वार्षिक सेमिनारों में राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय एवं निजी क्षेत्र के अर्थशात्रियों सहित समग्र नीतिगत तंत्रव्यवस्था ने अपनी रूचि दर्शाई है। गत वर्ष के दौरान राज्य वित्त से संबंधित विविध प्रकार के विषयों पर अपने अध्ययन अनुसंधान प्रकाशित किए हैं। पंद्रहवे वित्त आयोग के अनुरोध पर उनके लिए अनुसंधान किया है।

हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्पूर्ण भारत तथा अन्य सेवाओं के कनिष्ठ एवं मध्यम स्तरीय अधिकारियों समष्टि अर्थशास्त्र तथा लोक वित्त के सामयिक विषयों की प्रारंभिक जानकारी दिए जाने पर ध्यान दिया जाना जारी रखा गया है। वर्ष के दौरान हमारे द्वारा विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के लिए आयोजित किए जाने वाले लोक अर्थशास्त्र के पुनश्चर्या कार्यक्रम को संचालित किया गया।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साझा अनुसंधान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रमुख कार्यक्रम थे | अनुसन्धान में ऐसे कई मुद्दे समाविष्ट हुए जिनका सन्दर्भ राष्ट्रीय नीति निर्धारण से था।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

रा लो वि नी सं द्वारा वर्ष के दौरान अपने दायित्वों से संबंधित विषयों के निर्वाह के लिए अनेक कार्यशालाओं, बैठकों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया है।

"आरटीई के लिए संसाधन की आवश्यकता: आगे का रास्ता" नामक एक संगोष्ठी एनआईपीएफपी में 12 अप्रैल 2019 को आयोजित की गई | इस संगोष्ठी के बाद एशिया और प्रशांत 2019 के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण: विकास से परे की महत्वाकांक्षाएं पर UNESCAP के सहयोग से 18 अप्रैल 2019 को एक नीति वार्ता हुई ।

रा लो वि नी सं ने बांग्लादेश के वित्त सचिव के अनुरोध पर बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के लिए 10 से 17 जुलाई 2019 के दौरान भारत में कार्यान्वित की जा रही लाइव ब्लॉक चेन परियोजनाओं के लिए एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया। टीम ने तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में नीति आयोग और ई-गवर्नेंस और आईटी विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की। विषय पर अवसरों और चुनौतियों का पहला अनुभव देने के लिए निजी क्षेत्र के कार्यान्वयनकर्ताओं और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाड़ियों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं।

रा लो वि नी सं , सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ और एनसीएईआर द्वारा केंद्रीय बजट 2019-20 और 2020–21 पर दो सेमिनार क्रमशः 22 जुलाई 2019 और 8 फरवरी 2020 को संयुक्त रूप से आयोजित किए गए थे।

राज्य वित्त के मुद्दे : राज्य बजट 2019 -20 के विश्लेषण पर दिनांक 20 अगस्त 2019 को एक सेमीनार का आयोजन किया गया ।

रा लो वि नी सं ने संघवाद पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कोच्चि में 27-29 अगस्त 2019 के दौरान किया। सम्मेलन का उद्देश्य संघवाद के कुछ प्रमुख मुद्दों पर ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच तैयार करना था। सात देशों के प्रतिभागियों ने संघवाद में समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और अपने देश के अनुभवों को साझा किया।

8 नवंबर, 2019 को 'न्यायोचित वित्तीय अंतरण' पर एक दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के ग्रांथम इंस्टिट्यूट के के साथ संयुक्त रूप से आयोजन किया गया ।

अपने सम्बंधित देशों में थिंक टैंक स्थापना के चरणों और चुनौतियों के संबंध में अफगानिस्तान और भूटान की सरकारों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारीयों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र नवंबर 2019 में आयोजित किया गया। यह बैठक UNESCAP के अनुरोध पर आयोजित की गई थी।

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए: **क)** भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) के लिए लोक वित्त पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 8-12 जुलाई 2019; **ख)** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम, 2 – 6 दिसंबर 2019 ; **ग)** शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक अर्थशास्त्र में

दो सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स, 9–20 दिसंबर 2019; **डी)** लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर आईसीएएस प्रोबेशनर्स के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 9–20 दिसंबर 2019; **ई)** बांग्लादेश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए लोक वित्त पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13 -17 जनवरी 2020 ; **फ)** नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, शिमला से 20 से 31 जनवरी 2020 तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (IA & AS) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम; **छ)** इथियोपिया सरकार, हाउस ऑफ फेडरेशन और इथियोपिया, बिश्फोटू, इथियोपिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त विभाग के अधिकारियों के लिए अंतर-सरकारी वित्तीय संबंधों पर दो सप्ताह का विशेषज्ञ प्रमाणन कार्यक्रम, 27 जनवरी -7 फरवरी 2020 ।

आत्म निर्भरता प्राप्ति विषयक रिपोर्ट

रा लो वि नी सं, वित्त मंत्रालय भारत सरकार से मूल स्टाफ के वेतन का नब्बे प्रतिशत वार्षिक अनुदान के रूप में प्राप्त करता है | वेतन व्यय का बाकी भाग एवं अन्य प्रशासनिक व पूंजीगत व्यय संस्था अपने संसाधनों से वहन करती है | अनुदानों के अलावा संस्था परियोजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधन जुटाती है। संस्था के कुल व्यय मे अपने संसाधनों का अनुपात वर्ष 2017-18 मे 61.46% तथा वर्ष 2019-20 मे 72.77% था[2] ।

विकास

डॉ लेखा चक्रवर्ती ने 23 मई, 2019 को प्रोफेसर के रूप में कार्यग्रहण किया ।

डॉ सतद्रु सिकदर ने, 1 जुलाई, 2019 को सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यग्रहण किया ।

डॉ रंजन कुमार मोहंती ने 1 जुलाई, 2019 को सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यग्रहण किया ।

डॉ सुधांशु कुमार, सहायक प्रोफेसर ने 31 अगस्त, 2019 को त्यागपत्र दिया

डॉ शिवा चिदंबरम, एसएलआईओ ने 29 जनवरी, 2020 को त्यागपत्र दिया

श्री जगमोहन सिंह रावत, कार्यकारी अधिकारी, 31 जनवरी, 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुश्री इन्द्रा हसीजा, सहायक, 31 मार्च, 2020 से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

[2] यह वृद्धि मुख्यतः कुछ बड़ी दाता वित्त पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन, संकाय के आठ पदों की रिक्ति , कर्मचारी व्यय मे कटौती से उत्पन्न हुई है।

अनुसंधान क्रियाकलाप

निष्पादित अध्ययन

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए की गयी शोध गतिविधियां

1. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण शासन (PMAY-G) के अभिशासन मापदंडों का मूल्यांकन
   प्रायोजक: विकास मंत्रालय, भारत सरकार
   दल: एन.आर. भानुमूर्ति , एच् के अमरनाथ , भाबेश हज़ारिका, कृष्ण शर्मा, कनिका गुप्ता, तन्वी ब्राम्हे
   लक्ष्य: इस परियोजना में, हमने प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित विभिन्न मुद्दों, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, डिजाइन, कार्यान्वयन और अन्य शासन से संबंधित मुद्दों को देखा। इसके अलावा, इस परियोजना ने यह भी देखा कि इस योजना ने किस हद तक कुशल और अकुशल दोनों तरह के मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।

2. उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के निष्पादन लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए समझौता
   प्रायोजक: नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक (सीएजी)
   दल: अजय शाह, ईला पटनायक , अमय सप्रे, शुभो रॉय, हरलीन कौर, महिमा गुप्ता, मनप्रीत सिंह, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, समीर पेठे, शेफाली मल्होत्रा, सुप्रिया कृष्णन।
   लक्ष्य: रा लो वि नी सं, उत्तर प्रदेश सरकार के अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग पर प्रदर्शन लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सीएजी को परामर्श और ज्ञान सहायता प्रदान करने के लिए बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी है। लेखापरीक्षा के दौरान परामर्श और समर्थन के उद्देश्य से सीoएoजीo के साथ रा लो वि नी सं का जुड़ाव रणनीतिक उद्देश्य विकास प्रदान करना था, लेखा परीक्षा योजना, लेखा परीक्षा निष्पादन और विश्लेषण (मई 2018-जुलाई 2019).

3. "भारत में डिजिटल संचार संवर्धन हेतु ज्ञान भागीदारी के लिए प्रस्ताव: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका" -(सितम्बर 2019 अक्टूबर 2019)
   प्रायोजक: दूरसंचार विभाग
   दल: अजयशाह, ईला पटनायक , स्मृति परशीरा , रिषभ बेली, फ़ैज़ा रहमान, वरुण सेन बहल
   लक्ष्य: इस कार्य के तहत हमसे निम्नलिखित गतिविधियां अपेक्षित थीं :
   1. "प्रॉपेलिंग डिजिटल कम्युनिकेशंस इन इंडिया: द रोल ऑफ एफडीआई 'पर रिपोर्ट तैयार करना
   2. सेमिनार के लिए सत्र डिजाइन, विषयों और संभावित वक्ताओं पर इनपुट प्रदान करना
   3. उद्घाटन, मुख्य और मंत्रिस्तरीय भाषणों के लिए इनपुट प्रदान करना

4. ट्राई - एन आई पी एफ पी रिसर्च प्रोग्राम का कार्यान्वयन

प्रायोजक: भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)
दल: अजय शाह, स्मृति परशीरा , मयंक मिश्रा, फ़ैज़ा रहमान, सुदीप्तो बनर्जी, देवेंद्र दामले, रिषभ बेली, सारंग मोहरिर , आशिम कपूर, रचना शर्मा, सुदीप्तो बनर्जी, विशाल त्रेहान, सृष्टि शर्मा।
लक्ष्य: रा लो वि नी सं ने दूरसंचार प्रसारण क्षेत्रों के नियमन और आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्रों में नीतिगत विश्लेषक अनुसंधान प्रदान करने के लिए TRAI के साथ तीन साल का समझौता किया है। (जून 2016-मई 2019)

5. एमसीए अनुसंधान कार्यक्रम
प्रायोजक: कारपोरेट मामलों के मंत्रालय
दल: ईला पटनायक, प्रतीक दत्त, सुदीप्तो बनर्जी, कार्तिक सुरेश, मेधा राजू, शुभ रॉय रॉय, राधिका पांडे
लक्ष्य: प्रस्तावित ढांचा तीन वर्षों के लिए एमसीए और रा लो वि नी सं के बीच एक औपचारिक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, रा लो वि नी सं, एमसीए की वैधानिक जिम्मेदारियों के संबंध में एमसीए को आवश्यक कानूनी, नीति और अनुसंधान सहायता प्रदान करेगा। (फरवरी 2019-जनवरी 2021)

6. वर्ष 2016-17 राज्य एफआर बी एम अधिनियम का सिक्किम सरकार द्वारा किये गए अनुपालन की समीक्षा
प्रायोजक: सिक्किम सरकार
दल: प्रताप रंजन जेना
लक्ष्य: रिपोर्ट में 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार के राजकोषीय रुख का आकलन किया गया।

7. सिक्किम के लिए मध्यम अवधी राजकोषीय योजना 2020 -21 से 2022-23
प्रायोजक: सिक्किम सरकार
दल: प्रताप रंजन जेना
लक्ष्य: रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए सिक्किम सरकार के लिए मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना (एम टी एफ पी) को प्रस्तुत किया गया। एम टी एफ पी रिपोर्ट 2020-21 राजकोषीय नीति उद्देश्यों और आगामी बजट वर्ष और दो जावक वर्षों में राजकोषीय लक्ष्यों का अनुमान का आकलन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट मौजूदा मैक्रो-फिस्कल माहौल पर आधारित थी और सिक्किम में एफआरबीएम एक्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। रिपोर्ट में तीन साल के लिए राजकोषीय परिवर्तनों का अनुमान है, जिसमें एफआरबीएम अधिनियम की शर्तों के अनुसार बजट वर्ष भी शामिल है

वित्त मंत्रालय के लिए की गयी शोध गतिविधियां

1. भारत में वस्तु और सेवा (जी एस टी) कर लागू के राजकोषीय आशय

प्रायोजक: 15 वीं वित्त आयोग
दल: सच्चिदानंद मुखर्जी, आर कविता राव
लक्ष्य: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत देश की कर प्रणाली में एक बड़ा सुधार है। इसने कई प्रचलित करों को ग्रहण कर लिया है। चूंकि जीएसटी के प्रदर्शन से सरकार के दोनों स्तरों के राजस्व पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यह अध्ययन जीएसटी राजस्व और विभिन्न सरकारों के लिए शेयरों के आकलन के लिए एक पद्धति स्थापित करता है।

2. "मैक्रो-फिस्कल लिंकेजेज़ पर अध्ययन"
प्रायोजक: 15 वीं वित्त आयोग
दल: एन आर भानुमूर्ति, सुकन्या बोस, साक्षी सतीजा
लक्ष्य: ***15*** वें वित्त आयोग के अनुरोध पर, संस्थान ने जीडीपी विकास, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, सार्वजनिक ऋण, आदि जैसे विभिन्न व्यापक आर्थिक मानकों पर ***14*** वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को उच्चतर हस्तांतरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया है। अध्ययन ने ***15*** वें वित्त आयोग की अवधि के अंत तक एक नया एफआरबीएम रोडमैप और यूएस ***$ 5*** ट्रिलियन को प्राप्त करने की व्यवहार्यता का प्रस्ताव देने पर भी काम किया।.

3. "कैपिटल मार्केट्स के कराधान" पर अध्ययन
प्रायोजक: 15 वीं वित्त आयोग
दल: आर कविता राव, सुरांजलि टंडन, डी पी सेनगुप्ता

4. वित्त आयोगों की रिपोर्टों का अवलोकन
प्रायोजक: 15 वीं वित्त आयोग
दल: पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता

5. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नीति का संशोधित मसौदा
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

6. मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के साथ समीक्षा बैठक के लिए रिपोर्ट 19 वीं जून 2019
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

7. भुगतान एवं निबटारा प्रणाली ड्राफ्ट विधेयक और भारतीय रिजर्व बैंक के असंतोष टिप्पणी पर उत्तर
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

8. स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) ग्लोबल के साथ संप्रभु वार्षिक क्रेडिट समीक्षा बैठक के लिए रिपोर्ट

प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

9. बैंक पुनर्पूंजीकरण का बैंकों की वैधानिक तरलता अनुपात, अग्रिम और उनके द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त स्तर-1 पूंजी पर प्रभाव का अध्ययन
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

10. घरेलू अवसंरचना निवेश रिपोर्ट
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

11. ऋण और वित्तीय बाजार अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर नोट
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

12. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशिओं (आईसीओआर) की पुन: गणना
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

13. बांड बाजार को मजबूत बनाने पर नोट
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

14. शीर्षक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में प्याज की कीमतों की भूमिका पर नोट
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

15. वित्तीय विकास सूचकांक रैंकिंग में सुधार के लिए रोडमैप
प्रायोजक: रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय
दल: रथिन राय

अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के लिए की गयी शोध गतिविधियां

1. "किसानों और निर्यातकों पर कॉफी बोर्ड द्वारा प्रदत्त विभिन्न सब्सिडियों का किसानों और निर्यातकों पर प्रभाव का आकलन"
प्रायोजक: कॉफी बोर्ड
दल: एन.आर. भानुमूर्ति , भाबेश हज़ारिका, प्रिया केशरी

लक्ष्य: कॉफी बोर्ड और भारत सरकार कॉफी प्लांटर्स के साथ-साथ निर्यातकों को भी लंबे समय से कई तरह की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य कॉफी की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ खेती की लागत पर इन सब्सिडियों के प्रभाव को समझना था |

2. त्रिपुरा सरकार के लिए अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ जीएसडीपी अनुपात का एक तुलनात्मक कर अध्ययन (नवंबर 2019)
   प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
   दल: सच्चिदानंद मुखर्जी, सताद्रू, सिकदर, शिवानी, विभा कुमारी
   लक्ष्य: अध्ययन कुल मिलाकर त्रिपुरा के प्रधान कर संग्रह कर राजस्व का अन्य प्रमुख पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना पर केंद्रित है। इस अध्ययन का विश्लेषण रा लो वि नी सं के वित्त खाता डेटाबेस पर आधारित है और अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य त्रिपुरा के अन्य राज्यों की तुलना में कर संग्रह की तस्वीर पेश करना है, इसलिए अध्ययन उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है जहां त्रिपुरा को अतिरिक्त कर राजस्व जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।.

3. भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 71 वें दौर के सर्वेक्षण से स्वास्थ्य पर घरेलू खर्च का विश्लेषण
   प्रायोजक: विश्व स्वास्थ्य संगठन
   दल: मीता चौधरी, जय देव दुबे, बिदिशा मंडल
   लक्ष्य: यह विश्लेषण भारत में स्वास्थ्य पर फुटकर खर्च की प्रकृति, सीमा और प्रभाव की आधारभूत समझ प्रदान करता है, और भविष्य में भारत के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ट्रैक करने के लिए एक मापदंड प्रदान करता है

4. अनुसंधान परियोजना (मैक्रोइकॉनॉमिक्स): वित्तीय संरचना, संस्थागत गुणवत्ता और मौद्रिक नीति संचरण: एक मेटा-विश्लेषण
   प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
   दल: श्रुति त्रिपाठी, सबर्णी चौधरी, सहाना रॉय चौधरी
   लक्ष्य: लंबे समय से मौद्रिक नीति प्रसारण का साहित्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक गतिविधियों और मुद्रास्फीति के लिए मौद्रिक नीति के कमजोर संचारण को स्वीकार करता है। नाजुक वित्तीय प्रणाली, वित्तीय एकीकरण का निम्न स्तर और कमजोर संस्थान को अक्सर इन अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति संचरण की कमी के कारणों के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह पत्र इस बात की जांच करता है कि मेटा-विश्लेषण ढांचे का उपयोग करके विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के एक व्यापक सेट में मौद्रिक नीति प्रसारण की सीमा में इन कारकों में किस हद तक भिन्नता की व्याख्या की जा सकती है। हम यह पाते हैं कि विभिन्न वित्तीय संकेतकों द्वारा संकेतित वित्तीय विकास की डिग्री मौद्रिक नीति संचरण के परिमाण और समय अंतराल में क्रॉस-कंट्री विविधताओं की व्याख्या करती है। हम उत्पादन वृद्धि के लिए संचरण परिमाण को वित्तीय त्वरक की भूमिका में भी पाते हैं |

5. भारत में उभरती प्रौद्योगिकियों के नियमन पर एक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए एँफ़ एन एँफ़ के साथ समझौता ज्ञापन
   प्रायोजक: फ्रेडरिक नौमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम
   दल: रेणुका साने, रिषभ बेली, स्मृति पारशीरा , फ़ैज़ा रहमान
   लक्ष्य: एफएनएफ ने वर्ष 2019-20 के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के विनियमन पर एक सम्मेलन आयोजित करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

6. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस - डिजिटल आइडेंटिटी रिसर्च इनिशिएटिव (डीआईआरआई)
   प्रायोजक: इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस
   दल: रेणुका साने, स्मृति पारशेरा
   लक्ष्य: आईएसबी में डीआईआरआई आधार पर ध्यान देने के साथ डिजिटल पहचान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान आयोजित करता है और इस उद्देश्य के लिए अनुसंधान अध्येताओं का एक नेटवर्क भी बना रहा है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य "आधार" अधिनियम की धारा 5 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है जो कि कमजोर समूहों के नामांकन के लिए विशेष उपायों से संबंधित है | साथ ही प्रक्रिया में कमियां और उन्हें संबोधित करने के संभावित तरीकों को भी चिन्हित करना है | अध्ययन उन सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सिफारिशें करेगा जिससे इन् समूहों की 'आधार' से संबंधित प्रक्रियाओं और इसके समान डिजिटल पहचान प्रणाली में इनकी भागीदारी को मजबूत करने में मदद कर सकें |

7. स्वास्थ्य और उसके वित्तपोषण पर शोध एवं नीतियों में सुधार पर एक अध्ययन
   प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
   दल: अजय शाह, ईला पटनायक, शुभो रॉय, शेफाली मल्होत्रा, हरलीन कौर, रचना शर्मा, संहिता सपटणेकर , महिमा गुप्ता, मनप्रीत सिंह, समीर पेठे, सुप्रिया कृष्णन, मधुर मेहता।, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मौमिता दास।
   लक्ष्य: भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याएं जटिल हैं। एक तरफ, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे हैं, और दूसरी ओर, वे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की स्थिति और इस व्यय के लिए लेखांकन के कार्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन से संबंधित हैं। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सूचना की कमी , अपर्याप्त या अपूर्ण डेटा से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति और इसके खर्च में एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव से भी है।

   बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत में स्वास्थ्य की स्थिति और इसके वित्तपोषण की बेहतर समझ हासिल करने के लिए आवश्यक उपकरणों को विकसित करने के लिए रा लो वि नी सं को वित्तपोषित कर रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पर एक व्यापक डेटासेट बनाकर उक्त सूचना अंतरालों को पाटने के लिए इस परियोजना को डिजाइन किया गया है। समग्र उद्देश्य विश्वसनीय और व्यापक डेटा प्रदान करना है ताकि स्वास्थ्य निर्णय पर अनुसंधान और विश्लेषण के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को डिजाइन करने और निगरानी करने में सहायता के साथ नीतिगत निर्णय बेहतर रूप से सूचित किए जा सकें (दिसम्बर 2015- दिसंबर 2019) |

8. एक प्रभावी राष्ट्रीय काउंसिल फॉर वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण (" NCVET ") की स्थापना के लिए संगठन डिजाइन और आंतरिक प्रक्रियाएं
   प्रायोजक: ओमिड्यार नेटवर्क सेवा
   दल: अजय शाह, ईला पटनायक, प्रतीक दत्ता, सारंग मोहरिर, सुदीप्तो बनर्जी, कार्तिक सुरेश, मेधा राजू
   लक्ष्य: एन सी वी इ टी (दो नियामक निकायों, एन सी वी टी और एन एस डी ए के विलय से स्थापित) द्वारा पूरे भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार को सम्पोषित करने के लिए अध्ययन। यह अध्ययन एन सी वी इ टी के लिए एक डिजाइन का उत्पादन करेगा; प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा और, एन सी वी इ टी द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्यों और प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करेगा। इस अध्ययन से उन महत्वपूर्ण नियामक साधनों, अनुबंधों और दिशानिर्देशों की भी पहचान होगी, जिन्हें जारी करने और लागू करने की आवश्यकता होगी।
   रा लो वि नी सं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर एक कार्यान्वयन योजना के विकास में सहायता करेगा, और इस संबंध में परामर्श और बैठकें आयोजित करेगा (फरवरी 2019-अगस्त 2019) |

9. भारतीय राज्यों के लिए कर प्रयास और कर संग्रहण दक्षता मापने सम्बन्धी शोध (जून 2017- जून 2019)
   प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
   दल: हरि नायडू
   लक्ष्य: भारतीय राज्यों के लिए कर प्रयास और कर संग्रहण दक्षता मापने सम्बन्धी शोध |

चल रही परियोजनाएं

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए चल रही शोध गतिविधियां

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय पहलू: :प्रभाव और भविष्य के लिए सीख
   प्रायोजक: नीति आयोग(ट्रांस्फोर्मिंग भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान)
   दल: मीता चौधरी, रंजन कुमार मोहंती
   लक्ष्य: यह अध्ययन बताता है कि केंद्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों में स्वास्थ्य व्यय को किस हद तक प्रबलित किया गया है।

2. गृह मंत्रालय- रा लो वि नी सं रिसर्च प्रोग्राम
   प्रायोजक: गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार
   दल: रथिन राय, मीता चौधरी, अमय सप्रे, रत्नेश
   लक्ष्य: केंद्रशासित प्रदेशों के राजस्व और व्यय का आकलन करने के लिए, बजट आवंटन के लिए मानदंडों पुनरीक्षित करना और स्थानीय निकायों को निधि के विचलन और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके द्वारा किए गए व्यय की जांच करना ।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रोजगार सृजन के आकलन पर अध्ययन
   प्रायोजक: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
   दल: एन आर भानुमूर्ति , दिनेश कुमार नायक, अशोक भाकर, भाबेश हज़ारिका, कनिका गुप्ता, तन्वी ब्रह्मे
   लक्ष्य: अध्ययन के पहले भाग का प्राथमिक उद्देश्य शहरी भारत में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घरों के निर्माण का रोजगार सृजन पर प्रभाव का अनुमान लगाना है। अध्ययन में यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे किफायती आवास क्षेत्र में किए गए निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो रहे हैं। अध्ययन का दूसरा हिस्सा यह बताने की कोशिश करता है कि किफायती आवास क्षेत्र में किए गए निवेश से समाज के लक्षित वर्गों को क्या लाभ होता है और कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुझाव क्या होंगे?.

4. सशर्त नकद अंतरण का गर्भवती महिलाओं मजदूरों के बीच बेहतर स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर प्रभाव : मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना मध्य प्रदेश से साक्ष्य
   प्रायोजक: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सरकार मध्य प्रदेश
   दल: भाबेश हज़ारिका, रंजन मोहंती, दिनेश नायक, एनआर भानुमूर्ति , कनिका गुप्ता, कनिका कुमार, अंशु शुक्ला
   लक्ष्य: यह मूल्यांकन करना कि मध्य प्रदेश में अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के बीच एम् एम् एस एस पी एस वाई ने मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवा में सुधार कैसे किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य योजना जागरूकता, निधि प्रवाह (डिजाइन और उसमे हो रही देरी), व्यय प्रोफ़ाइल, और योजना के कार्यान्वयन और स्वीकृति के बारे में सीमावर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की धारणा और लक्षित आबादी के बीच स्वीकार्यता जैसे मुद्दों का विश्लेषण करना है।

5. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक: अनुसंधान कार्यक्रम
   प्रायोजक: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
   दल: ईला पटनायक, मेधा राजू, हरलीन कौर, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, रचना शर्मा, राधिका पांडे
   लक्ष्य: कैग और रा लो वि नी सं के बीच दो वर्षों के लिए एक औपचारिक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित ढांचे को डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, रा लो वि नी सं निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा::
   - संस्थान की विशेषज्ञता के क्षेत्र के भीतर अनुसंधान विषयों से संबंधित मुद्दों पर सीएजी को अनुसंधान और परामर्श समर्थन;
   - अनुसंधान विषयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नीति निर्माण में सीएजी को अनुसंधान और विश्लेषणात्मक समर्थन;
   - शासन, लोक प्रशासन और प्रदर्शन, और व्यय के मूल्य से संबंधित प्रश्नों पर सिफारिश प्रदान करना;

- लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं (कराधान, सरकारी ऋण और व्यय सहित), और वित्तीय विनियमन पर तकनीकी सहायता प्रदान करना; तथा
- कैग द्वारा ऑडिट किए गए विभिन्न क्षेत्रों पर तकनीकी सहायता और अनुसंधान प्रदान करना, जिसमें ऑडिटिंग के दृष्टिकोण, बेंचमार्क की पहचान शामिल होगी। (जून 2019 -जून 2021)

6. वर्ष 2017-18 राज्य एफआर बी एम अधिनियम का सिक्किम सरकार द्वारा किये गए अनुपालन की समीक्षा
   प्रायोजक: सिक्किम सरकार
   दल: प्रताप रंजन जेना
   लक्ष्य: यह रिपोर्ट 14 वें एफसी की सिफारिशों के अनुसार अधिनियम में संशोधन के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य सरकार के वित्तीय रुख का आकलन करेगी।

7. संस्थान में संकाय के लिए लोक वित्त जानकारी डाटाबैंक अद्यतन करना
   प्रायोजक: रा लो वि नी सं
   दल: एच अमरनाथ, दीवान चंद, रोहित दत्ता
   लक्ष्य: शैक्षणिक प्रयोजन के लिए संकाय को सरकारी वित्त (केंद्र और राज्य दोनों) पर जानकारी प्रदान करना

8. ऑनलाइन डाटाबेस निर्माण
   प्रायोजक: रा लो वि नी सं
   दल: एच अमरनाथ, रोहित दत्ता
   लक्ष्य: लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ डेस्क पर लोक वित्त सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना | विश्लेषणात्मक, पृथक करणीय डेटाबेस जो क्वेरी आधारित है और अनुमेय इंटरनेट प्रोटोकॉल पते से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है

9. त्रिपुरा सरकार की ऋण स्थिरता पर एक अध्ययन
   प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
   दल: मनीष गुप्ता, स्मृति मेहरा

10. त्रिपुरा राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति पर एक अध्ययन
    प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
    दल: मनीष गुप्ता, समप्रीत कौर

11. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) ने हाल ही में एक परियोजना शुरू की है, जो भारत में 'विशेष क्षेत्रों में गंभीर मुद्दों' का अध्ययन करने के लिए है।
    प्रायोजक: सामाजिक विज्ञान अनुसंधान भारतीय परिषद (आईसीएसएसआर)

दल: ईला पटनायक, आशिम कपूर, रचना शर्मा, समीर पेठे, शेफाली मल्होत्रा, चिराग आनंद

12. वर्ष 2018-19 राज्य एफआर बी एम अधिनियम का सिक्किम सरकार द्वारा किये गए अनुपालन की समीक्षा

प्रायोजक: सिक्किम सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना

लक्ष्य: यह रिपोर्ट 14 वें एफसी की सिफारिशों के अनुसार अधिनियम में संशोधन के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य सरकार के वित्तीय रुख का आकलन करेगी।

वित्त मंत्रालय के लिए चल रही शोध गतिविधियां

1. राजस्व विभाग के लिए पारदर्शिता ऑडिट

प्रायोजक: वित्त मंत्रालय भारत सरकार

दल: सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला, विभा कुमारी

लक्ष्य: आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को इसकी उप-धारा (1) (बी) में सूचीबद्ध सूचना की जानकारी को स्वतः प्रकट करने की आवश्यकता है। विभागों को उन सूचनाओं का विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है जो आवेदकों द्वारा सबसे अधिक मांगी जाती हैं और इसे अपनी वेबसाइट पर स्वतः प्रदान करनी है । इस प्रावधान के अनुसरण में, डी ओ पी टी ने आगे निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंत्रालय / लोक प्राधिकरण को प्रत्येक मंत्रालय / विभाग / लोक प्राधिकरण के तहत संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से हर साल तीसरे पक्ष द्वारा अपने सक्रिय स्वतः प्रकटीकरण पैकेज का ऑडिट कराना चाहिए और मुख्य सूचना आयोग को निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए । रा लो वि नी सं को केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों के तीसरे पक्ष के ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गयी है ।

2. डी आई पी ए ऍम में विनिवेश की प्रक्रिया पर रिसर्च इनपुट

प्रायोजक: डी आई पी ए ऍम

दल: रेणुका साने, सुदीप्तो बनर्जी, कार्तिक सुरेश, सृष्टि शर्मा, सारंग मोहरिर

लक्ष्य: निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनुसंधान और बौद्धिक कारक प्रदान करना :

- डी आई पी ए एम् की पंचवर्षीय दृष्टि योजना
- विनिवेश के लिए वर्तमान दृष्टिकोण की समीक्षा
- विनिवेश प्रक्रिया के नए क्षेत्र
- पहले से ही पूर्ण विनिवेश लेनदेन का विश्लेषण
- नियमित और अनुमानित आधार पर शेयरों को बेचने के तरीके

अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के लिए चल रही शोध गतिविधियां

1. त्रिपुरा के राज्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए संभव उपायों पर अध्ययन
   प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
   दल: सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला, विभा कुमारी
   लक्ष्य: यह अध्ययन त्रिपुरा सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की संभावनाओं की खोज करता है। अध्ययन का मुख्य फोकस राज्य के अपने कर राजस्व पर होगा। चूंकि जीएसटी त्रिपुरा के ओटीआर के पर्याप्त कर आधार का हिस्सा है, इसलिए जीएसटी संग्रह में त्रिपुरा के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण राज्य को जीएसटी के बाद मुआवजे के शासन के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। अध्ययन में अन्य करों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे - क) गैर - जीएसटी वस्तुओं, अर्थात्, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और मादक पेय (बिक्री कर संग्रह, यदि कोई हो) से मानव उपभोग के लिए कर संग्रह। ख) मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों से राज्य उत्पाद शुल्क (विभिन्न शुल्क और कर्तव्यों के संदर्भ में), और परिवहन कर, मोटर वाहन (एमवी) कर और यात्रियों और वस्तु कर (पीजीटी)

2. भारत में स्वास्थ्य व्यय का लोक वित्तपोषण: आगे की राह
   प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
   दल: मिता चौधरी, रंजन कुमार मोहंती, श्रुति त्रिपाठी, प्रीतम दत्ता जम्मू, जय देव दुबे, बिदिशा मंडल, सुनेत्रा घटक, राशि मित्तल, रजनी पांडे
   लक्ष्य: यह भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्तपोषण के साथ अनुभवों को समझने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक तीन-वर्षीय परियोजना है

3. भारत में त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद विकास की नाउ कास्टिंग (एनसीएईआर के साथ सहयोग)
   प्रायोजक: (एनसीएईआर के साथ सहयोग)
   दल: रुद्राणी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मंडल (एनसीएईआर), बोर्नेलि भंडारी (एनसीएईआर)
   लक्ष्य: उच्च आवृत्ति मैक्रो डेटा का उपयोग करके तिमाही जीडीपी वृद्धि का वास्तविक समय पूर्वानुमान.

4. सी पी आई मुद्रास्फीति का लघु अवधि पूर्वानुमान
   प्रायोजक: रा लो वि नी सं
   दल: रुद्राणी भट्टाचार्य, मृगांक्षी कपूर (बिट्स पिलानी)

5. क्या ई-एन ए एम् भारत में फलों और सब्जियों के बाजार को एकीकृत करने में सफल है : - एक वेक्टर त्रुटि संशोधन मॉडल से साक्ष्य
   प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
   दल: रुद्राणी भट्टाचार्य, सब्रानी चौधरी

6. क्या भारतीय मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को अवलम्बित करती है ?

प्रायोजक: प्रोफेसर पी आर ब्रह्मानंद अनुसंधान अनुदान, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु, 2018-19
दल: रुद्राणी। भट्टाचार्य

7. भारत में उभरती प्रौद्योगिकियों के नियमन पर एक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए ऍफ़ एन ऍफ़ के साथ समझौता ज्ञापन
प्रायोजक: फ्रेडरिक नौमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम
दल: रेणुका साने, ऋषभ बेली, स्मृती पार्शीरा ओंमकार, फैजा रहमान
लक्ष्य: ऍफ़ एन ऍफ़ ने वर्ष 2020 के लिए और उभरती प्रौद्योगिकियों भारत के विनियमन पर एक सम्मेलन आयोजित करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

8. ओमिड्यार - आईडीएफसी फाउंडेशन - : निम्नांकित के लिए डेटा गवर्नेंस नेटवर्क: 1) गोपनीयता नीतियों की समझ को क्या संचालित करता है ;2) डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के लिए एजेंसी डिजाइन ;3) वर्तमान निगरानी संबंधित कानून ;4) विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के उपयोग के आसपास गोपनीयता के मुद्दों का अध्ययन करना (ड्रोन, सीसीटीवी, चेहरे की पहचान, सेल टॉवर ट्रैकिंग, एन्क्रिप्शन उपकरण, आदि)
प्रायोजक: आईडीएफसी फाउंडेशन और ओमिड्यार नेटवर्क
दल: रेणुका साने, स्मृती पार्शीरा, रिषभ बेली, फ़ैज़ा रहमान
लक्ष्य: निम्नांकित के लिए डेटा गवर्नेंस नेटवर्क :
   - गोपनीयता नीतियों को समझने के क्या पैमाने हैं: अर्थात्, क्या कारक जैसे आयु, शिक्षा, बुद्धिलब्धि, अंग्रेजी में सहजता, शहरीकरण और इंटरनेट-आधारित सेवाओं से परिचित, व्यक्ति को वर्तमान मौजूदा प्रस्ताव के मूल्यांकन करने में भूमिका निभाते हैं । यह भारत में गोपनीयता अधिकारों की विभिन्न अवधारणाओं और तौर-तरीकों (अभिव्यक्ति की) का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखता है |
   - डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के लिए एजेंसी डिजाइन, भारत में एक नए डेटा सुरक्षा ढांचे के निर्माण की दिशा में चल रहे काम से डीपीए की स्थापना और डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार करने की उम्मीद है। डीपीए को महत्वपूर्ण नियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के साथ सौंपा जाने की उम्मीद है। इस अध्ययन में, हम डीपीए के निर्माण के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखते हैं|
   - भारत में वर्तमान निगरानी संबंधित कानून, नीतियों और तंत्रों की जांच करें, वर्तमान प्रणालियों में कमी की पहचान करें और नीतिगत पहल का सुझाव दें|
   - विशिष्ट प्रौद्योगिकियों जैसे (ड्रोन, सीसीटीवी, चेहरे की पहचान, सेल टॉवर ट्रैकिंग, एन्क्रिप्शन उपकरण, आदि के उपयोग के आसपास गोपनीयता पर असर का अध्ययन करना|

9. भारत के लिए उपभोक्ता वित्त में शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) ढांचे की ओर
प्रायोजक: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

दल: रेणुका साने, विमल बालासुब्रमण्यम, मिथिला एक सारा, कुषाण बिस्वास, सुरेश कुमार, उत्कर्ष
लक्ष्य: इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- जीआरएम पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ क्या हैं और एक अच्छे जीआरएम के सिद्धांतों पर कैसे पहुंचते हैं। जीआरएम को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में प्रौद्योगिकी कैसे विकसित की गई है - विशेष रूप से उन बड़े देशों में जहाँ अधिकांश आबादी गरीब है
- उपभोक्ता के मौजूदा उत्पादों और जीआरएम के साथ अनुभवों का मूल्यांकन यह समझने के लिए करें कि किसी समस्या का सामना करने पर घर वाले क्या करते हैं?
- घरों का वित्तीय बाजारों में भागीदारी के निर्णय लेने के लिए जीआरएम के प्रभाव का मूल्यांकन। और पिछले अनुभव का विश्लेषण करने के लिए और वे भौतिक संपत्तियों में अतिरिक्त प्रवाह से कैसे संबंधित हैं।
- यह मूल्यांकन कैसे घरों की विशेषताओं में अंतर और उनकी प्रतिक्रियाओं में विभिन्नता लाता है | क्या उच्च आय वाले घरों में कम आय वाले लोगों की तुलना में कम सवालों के जवाब खोजने पड़ते हैं और बेहतर करते हैं | क्या गरीबों को एक विषमानुपात कल्याणकारी हानि का सामना करना पड़ता है तथा जोखिम ग्राह्यता से उनकी प्रतिक्रिया कैसे भिन्न होती है? समय की वरीयता की दर से उनकी जोखिम ग्राह्यता कैसे भिन्न होती है?

10. सरकारी स्कूलों से छात्रों के बहिर्गमन की विवेचना
प्रायोजक: अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अनुसंधान अनुदान, 2018
दल: सुकन्या बोस, प्रियंता घोष, मनोहर बोडा, अरविंद सरदाना
लक्ष्य: यह अध्ययन सरकारी स्कूल से बाहर निकलने की घटना को विशेषकर पिरामिड में सबसे नीचे के समूहों पर ध्यान देते हुए उन कारणों को बताने का प्रयास करता है। सार्वजनिक प्रावधान और विनियमन के साथ साथ यह अध्ययन बाजार के प्रावधान की प्रकृति को भी विश्लेषित करेगा |

11. लिंग संवेदनशील बजट का स्कूल शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन
प्रायोजक: नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन
दल: सुकन्या बोस
लक्ष्य: स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए अपने आवेदन में लिंग बजट पर नीतियों और प्रथाओं को समझने के लिए.

12. "भूमि बाजार को बेहतर बनाने हेतु"
प्रायोजक: ओमिड्यार नेटवर्क
दल: ईला पटनायक, देवेंद्र दामले, विशाल त्रेहन, तुषार आनंद, विराज जोशी
लक्ष्य: भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है और संभवतः भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम सुधार वाले कारकों में से एक है। पिछले दो दशकों में वृद्धि और फलस्वरूप शहरीकरण की बढ़ी हुई गति के कारण भूमि बाजारों में मांग में परिवर्तन हुआ है। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित है

- भूमि प्रशासन प्रणालियों का ज्ञान अर्जन एवं प्रशासनिक डिजाइन और क्षमता में सुधार करने के लिए ।
- अक्षमताओं को कम करने, लेनदेन की लागत कम करने और भूमि बाजारों में बेहतर संपत्ति अधिकार बनाने के लिए भूमि पर अधिकारों और प्रतिबंधों की भूमिका को समझना
- भूमि बाजारों में बाजार की असफलताओं और भूमि को नियंत्रित करने वाले नियमों की भूमिका और डिजाइन को समझना (अप्रैल 2019-मार्च 2021)

13. न्याय चुनौती के लिए डेटा

प्रायोजक: वयम फोरम फॉर सिटीजनशिप

दल: ईला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद, विराज जोशी, विशाल त्रेहन, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

लक्ष्य: इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के अनुबंध प्रवर्तन मशीनरी को समझने के लिए डेटासेट बनाना है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

- अनुबंध प्रवर्तन मुकदमेबाजी पर केस-लेवल की टाइम सीरीज़ डेटासेट, राज्यों के चुनिंदा जिलों और उच्च न्यायालयों में अनुबंध से संबंधित विवादों पर नज़र रखना। इस डेटा को समय-समय पर परिणाम के रूप में जारी किया जाएगा;
- कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इंडेक्स, जो उपरोक्त आंकड़ों से उत्पन्न होगा। सूचकांक को इस आधार पर विभिन्न अदालतों और राज्यों के प्रदर्शन की निगरानी और तुलना करने के लिए आवधिक अंतराल पर गणना की जाएगी। फिर उत्पन्न परिणामों का उपयोग नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए किया जा सकता है।
- प्रयोग करने योग्य डेटा की उपलब्धता होने पर एक पाठ प्रसंस्करण मॉड्यूल को विकसित करने का उद्देश्य है जो कि नियमित अभिव्यक्ति मिलान या एक वर्गीकरण एल्गोरिथ्म के माध्यम से निर्णय / आदेश के असंरचित पाठ से अनुबंध प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक जानकारी निकलेगा। (दिसंबर 2019-मई 2020)

14. भारत में कर विवादों का विश्लेषण

प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

दल: सुरांजलि टंडन, आदित्य रेड्डी, अक्षय गर्ग

लक्ष्य: भारत में कर विवाद कानून के कार्यान्वन में लगातार लम्बे समय लेने के लिए ध्यान आकर्षित करता है । विवादों का आर्थिक परिणाम प्रशासन के साथ-साथ करदाता पर होता हैं। यह परियोजना करदाताओं और कर विभाग के बीच संवाद को पाटने का एक तरीका है। इस अध्ययन में प्रस्तावित किया है कि कर विवादों के कारण और इसकी प्रशासनिक चुनौतियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक केस स्टडी या साक्षात्कार का तरीका अपनाया जाए। इस परियोजना का परिणाम महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करना है जो कर विवादों की मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा |

15. भारत में वित्तीय बाजारों का कराधान
    प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
    दल: आर कविता राव, सुरंजलि टंडन, डीपी सेनगुप्ता, आदित्य रेड्डी, अक्षय गर्ग
    लक्ष्य: इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न उपकरणों के कर उपचार की जांच करना और वर्तमान डिजाइन के लिए आर्थिक औचित्य की जांच करना और करदाता और राजस्व विभाग के साथ मिलकर मौजूदा कानून को सरल बनाने के तरीके सुझाना है।

16. कर नीति और आकलन का मूल्यांकन
    प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
    दल: आर कविता राव
    लक्ष्य: यह सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन भारत में करों की संरचना के बारे में लोगों की धारणाओं और अधिक करों का भुगतान करने की उनकी इच्छा का दस्तावेजीकरण करने का प्रस्ताव करता है।

17. इथियोपिया में वित्तीय संघवाद (जून 2019 - जून 2021 दो वर्ष लगभग)
    प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
    दल: रथिन राय, लेखा चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता
    लक्ष्य: (क) इथियोपिया में अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए (ख) राजकोषीय विकेंद्रीकरण राजस्व साझाकरण" और "राजकोषीय हस्तांतरण" को लागू करने और वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए मेल्स लीडरशिप अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम। हाउस ऑफ़ फेडरेशन (उच्च सदन / सीनेट) और फ़ोरम ऑफ़ फ़ेडरेशन (ओटावा) के साथ |

18. अंतर सरकारी राजकोषीय संबंध प्रमाणन कार्यक्रम (सहयोगी संस्थाएं रा लो वि नी सं, भारत, फोरम ऑफ़ फेडरेशन, कनाडा और मेलेस ज़ेनावी नेतृत्व अकादमी, इथियोपिया)
    प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
    दल: रथिन रॉय, लेखा चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता

19. लैंगिक समानता और लिंग बजट का शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए राजकोषीय खर्च पर प्रभाव एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक अध्ययन - (सितंबर 2017 - अगस्त 2020)
    प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
    दल: लेखा चक्रवर्ती
    लक्ष्य: वित्तीय नीति प्रथाओं के प्रभाव का प्रयोगसिद्ध रूप से विश्लेषण करने के लिए - विशेष रूप से लैंगिक बजट की प्रक्रियाओं और विश्लेषणात्मक ढाँचों के संदर्भ में - एशिया प्रशांत देशों में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था ढांचे के भीतर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में समान रूप से समान रूप से वितरित किए गए लिंग के चर।

20. बच्चों के लिए लोक वित्त: राज्य स्तरीय विश्लेषण - गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक - (मई 2019 - जनवरी 2022)
    प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
    दल: लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, जेनेट फरीदा याकूब, अनिंदिता घोष

21. अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय नीति। अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी (फरवरी 2019 - अगस्त 2021) के साथ अनुसंधान सहयोग
    प्रायोजक: बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
    दल: लेखा चक्रवर्ती, मारिया फ्लोरो (सलाहकार: अमेरिकी विश्वविद्यालय)

22. राज्य जैव विविधता रणनीति का विकास और कार्य योजनाओं (एस बी सैपस) को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए संसाधन संग्रहण रणनीति,
    प्रायोजक: यूएनडीपी
    दल: रीता पांडे, गरिमा जसूजा , अनुजा मल्होत्रा, प्रिया यादव

23. भारत सरकार-यूएनडीपी की "सुरक्षित हिमालय परियोजना" के तहत राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना और विकास संसाधन संग्रहण रणनीतियाँ (एस बी सैपस) सिक्किम में लागू करने के लिए
    प्रायोजक: यूएनडीपी
    दल: रीता पांडे, गरिमा जसूजा , अनुजा मल्होत्रा, प्रिया यादव

नयी परियोजनाओं की पहल

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए प्रारंभ शोध गतिविधियां

1. भारत में चिकित्सा नैतिकता का विनियमन और प्रशासन - **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** (डी एस टी) डी एस टी - **ईला पटनायक; रेणुका साने**
2. उत्तराखंड सरकार के वित्तीय प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए (एन आई पी एफ पी) और पंडित दीन दयाल उपाध्याय केंद्र के बीच सहयोग **उत्तराखंड सरकार - रथिन रॉय**
3. प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में इक्विटी की लागत पर अध्ययन (ए ए आई हवाई अड्डों और अन्य प्रमुख निजी हवाई अड्डों) - **प्रायोजित ए ई आर ए - अजय शाह**
4. जीएसटी के राजस्व प्रभाव का विश्लेषण दिल्ली सरकार एन सी टी के लिए - **दिल्ली सरकार - सच्चिदानंद मुखर्जी**
5. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के कारण छावनी बोर्डों (सीबी) को राजस्व के नुकसान पर अध्ययन। - **रक्षा मंत्रालय भारत सरकार - सच्चिदानंद मुखर्जी**

6. महाराष्ट्र के राजस्व मैं वृद्धि - जी एस टी राजस्व - **महाराष्ट्र सरकार** - **सच्चिदानंद मुखर्जी**

वित्त मंत्रालय के लिए प्रारंभ गतिविधियां

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की रियल टाइम व्यापक आर्थिक निगरानी के लिए एक मॉडल (मासिक आधार पर अर्थव्यवस्था की निगरानी) **वित्त मंत्रालय, सरकार।** भारत, नई दिल्ली - **प्रमोद सिन्हा**

अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के लिए प्रारंभ शोध गतिविधियां

1. वित्तीय बाजारों में कराधान संरचना पर अध्ययन - **एन आई पी एफ पी** - **आर कविता राव; सुरांजलि टंडन**
2. पर्यावरणीय राजकोषीय अंतरण **संघ केफोरम, ओटावा।** - **लेखा चक्रवर्ती; अमनदीप कौर**

कार्यशालाएं, बैठकें तथा सम्मेलन

स ० न ०	शीर्षक	आयोजित किया गया	दिनांक और स्थान
1	रा लो वि नी सं -सीजीएपी द्वारा `डेटा सुरक्षा 'पर राउंडटेबल	संयुक्त रूप से CGAP के साथ आयोजन किया रेणुका साने, स्मृति पार्शीरा और फ़ैज़ा रहमान	1 अप्रैल, 2019 रा लो वि नी सं
2	निगरानी सुधार पर रा लो वि नी सं द्वारा गोलमेज	रेणुका साने और स्मृति पार्शीरा, रा लो वि नी सं द्वारा सह आयोजित किया	2 अप्रैल 2019 रा लो वि नी सं
3	"आरटीई के लिए संसाधन की आवश्यकता: आगे का रास्ता" पर अर्द्ध दिवस सेमिनार	सुकन्या बोस	12 अप्रैल 2019 रा लो वि नी सं ऑडिटोरियम
4	'एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2019: विकास से परे महत्वाकांक्षाएं' पर अर्द्ध दिवस पॉलिसी डायलॉग	एन आर भानुमूर्ति	18 अप्रैल, 2019 यूएनईएससीएपी के सहयोग से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हॉल रा लो वि नी सं के आर एंड बिल्डिंग में
5	5-I संघ बजट 2019-20: सुधार और विकास परिप्रेक्ष्य पर सम्मलेन	संयुक्त रूप से पांच संस्थानों द्वारा आयोजित: सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ और रा लो वि नी सं	22 जुलाई, 2019, द इंपीरियल, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में।
6	राज्यों के वित्त में मुद्दे - राज्य बजट 2018-19 का विश्लेषण पर एक आधे-दिवसीय संगोष्ठी	मनीष गुप्ता,	20 अगस्त, 2019 नई दिल्ली के होटल ओबेरॉय में।
7	संघवाद के कुछ प्रमुख मुद्दों पर नवीनतम सोच को साझा करने के लिए एक मंच बनाने के लिए 'संघवाद' पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी	रत्नेश	27-29 अगस्त, 2019 को होटल मैरिडियन, कोच्चि में

स ० न ०	शीर्षक	आयोजित किया गया	दिनांक और स्थान
8	डाटा गवर्नेंस नेटवर्क रिसर्च पर कार्यशालाएं	रा लो वि नी सं, रेणुका साने	4 सितंबर, 2019 रा लो वि नी सं
9	'डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में खोज नीति संबंधी मुद्दों पर एक ऑफसाइट सम्मेलन का आयोजन	रेणुका साने, ऋषभ बेली, फैजा रहमान और स्मृति परशेरा, रा लो वि नी सं	10 और 11 अक्टूबर 2019 को शिमला में
10	न्याय के साथ वित्त पोषण में परिवर्तन पर अर्ध दिवस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	संयुक्त रूप से ग्रांथम रिसर्च इंस्टीट्यूट, एलएसई के साथ, सुरंजलि टंडन	8 नवंबर, 2019 को ऑडिटोरियम, रा लो वि नी सं
11	अपने संबंधित देशों में थिंक टैंक स्थापना के चरणों और चुनौतियों के संबंध में अफगानिस्तान और भूटान की सरकारों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र नवंबर 2019 में आयोजित किया गया । यह बैठक UNESCAP के अनुरोध पर आयोजित की गई थी।	रत्नेश	19 नवंबर, 2019, रा लो वि नी सं
12	रा लो वि नी सं में गणतंत्र को मजबूत बनाना विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालयसाथ संयुक्त रूप रेणुका साने, अजय शाह	10 जनवरी 2020, रा लो वि नी सं
13	5-I केंद्रीय बजट 2020–21: सुधार और विकास परिप्रेक्ष्य	पांच संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित: सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ और रा लो वि नी सं	8 फरवरी, 2020, मल्टीपर्पज हॉल, आईआईसी, नई दिल्ली में।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

एसएन	शीर्षक	तिथि	स्थान	प्रोग्राम समन्वयक
1	इंडियन इकोनॉमिक सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों (OT) के लिए ' लोक वित्त पर एक-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई ई एस)	08-12 जुलाई, 2019	रा लो वि नी सं	रुद्राणी भट्टाचार्य
2	BMGF वित्त पोषित परियोजना के तहत और बांग्लादेश के वित्त सचिव के अनुरोध पर बांग्लादेश सरकार से 11 अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के लिए एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया | यह दौरा भारत में लागू किया जा रहे ब्लॉकचैन प्रोजेक्ट्स से सम्बंधित था और इसे नीति आयोग के परामर्शानुसार आयोजित किया गया	जुलाई10-17, 2019	दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई	रत्नेश
3	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अधिकारियों (आई ए और ए एस अधिकारी) के लिए एक सप्ताह का उन्नत प्रबंधन विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	02-06 दिसंबर, 2018	रा लो वि नी सं	मनीष गुप्ता
4	शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए लोक वित्त में 13 वां दो सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स	दिसंबर 09-20, 2019	रा लो वि नी सं	सुरांजलि टंडन और रंजन कुमार मोहंती
5	लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर आई सी ए एस प्रोबेशनर्स के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिसंबर 09-20, 2019	रा लो वि नी सं	अमनदीप कौर
6	वित्त मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठअधिकारियों के लिए लोक वित्त पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम ओडिशा में भागीदार राज्य ओडिशा के साथ संयुक्त रूपआयोजित किया गया	13-17 जनवरी, 2020 तक,	भुबनेश्वर, ओड़िसा	रथिन रॉय और रत्नेश
7	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए लोक वित्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड एकाउंट्स, शिमला में आयोजित किया गया	20-31 जनवरी, 2020	रा लो वि नी सं	सतद्रु सिकदर
8	अंतर-सरकारी वित्तीय संबंधों पर विशेषज्ञ प्रमाणन कार्यक्रम	27 जनवरी -7 फरवरी, 2020	बिशोफ्तु, इथियोपिया	लेखा चक्रवर्ती

प्रकाशन एवं संचार

संस्थान का अर्द्ध वार्षिक समाचार पत्र जुलाई 2019 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें अभी तक चल रही परियोजनाओं, संकाय गतिविधियों और घटनाओं से अवगत किया गया । जनवरी 2020 और जुलाई 2020 का मुद्दा तैयारी के तहत है और जुलाई 2020 में प्रकाशित होने की संभावना है | रा लो वि नी सं संकाय और उनके सहयोगियों द्वारा लिखित कुल 43 वर्किंग पेपर रा लो वि नी सं वर्किंग पेपर सीरीज के तहत प्रकाशित किए गए थे।

विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 47 ब्लॉग लेख रिपोर्टिंग वर्ष में प्रकाशित हुए।

प्रकाशन इकाई ने संस्थान की वेबसाइट www.nipfp.org.in को नियमित रूप से अपडेट करने का कार्य भी किया । ब्लॉग http://nipfp.org.in/blog/ पर उपलब्ध है। रा लो वि नी सं ने अपने ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट पर @nipfp_org_in यूजरनेम के साथ संस्था के अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतिपरक मंडलियों में प्रभावी ढंग से प्रसारित किया |

संस्था के प्रसार के प्रयासों के तहत शोध पत्रों को हितग्राहकों के मध्य प्रचुर मात्रा में वितरित किया गया

(रा लो वि नी सं कार्य पत्रों की सूचि अनुलग्नक – II में दी गयी है , मूल्य अंकित प्रकाशनों की सूची अनुलग्नक V, में दी गई है)

पुस्तकालय तथा सूचना केंद्र

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र में लोक वित्त, आर्थिक नीति, स्थूल एवं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था एवं उद्योग अध्ययन, योजना एवं विकास, आर्थिक सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय एवं नैसर्गिक अर्थव्यवस्था, नगरीय अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र तथा संघवाद एवं विकेन्द्रीकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।

पुस्तकालय के सभी क्रियाकलापों तथा सेवाओं के प्रचालन को एन्ट्रप्राइज जावाबिन्स (ईजीबी) आधारित पुस्तकालय साफ्टवेयर पैकेज एलआईबीएसवाईएस-7.0 के द्वारा कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं।

यहां 65637 से भी अधिक पुस्तकें एवं अन्य पेपर उपलब्ध हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान पुस्तकालय के संग्रह में 296 नए पेपर तथा 11 कार्यशील पेपर जोड़े गए थे। इस पुस्तकालय को अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डिपाजटरी के अंतर्गत 2 नए प्रकाशन प्राप्त हुए हैं। इस पुस्तकालय द्वारा निम्नलिखित राष्ट्रीय / अतर्राष्ट्रीय जनरलों, डाटा बेस जनरलों तथा अन्य आनलाइन जनरलों की सदस्यता ली और प्राप्त की ।

विवरण	कुल संख्या
अंतर्राष्ट्रीय जरनल	32
राष्ट्रीय जरनल	44
पत्रिकाएं	16
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता के अंतर्गत जरनल: अमेरिकन इकनोमिक एसोसिएशन अमेरशन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टिट्यूट फॉर फिस्कल साइंस इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक फाइनेंस	12
निम्नलिखित आनलाइन डेटाबेस के अंतर्गत जरनल: साइंस डायरेक्ट : इकोनॉमिक्स , इॅकोनोमैट्रिक्स एंड फाइनेंस बंडल ओ यू पी ऑनलाइन इकनोमिक जर्नल बंडल कलेक्शन जे एस टी ओ आर (बिज़नेस कलेक्शन । तथा ॥) इकोनलिट पूर्ण टैक्स्ट वर्जन के साथ स्टाटा जरनल	3418

इस पुस्तकालय में 15 पत्रिकाओं के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्र भी उपलब्ध हैं:

क्र। नं।	नेशनल न्यूजपेपर	प्रिंट / ऑनलाइन
1	बिजनेस लाइन	प्रिंट
2	बिजनेस स्टैंडर्ड	प्रिंट
	बिजनेस स्टैंडर्ड + वॉल स्ट्रीट जर्नल	ऑनलाइन
3	इकोनॉमिक टाइम्स	प्रिंट
4	रोजगार समाचार	प्रिंट
5	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	प्रिंट
6	इंडियन एक्सप्रेस	प्रिंट
7	मिंट	प्रिंट
8	नवभारत टाइम्स (हिंदी)	प्रिंट
9	टेलीग्राफ (कोलकाता संस्करण)	प्रिंट
10	हिंदू	ऑनलाइन
11	हिंदुस्तान टाइम्स	प्रिंट
12	द स्टेट्समैन	प्रिंट
13	टाइम्स ऑफ़ इंडिया	प्रिंट
स्ल। नहीं।	**अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र**	**प्रिंट / ऑनलाइन**
1	फाइनेंसियल टाइम्स	ऑनलाइन

इस पुस्तकालय में प्राप्त होने वाले सभी पेपर एवं लेख नियमित तौर पर डेटाबेस में शामिल किए जाते हैं तथा इन्हें नीचे उल्लिखित प्रकाशन बुलेटिनों के माध्यम से जारी किया जाता है:-

- करंट अवेयरनैस सर्विस (पुस्तकों का नया संवर्धन)
- आर्टिकल अलर्ट सर्विस (समाचार पत्रों की क्लीपिंग्स में नया संवर्धन)
- करंट कंटेंट्स सर्विस (पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली आवधिक पत्रिकाओं के कांटेट पृष्ठों का मासिक बुलेटिन)
- बजट पूर्व एवं बजट के पश्चात के विशेष बुलेटिन

इस पुस्तकालय द्वारा करंट अवेयरनैस सर्विस; बिबलोग्राफिक्ल सर्विस एवं रेफरेंस सर्विस भी उपलब्ध कराई जाती है। ईमेल के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी के संकाय सदस्यों को बुक अलर्ट तथा आर्टिकल अलर्ट नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, पुस्तकालय द्वारा निम्लखित ई-रिर्सोसिस के लिए भी सब्सक्राइब किया गया है:-

ई-संसाधन

S.No.	Name of the Database	Web-Link	Mode of Accessibility
1.	आक्सफोर्ड आनलाइन इकॉनोमिक जरनल बंडल क्लेक्शन	http://www.oxfordjournals.org	आईपी आधारित
2.	जेएसटीओर (बिजनेस क्लेक्शन I तथा II)	http://www.jstor.org	आईपी आधारित
3.	एलसेवियर:साइंस डायरेक्ट जनरल: इकॉनोमिक्स, इकोनोमैट्रिक एंड फाइनेंस सब्जेक्ट बंडल	http://www.sciencedirect.com	आईपी आधारित
4.	इकोनलिट पूर्ण टैक्स्ट वर्जन के साथ	http://www.search.ebscohost.com	आईपी आधारित

ई-डेटाबेस:

S.No.	Name of the Database	Web-Link	Mode of Accessibility
1.	ओईसीडी टैक्सेशन लायब्रेरी	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
2.	ओईसीडी इकॉनोमिक्स आई लायब्रेरी	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
3.	ओईसीडी गवर्नेंस आई लायब्रेरी	http://www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
4.	आईबीएफडी इलैक्ट्रानिक आनलाइन	http://www.ibfd.org	यूजर आईडी/ पासवर्ड आधारित एस्सेस (अधिकतम 5 उपयोक्ता)
5.	आईएमएफ ईलायब्रेरी	http://www.elibrary.imf.org	आईपी आधारित
6.	स्टाटा जनरल	http://www.stata-journal.com	पीडीएफ उपलब्ध
7.	ईपीडब्ल्यूआरएफ इंडिया टाइम सीरिज	http://www.epwrfits.in	आईपी आधारित
8.	सीईपीआर (डिस्कशन पेपर)	http://www.cepr.org	(चयनित उपयोक्ताओं के लिए)
9.	इंटरनेशनल टैक्सेशन	http://www.internationaltaxation.taxmann.com	यूजर आईडी/ पासवर्ड आधारित एस्सेस
10.	मनुपत्र (under DEA Project)	www.manupatra.com	यूजर आईडी/ पासवर्ड आधारित एस्सेस

कारपोरेट डेटाबेस :

S.No.	Name of the Database	Web-Link	Mode of Accessibility
1.	सीएमआईई: इकॉनोमिक आउटलुक	http://www.economicoutlook.cmie.com	आईपी आधारित
2.	सीएमआईई: प्रोएसआईक्यू	http://www.prowess.cmie.com	आईपी आधारित
3.	सीएमआईई: कैपेक्स	http://www.capex.cmie.com	आईपी आधारित

इ बुक डेटाबेस

S.No	Name of the Database	Web-Link	Mode of Accessibility
1.	एडवर्ड एलगर ई-बुक्स	https://www.elgaronline.com/browse?access=user&level=parent	आईपी आधारित
2.	**स्प्रिंगर ई-बुक्स सब्जेक्ट बंडल आन इकॉनोमिक्स	http://www.link.springer.com	आईपी आधारित

Note: **यह स्प्रिंगर डेटाबेस वर्ष 2016 से समाप्त कर दिया गया है तथा इसका एस्सेस केवल 2005 से 2015 के लिए उपलब्ध है।

संसाधन सहभाजन:

पेपर डिलीवरी सेवा में और संसाधन सहभाजन के संबंध में पुस्तकालय ने डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (डीईएलएनईटी) के साथ अपनी सदस्यता बरकरार रखी गई । वर्ष के दौरान अन्य पुस्तकालयों से 146 दस्तावेज ऋण पर लिए गए तथा अन्य पुस्तकालयों को 50 दस्तावेज दिए गए। वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 207 बाह्य अनुसंधान स्कालरों तथा नीति निर्माताओं द्वारा पुस्तकालय का दौरा किया गया।

विजिटर रिकार्ड: 2019-20

Visitors Record: 2019-20 (Month Wise)	No of Visitors
अप्रैल	11
मई	22
जून	12
जुलाई	12
अगस्त	23
सितम्बर	31
अक्तूबर	22
नवम्बर	14
दिसम्बर	41

जनवरी	11
फरवरी	4
मार्च	4
जोड़	**207**

आरईपीईसी (अर्थशास्त्र के लिए अनुसंधान पेपर)

आरईपीईसी 87 देशों के सैंकड़ों स्वयंसेवको का सामूहिक प्रयास है जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र सम्बंधित विज्ञानों के अनुसंधान के वितरण को प्रोत्साहित किया जाता है । इस परियोजना का मर्म कार्यशील दस्तावेजों, पुस्तकों, पुस्तक अध्यायों का आनलाइन विकेन्द्रित ग्रंथागार है जिसका अनुरक्षण स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थानपुस्तकालय द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय विषय की इस रिपोजिटरी आरईपीईसी (अर्थशास्त्र के लिए अनुसंधान पेपर) में प्रतिभागिता करके संस्थान के कार्यशील दस्तावेजों का मैटाडाटा अपलोड किया गया है। वर्ष के दौरान आरईपीईसी (अर्थशास्त्र के लिए अनुसंधान पेपर) में 43 कार्यशील पेपर अपलोड किए गए थे। विश्व भर में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थानके इन कार्यशील पेपरों को 2281 बार डाउनलोड किया गया तथा 10382 बार इसके संक्षेप सार का अवलोकन किया गया।

आरईपीईसी कार्यशील पेपर सीरिज 2019-20 की एस्सेस सांख्यिकी

डाउनलोड तथा सार प्रेक्षण की संख्या		
अप्रैल **2019**-मार्च **2020**		
माह	डाउनलोड	सार प्रेक्षण
2019-04	186	766
2019-05	210	662
2019-06	117	546
2019-07	168	684
2019-08	150	723
2019-09	254	894
2019-10	171	1034
2019-11	201	1175
2019-12	184	1018
2020-01	271	1312
2020-02	172	817
2020-03	197	751
जोड़	**2281**	**10382**

रैप्रोग्राफिक सेवाएं

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय संसाधन सामग्री के लिए संकाय सदस्यों तथा बाह्य अनुसंधान स्कालरों को रैपरोग्राफिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। उपयोक्ताओं द्वारा हमारे रैपरोग्राफिक रोस्टर का सराहना की गई है। लगभग 6000 पृष्ठों की फोटोकापी की गई सामग्री अनुसंधान कार्य के लिए उपयोक्ताओं को वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई थी। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान पुस्तकालय में रैप्रोग्राफिक नयाचार का अनुसरण कापीराइट उल्लंघन नहीं किया जाता है।

पुस्तकालय :कर्मचारी गतिविधियां (2019-20)

पत्र प्रकाशित / प्रस्तुतः

- खान, मो। ***ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज के माध्यम से भारतीय पुस्तकालयों के बदलते परिदृश्य"*** *8"वें पुस्तकालय और सूचना पेशेवर शिखर सम्मेलन)I-LIPS 2019) के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन* ***"साझा भविष्य के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों से पुस्तकालयों को सशक्त करना "*** 22-24 नवंबर, 2019 को ऑडिटोरियम, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यह सम्मेलन कई अन्य प्रतिष्ठित भारतीय पुस्तकालय संघों के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग और गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

संगोष्ठी सम्मेलन, संगोष्ठी कांग्रेस

- खान, मो। आसिफ एक *विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क (डेलनेट)28वीं वार्षिक आम बैठक* 9अप्रैल 2019 डेलनेट, जेएनयू कैम्पस, वसंत कुंज, नई दिल्ली में भाग लिया ।
- खान, मो। आसिफ ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया ***"सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में पुस्तकालयों की भूमिका",*** 12 अप्रैल, 2019 को IGNCA स्थलऑडिटोरियम :, CV मेस बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली में। यह संगोष्ठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और एशियाई पुस्तकालय संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।
- खान, मो। आसिफ *32nd स्थापना दिवस व्याख्यान पर कार्यक्रम* ***"त्वरित आर्थिक विकास और ट्रिकल डाउन सुधारेतर अवधी में भारतीय अनुभव और नीतिगत विकल्प : "*** मई, 2019 संस्थान औद्योगिक विकास में अध्ययन के लिए (आईएसआईडी), वसंत कुंज में, नई दिल्ली में भाग लिया
- खान, मो। आसिफ ने ***"लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन"*** पर पांच दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 21 जून, 2019 में साउथ कैंपस, नई दिल्ली में भाग लिया।

खान, मो। आसिफ ने ***"एल्सेवियर कनेक्ट फोरम 2019"*** 16 सितंबर, 2019 को IIT दिल्ली में भाग लिया। यह कार्यक्रम एल्सेवियर द्वारा IIT दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था ।

कमप्यूटर सेंटर

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की कंप्यूटर यूनिट शैक्षणिक बिरादरी के साथ साथ संस्थान के अन्य-कार्यालय, जैसे लेखा, प्रशासन, सभागार, पुस्तकालय, प्रकाशन और संचार को महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करती है। कंप्यूटर केंद्र संकाय और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पुराने सिस्टम को निरंतर संवर्धित करता रहता है। रा लो वि नी सं परिसर पूरी तरह से वाईफाई नेटवर्क सक्षम है।

संस्थान की इंटरनेट सुविधा (nipfp.org.in) एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन), और एम.टी.एन.एल द्वारा समर्थित है। वेबसाइट का प्रबंधन रा लो वि नी सं के प्रोफेसर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जा रहा है।

पुस्तकालय और लेखा विभाग को विशेष सॉफ्टवेयर प्रदान किया गया है । जबकि लिब्सिस और प्रोवेस के माध्यम से पुस्तकालय को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, लेखा विभाग के काम को सुविधा प्रदान करने के लिए ई एक्स एकाउंट्स और पे रोल सॉफ्टवेयर प्रदान किए गए हैं कंप्यूटर यूनिट कंप्यूटर समिति द्वारा समयसमय पर तैयार की गई समग्र नीति मार्गदर्शन के- तहत कार्य कर रही है।

संकाय क्रियाकलापों के मुख्यअंश

राथिन रॉय

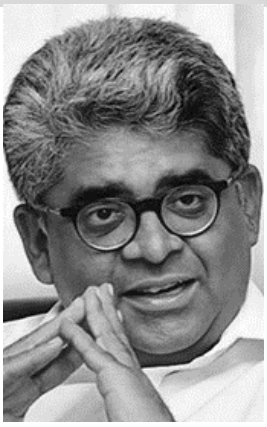

डॉ. राथिन रॉय, निदेशक ने "एसडीजीएस के लिए बॉन्ड" यूएनडीपी और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित गोलमेज कार्यशाला में भाग लिया।

इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस बांग्लादेश (IPF) ढाका और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान नई दिल्ली के बीच उपयोगी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर समारोह में 29 अप्रैल से 2 मई 2019 को भाग लिया।

निम्नांकित पैनलों में भाग लिया 1. ए आई के समय में अधिकार: इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और पब्लिक लॉ फ्रेमवर्क 2. भारत के लिए 21 वीं सदी के राज्य का निर्माण करने में क्या लगेगा? 2 मार्च 2020 को सिल्वर ओक, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में "21 वीं सदी के भारत के लिए नीति परिप्रेक्ष्य" पर सीपीआर संवाद में सीपीआर की राज्य क्षमता पहल का शुभारंभ।

सामाजिक नीति वित्तपोषण का अनुश्रवण: रुझान एवं उभरते मुद्दे पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया| यह आयोजन सीपीआर द्वारा 3 मार्च 2020 को सीपीआर, द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया |

15 जुलाई 2019 को पुणे में सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित बजट विश्लेषण 2019 पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया।

पुणे में 12 जुलाई, 2019 को पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट (पीआईसी)2019-20 के एक सत्र में भाग लिया।

1 नवंबर 2019 को पूजा मेहरा द्वारा लिखित पुस्तक "द लॉस्ट डेकेड" (2008-18): हाउ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी डिवॉल्वड इंटू ग्रोथ विथाउट ए स्टोरी पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में 1 मई को आयोजित की गयी चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया |

रा लो वि नी सं दिल्ली, आईपीएफ ढाका के बीच समझौता ज्ञापन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ढाका का दौरा किया| 11-15 नवंबर 2019

आमंत्रित व्याख्यान

11 अप्रैल 2019 को आर्यभट कॉलेज, नई दिल्ली में सामाजिक विकास एवं न्याय के एक सत्र में भाषण दिया|

ए डी आर आई , पटना द्वारा आयोजित कार्यक्रम "बाल बजट बिहार : वर्तमान अभ्यास और भविष्य के निर्देश" पर एक संगोष्ठी में एक उद्घाटन सत्र के लिए आमंत्रित किया गया|

17 से 21 मई 2019 के दौरान सिंगापुर में डी बी एक्सेस सम्मेलन 201 9 में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया।

8 जून 2019 को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), कोलकाता द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक आउटलुक 2019 में "भारतीय अर्थव्यवस्था: नीति पॉपुलिज्म, विकास, सुधार और रोजगार के बीच संतुलन" पर एक सत्र में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया।

14 जून 2019 को केंद्रीय बजट 2019-20 के संबंध में प्री बजट परामर्श-के निमित्त माननीय वित्तमन्त्री श्रीमति निर्मला सीतारमण एवं विभिन्न हितधारक समूहों के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया गया ।

14 जून 2019 को 'रूट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी: पॉलिसी प्रायोरिटीज़ फ़ॉर द 100 डेज' में एक पैनल चर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया।

20 जून, 2019 को सीनेट, द क्लेरम्स, नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के साथ-साथ आर्थिक नीति अनुसंधान केंद्र (सीईपीआर) द्वारा आयोजित नई दिल्ली में एनबीएफसी पर एक बंद दरवाजे के गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया।

25 जून से 3 जुलाई 2019 के दौरान लंदन और किगाली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF), नई दिल्ली द्वारा आयोजित कैम्ब्रिज वर्कशॉप और यूके-इंडिया वीक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

22 अगस्त 2019 को ताज पैलेस होटल, नई दिल्ली में माइंडमीन शिखर सम्मेलन 201 9 में एक राष्ट्र, एकाधिक भाग्य पर "की स्थायित्व भारत में सार्वजनिक वित्त पोषित आधारभूत परियोजनाओं" पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया|

9 अगस्त 2019 को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित "भारत में लोक वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिरता - एक प्रमुख चिंता" विषय पर मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

17 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा आयोजित आयोग के अधिकारियों के लाभ के लिए केंद्रीय बजट 2019-20 पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया।

7-10 जुलाई 2019 को अदीस अबाबा, इथियोपिया नई दिल्ली में दो संस्थानों के मध्य एफओएफ, अदीस अबाबाद - रा लो वि नी सं और अन्य जीओई साझेदारों के उपयोगी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया ।

24 सितंबर 2019 को ASSOCHAM, भारत, ताजमहल होटल, मानसिंह रोड, नई दिल्ली में, 12 वीं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन गोल्ड इकोनॉमिक फोरम" द्वारा आयोजित एसोचैम में भारत कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है" का मुख्य विषय आर्थिक मंदी और भारत में बेरोजगारी है"" एवं ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग फोरम: भारत कैसे स्वर्ण में आत्मनिर्भर बन सकता है" के आधार पर '5 ट्रिलियन इकोनॉमी को

साकार करने के लिए भारत के गोल्ड उद्योग को एकीकृत करता है।" आदि प्रमुख मुद्दों और समाधान में प्रतिभागी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया|

25 सितंबर 2019 को स्कोच द्वारा कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित 61 वें SKOCH समिट में मुख्य भाषण दिया।

27 सितंबर 2019 को जयपुर में राज्य के लिए प्रस्तावित आर्थिक परिवर्तन परिषद (ईटीसी) के लिए संदर्भ की शर्तों को विकसित करने के लिए राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र में भाग लिया।

30 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में विदेशी सेवा संस्थान (एफएसआई) द्वारा विदेशी राजनयिकों के लिए 68 वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में "विश्व अर्थव्यवस्था: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य" विषय पर राजनयिकों को संबोधित करने के लिए आमन्त्रित किया गया।

30 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के सेंटर में सेल्फ एम्प्लॉइड वूमन्स एसोसिएशन (एसईडब्ल्यूए) और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेषज्ञ वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) में भाग लिया।

10 अक्टूबर 2019 को आयोजित एलीवेटिंग इंडिया: द जर्नी टू 5 डॉलर ट्रिलियन इकोनॉमी' पर सीईपीआर, नई दिल्ली द्वारा पैनल डिस्कशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

14 अक्टूबर 2019 को नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड एकाउंट्स (NAAA) शिमला द्वारा आयोजित 1994 बैच के वरिष्ठ आईए और एएस अधिकारियों के लिए 5-दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में "भारत में समावेशी और सतत विकास" विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया गया।

17 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित छठवें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन "गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां 2019" में एक प्रमुख वक्ता के रूप में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।

18-20 अक्टूबर, 2019 को कोच्चि, केरल में IDFC इंस्टीट्यूट और कार्नेगी एंडोमेंट द्वारा इंटरनेशनल पीस के लिए संयुक्त रूप से आयोजित राजनीतिक अर्थव्यवस्था सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

2 नवंबर, 2019 को व्यवसायिक अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैंपस द्वारा आयोजित 46 वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

4 नवंबर 2019 को मसूरी के LBSNAA में IAS के अधिकारियों के लिए चतुर्थ चरण मिड-कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (MCTP) के प्रतिभागियों को "अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन और आगे आने वाली चुनौतियां" विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।

5 नवंबर, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस ए आर टीटी ए सी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में "बांग्लादेश के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक्स के मुद्दों" पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया।

6 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित भारत सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2019 में सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंस 'पर पूर्ण सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

18 नवंबर, 2019 को सेबी हेड ऑफिस, मुंबई में सेबी अधिकारियों के लिए 'वित्तीय बाजारों' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।

27 नवंबर 2019 को नई दिल्ली के संविधान क्लब में पीआरएस इंडिया द्वारा आयोजित अर्थव्यवस्था और नीतिगत कार्यों की स्थिति पर सांसदों से बात करने के लिए आमंत्रित किया गया।

2 दिसंबर 2019 को सीयूटीएस - सीआइआरसी द्वारा आयोजित छठवें द्विवार्षिक सम्मेलन में "बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विपुल शासनों के मामले में तेजी से ऑनलाइन विकास की दुनिया में" " सतत विकास के लिए विकासशील दुनिया में ऑनलाइन अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता आगे बढ़ने के लिए " विषय पर सतत सत्र में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 11-14 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पूर्ण रोजगार के भविष्य पर रोजगार नीति अनुसंधान संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

9 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में भारत कृषक समाज द्वारा आयोजित "भारतीय अर्थव्यवस्था और किसान - की राह" सम्मेलन में पैनल डिस्कशन में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

25-29 जनवरी 2020 को एडिस अबाबा, इथियोपिया में रा लो वि नी सं, नई दिल्ली और एफओएफ, अदीस अबाबाद के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत आईजीएफआर प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

पुणे इंटरनेशनल सेंटर, पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स द्वारा 3 फरवरी, 2020 को आयोजित 'यूनियन बजट 2020-21' पर सत्र में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया।

6 फरवरी 2020 को केरल के कोच्चि में 131 साल पुराने प्रकाशन समूह मलयाला मनोरमा द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट 2020-2021 पर विशेष व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।

14 फरवरी 2020 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया और 11 को एलईटी इवेंट में भी भाग लिया और 15-16 फरवरी, 2020 को बोस्टन, अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा आयोजित "20/20 दूरदर्शिता" इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया|

24 फरवरी 2020 को पी एफ एम और सेवा वितरण पर ओ डी आई वार्षिक सम्मेलन और अनुसंधान और साक्ष्य के उपयोग पर सरकारों के साथ काम करने पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

4 मार्च 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण से गुजरने वाले 'ग्रुप ए' के वित्त सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों, आई सी ए एस, आई डी ए एस, आई आर ए एस और आई पी एंड टी ए एफ एस के लिए 'रोडमैप से यूएसडी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी' पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया।

6 मार्च 2020 को देहरादून के एलबीएसएनएए में 7-9 वर्ष की सेवा के आईएएस अधिकारी के लिए द्वितीय चरण के मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में "डिकोडिंग इंडियाज स्लोडाउन" पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।

अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ

8 से -12 जुलाई, 2019 तक भारतीय आर्थिक सेवा प्रोबेशनरों के लिए लोक वित्त पर पाठ्यक्रम के लिए "भारत की मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति का अंकगणित" पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

22 जुलाई, 2019 को सुधार और विकास परिप्रेक्ष्य 5-। केंद्रीय बजट 2019-20 में व्याख्यान दिया|

2 दिसंबर, 2019 को वरिष्ठ आई ए ए एस अधिकारी के लिए एक सप्ताह के उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम में लोक वित्त में समकालीन मुद्दों पर व्याख्यान दिया गया|

9 दिसंबर, 2019 को शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए लोक वित्त में दो सप्ताह के 13 वें रिफ्रेशर कोर्स में व्याख्यान प्रस्तुत किया।

9 दिसंबर, 2019 को लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर आईसीएएस प्रोबेशनर्स के लिए दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान दिया।

13 जनवरी, 2020 को बांग्लादेश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए " लोक वित्त" पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान दिया|

20 जनवरी, 2020 को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारियों प्रशिक्षुओं के लिए "लोक वित्त" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान प्रस्तुत किया।

27 जनवरी, 2020 को इथियोपिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त विभाग से इथियोपिया, हाउस ऑफ फेडरेशन और अधिकारियों के समक्ष अंत:सरकारी राजकोषीय संबंधों पर विशेषज्ञ प्रमाणन कार्यक्रम में व्याख्यान प्रस्तुत किया।

8 फरवरी, 2020 को सुधार और विकास परिप्रेक्ष्य में 5-। केंद्रीय बजट 2020-21 में व्याख्यान दिया|

समितियों, विशेषज्ञ समूहों आदि में नियुक्ति

सदस्य, वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्तियाँ खोज समिति|

एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण यू एन ई एस सी ए पी के लिए विशेषज्ञ समूह के सदस्य|

फेलो, कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ सोसाइटी।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सतत वित्तीय प्रणाली में जांच - सदस्य, भारत सलाहकार समिति।

सदस्य, समावेशी विकास पर मेटा परिषद, विश्व आर्थिक मंच, जिनेवा।

सदस्य, भारत में जैव विविधता वित्त पहल के लिए तकनीकी सलाहकार समूह, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार (8 मई 2015 के उपरान्त)|

आरआईएस में संकाय पदों की व्यापक समीक्षा और उनके वेतनमान की समीक्षा करने के लिए आरआईएस समीक्षा समिति सदस्य।

सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष के ज्ञान/अनुसंधान पहल पर कोर समूह समिति।

सदस्य, अनुसंधान सलाहकार परिषद (आरएसी), आरआईएस।

सदस्य, शहरीकरण के सलाहकार बोर्ड आई.आई.एच.एस. बैंगलोर।

सदस्य, भारत से वित्तीय सेवाओं (एफएसडब्ल्यूजी) पर ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल वर्किंग ग्रुप।

सदस्य, सतत विकास पर भारत के स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा हेतु टास्क फोर्स 10-19 जुलाई 2017

सदस्य, 'राजकोषीय क्षेत्र पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

अध्यक्ष, मूल्यांकन निगरानी समिति, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग, नई दिल्ली।

सदस्य, नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप "समावेश: नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक प्रस्ताव" - ज्ञान और अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्किंग और साझेदारी के लिए तंत्र

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (31 अगस्त 2019 तक) के लिए नियुक्त सदस्य।

सदस्य, अग्रानुक्रम सलाहकार बोर्ड - मई 2018 से|

विशेष आमंत्रित, संचालन समिति, एसडीजी वित्तीय सुविधा, यूएनडीपी

आईआईटी, कानपुर में आर्थिक विज्ञान विभाग के प्रतिष्ठित मानद प्रोफेसर पद पर दो साल की अवधि के लिए नियुक्त (01.11.2019 से 31.10.2021 तक)|

सदस्य, मुख्यमंत्री की आर्थिक परिवर्तन परिषद, राजस्थान सरकार फरवरी 2020 से मार्च 2022 तक (यदि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया)

सदस्य, नीति आयोग के राष्ट्रीय डाटा और विश्लेषिकी प्लेटफ़ॉर्म परियोजना के लिए उच्च शक्ति अंतर-मंत्रालय समिति - फरवरी 21, 2020

राज्य को फिर से खोलने और विशेष रूप से आर्थिक नीतियों के बारे में सलाह देने के लिए पंजाब सरकार की सहायता के लिए एक समिति के सदस्य।

सदस्य, सलाहकार बोर्ड, स्कूल ऑफ पॉलिसी, गीतम विश्वविद्यालय

आर. कविता राव

8 जुलाई 2019 को भारतीय आर्थिक सेवा (IES) प्रोबेशनर्स के लिए लोक वित्त पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में "भारत में कर नीति डिजाइन में चुनौतियां" विषय पर व्याख्यान,

सी ए जी के वरिष्ठ अधिकारी के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में “अनअकॉउंटेड इनकम” ’पर व्याख्यान दिया, 4 दिसंबर 2019

4 दिसंबर 2019 को सी ए जी के वरिष्ठ अधिकारी के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में "जीएसटी" पर व्याख्यान दिया

एन आर भानूमुर्ति

25 मई 2019 को प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्वालियर द्वारा आयोजित चतुर्थ समावेशी वित्त सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।

पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, 11-12 जून, 2019 को "एशिया का विकास अनुभव 21 वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में दक्षिण एशिया में वित्तीय वैश्वीकरण और विकास पर एक पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया।

26 जून, 2019 को "भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल", एस सी ओ पी ई, पर विचार दिये|

13-14 जून, 2019 को भारतीय सांख्यिकी सेवा, आईएसईसी बैंगलोर के प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए कार्यशाला में टाइम सीरीज़ ईकॉनोमेट्रिक्स पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया|

9 जुलाई, 2019 को एनसीएईआर द्वारा आयोजित इंडिया पॉलिसी फोरम में चर्चाकार के रूप में आमंत्रित किया गया|

11 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में पीजीपी छात्रों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्दों पर दो व्याख्यान दिए|

26 जुलाई, 2019 को ब्रिटिश उच्चायोग, केंद्रीय बजट पर एक चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में उपस्थिति दी|

8 अगस्त, 2019 को भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्दों पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में पीजीपी छात्रों के लिए दो व्याख्यान दिए गए|

23 अगस्त, 2019 को एन ए एल एस ए आर हैदराबाद द्वारा आयोजित 19 वीं मूल आय पृथ्वी नेटवर्क कांग्रेस में पैनलिस्ट के रुप में प्रस्तुति|

11 सितंबर, 2019 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ में पीजीपी के छात्रों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्दों पर दो व्याख्यान दिए|

26 सितंबर 2019 में आईपीएस, कोलंबो, श्रीलंका द्वारा आयोजित 12 वें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया|

20 अक्टूबर, 2019 को वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, "भारत में मैक्रों-राजकोषीय मुद्दों" पर एक वार्ता दी|

30 अक्टूबर, 2019 को आईआईपीए में ए पी पी पी ए कार्यक्रम के लिए "सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन और कार्यक्रमों का मूल्यांकन" पर चर्चा के लिए एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया।

2 नवंबर, 2019 को भारत में राजकोषीय-मौद्रिक नेक्सस पर भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ, नोएडा परिसर में एमडीपी के छात्रों के लिए दो व्याख्यान दिए, ।

15 से 17 नवंबर, 2019 को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा आयोजित "$ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में चुनौतियां" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया।

21 नवंबर, 2019 को कोचीन, महाराजा कॉलेज में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया

22 नवंबर 2019 को मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, चेन्नई द्वारा आयोजित "स्थिरता के साथ विकास: आर्थिक संभावनाएं और भारत में चुनौतियां" विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया।

29 वें, 2019 को एस के ओ सी एच द्वारा आयोजित भारत आर्थिक मंच सम्मेलन के दौरान "कल्याणकारी अर्थशास्त्र" पर चर्चा के लिए एक पैनेलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया।

15 दिसंबर, 2019 को फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा आयोजित एफएमएस स्टेट ऑफ द यूनियन डिबेट के लिए जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया।

9 जनवरी, 2020 को मदुरै में, इंडियन इकॉनोमेट्रिक सोसाइटी के 56 वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान "राजकोषीय नीति, हस्तांतरण और भारतीय अर्थव्यवस्था" पर एक पत्र प्रस्तुत किया।

21, जनवरी, 2020 को आईआईपीए में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा आयोजित राज्य विधायकों के लिए "राज्य वित्त कार्यशाला" के दौरान एक व्याख्यान दिया।

3 फरवरी, 2020 को एस सी ओ पी ई, नई दिल्ली, में "केंद्रीय बजट: 2020-21" पर मुख्य भाषण की प्रस्तुति|

7 फरवरी, 2020 बी आई एम टी ई सी, नोएडा, द्वारा आयोजित "केंद्रीय बजट: 2020-21 और भारतीय अर्थव्यवस्था" पर एक चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित|

15 फरवरी, 2020 को जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद, द्वारा आयोजित "उद्योग: 4.0" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक सत्र की अध्यक्षता की|

18 फरवरी, 2020 को आईआईएफटी, नई दिल्ली में "भारत में राजकोषीय-मौद्रिक सांठगांठ" पर एक चर्चा में शामिल हुये|

13 मार्च, 2020 को आईएम टी गाज़ियाबाद में "भारत में वृहद-राजकोषीय नीतियों में उभरते मुद्दों" पर एक चर्चा में शामिल हुये

10 जुलाई, 2019 को आईईएस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए "भारत में मैक्रो-फिस्कल इश्यूज" पर एक चर्चा में शामिल हुये

3 दिसंबर, 2019 को आई ए ए एस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भारत में राजकोषीय-मौद्रिक सांठगांठ पर एक वार्ता में प्रस्तुति दी|

22 जनवरी, 2020 को आई ए ए एस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए "सार्वजनिक व्यय दक्षता" पर विचार प्रस्तुत किए|

17 दिसंबर, 2019 आईसीएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए भारतीय मैक्रोइकॉनॉमिक्स में मुद्दों पर एक चर्चा में उपस्थिति दी |

नवंबर, 2019 के दौरान NIPFP में कॉलेज व्याख्याताओं के लिए आयोजित रिफ्रेशर कोर्स के लिए 'राजकोषीय समेकन' पर दो व्याख्यान दिए|

समितियों, विशेषज्ञ समूहों आदि में नियुक्ति

सदस्य, राज्य सरकारों के तरीके और साधन अग्रिम पर सलाहकार समिति, भारतीय रिज़र्व बैंक, (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) अगस्त, 2019 से|

निगरानी और मूल्यांकन उच्च स्तरीय सलाहकार समिति, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, (अध्यक्ष: सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय) में जून 2019 से सदस्य|

सदस्य, पीएमएवाई-ग्रामीण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार -2019 के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए समिति, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, (अध्यक्ष: डॉ। नागेश सिंह) अक्टूबर 2019 से सदस्य

सदस्य, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सलाहकार समिति|

सदस्य, उप-राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की समिति, (अध्यक्ष: प्रो रविंद्र एच. ढोलकिया) जून 2018 से

सदस्य, गन्ना और चीनी उद्योग पर टास्क फोर्स, नीति आयोग, (अध्यक्ष: प्रो. रमेश चंद) दिसंबर 2018 से

सदस्य, विशेषज्ञों की स्थायी तकनीकी समिति, आयात निर्यात बैंक ऑफ इंडिया|

सदस्य, बोर्ड ऑफ़ इंडिया टुडे इकोनॉमिस्ट, 2017 से |

सदस्य, शासी निकाय, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स, नई दिल्ली|

सदस्य, संपादकीय सलाहकार बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक समसामयिक पत्र|

जूरी मेंबर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च अवार्ड - 2020, आयात निर्यात बैंक ऑफ इंडिया|

सदस्य, वार्षिक सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार समिति - 2019, , भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।

सदस्य, ओडिशा के ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पांचवें आम समीक्षा मिशन। नवंबर, 2019

सदस्य, कर्नाटक के जीएसडीपी के अनुमान के लिए समिति, कर्नाटक निगरानी प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार, (अध्यक्ष: प्रमुख सचिव, योजना)| सितंबर 2019 से

सचिव, द इंडियन इकॉनोमेट्रिक सोसाइटी|

प्रबंधक न्यासी, द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट|

अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ

वाइ.वी. रेड्डी और जी.आर. रेड्डी द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा 2019 में, "भारतीय राजकोषीय संघवाद" की समीक्षा, भाग 54, नंबर 1, पृ.सं.193-195|

रमेश चंद्र दास, एमराल्ड प्रकाशन, यूके, 2019 द्वारा "21 वीं सदी में मौद्रिक नीति के प्रभाव" पर एक संपादित पुस्तक के लिए "प्राक्कथन"।

पीएचडी थीसिस परीक्षक, पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पांडिचेरी विश्वविद्यालय और कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में।

समीक्षक: सामाजिक और आर्थिक विकास के जर्नल, अर्थशास्त्र और वित्त की त्रैमासिक समीक्षा, मात्रात्मक अर्थशास्त्र के जर्नल, आर्थिक अनुसंधान के बुलेटिन, आरबीआई वर्किंग पेपर्स, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, जोखिम विश्लेषण, सर्वखान, भारतीय आर्थिक समीक्षा, सार्वजनिक मामलों के जर्नल, मार्जिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, स्प्रिंगर बुक्स, सूक्ष्म वित्त समीक्षा।

ईला पटनायक –

30 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली के ने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा आयोजित आई ए ए एस ऑफिसर प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में "भारतीय अर्थव्यवस्था" पर बातचीत की गई।

5 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित "वितीय क्षेत्र सुधार" पर अपने विचार रखे।

1 फरवरी, 2020 को एन डी टी वी पर "बजट 2020 चर्चा" में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

9 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित "भारत के माननीय प्रधान मंत्री के साथ पूर्व-बजट परामर्श" पर एक गोलमेज चर्चा में भाग लिया।

12 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च द्वारा आयोजित सेंटर फॉर इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव की कार्यशाला में "बैंकों के लिए रोड मैप" पर सत्र के लिए एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

21 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में ओआरएफ - भारत त्रिपक्षीय फोरम द्वारा आयोजित सेमिनार "मोदी 2.0 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था" में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

18 अक्टूबर, 2019 को कोच्चि, केरल में आईडीएफसी द्वारा आयोजित “अर्थ डायलॉग्स: स्टेट कैपेसिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स:” भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी प्रॉमिस - रेटोरिक टू रियलिटी सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

10 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च द्वारा आयोजित “एलीवेटिंग इंडिया: द जर्नी टु ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी” पर पैनल चर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

18-19 सितंबर, 2019 से यू.एस. वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में द हेरिटेज फाउंडेशन के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित इंडिया ऑन द हिल: भारत अमरीका संबंधों के भविष्य का अंकन सम्मेलन में "न्यू इंडिया - यू.एस. ट्रेड नॉर्मल का सामना" पैनल में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया|

11-12 सितंबर, 2019 से ब्राज़ीलिआ में ब्रिक्स और इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (आईपीईए) द्वारा आयोजित सहयोग और विकास के नए तरीकों की खोज, ब्राजील ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2019 में "ब्रिक्स व्यापार और निवेश एजेंडा" पर पैनल में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

9 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा आयोजित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक, डेम मिनोच शफीक के साथ "अनपैकिंग इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी" पर गोलमेज चर्चा में भाग लिया।

4 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च (CEPR) द्वारा आयोजित "5 ट्रिलियन $ अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप" पर गोलमेज सम्मेलन में वक्ता के रूप में भाग लिया।

27 अगस्त, 2019 को ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा द्वारा आयोजित जिंदल ग्लोबल लेक्चर सीरीज के लिए "भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल" विषय पर व्याख्यान दिया।

18 जून, 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 5 वीं तिमाही के इकॉनमिस्ट्स हडल "भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने" में भाग लिया।

12-13 जून, 2019 को स्वीडन के माल्मो में जर्मन मार्शल फंड ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स (GMF) और स्वीडिश विदेश मंत्रालय के सहयोग से 16वें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारतीय त्रिपक्षीय फोरम "कनेक्टिंग कॉन्टिनेंट्स: ए चाइनीज प्रोगेरेटिव?" सत्र में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

16 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित "भारत के लिए विज़न फॉर 2030" सम्मेलन में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

जुलाई 2019 में भारतीय उद्योग परिसंघ - इंडिया टुडे बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ - इंडिया टुडे बजट राउंड टेबल पैनल की चर्चा में भाग लिया|

दिसंबर 2019 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन के द्वारा निर्देशित "भारत की महा-मंदी: क्या हुआ? रास्ता क्या है?" पर पैनल चर्चा में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया

समितियों, कार्य समूहों, कार्य बलों की सदस्यता –

सदस्य, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली की अकादमिक परिषद।

सदस्य, टास्क फोर्स डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करने की समिति।

अजय शाह

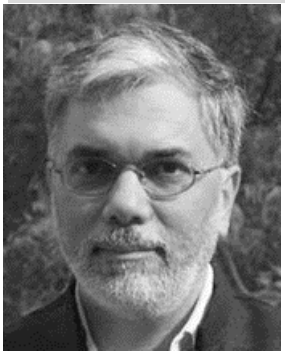

9-20 दिसंबर 2019 से लोक वित्त और नीति, नई दिल्ली वित्त मंत्रालय INGAF (भारत सरकार) के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस (ICAS) प्रोबेशनर्स के लिए लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में "रिपब्लिक-द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी की सेवा" पर पुस्तक चर्चा में भाग लिया।

25 से 29 नवंबर, 2019 को शिमला में नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड एकाउंट्स द्वारा आयोजित वरिष्ठ भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा सेवा अधिकारियों के लिए एडवांस्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में "आर्थिक नीति की कला और विज्ञान" पर एक चर्चा में प्रस्तुति।

22 नवंबर, 2019 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा मसूरी में आयोजित आईएएस अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ चरण में "नियमन" पर व्याख्यान दिया गया।

14-18 अक्टूबर, 2019 से शिमला में नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए "नियामक निकायों की लेखा परीक्षा" पर बातचीत में शामिल हुए।

16-25 अगस्त, 2019 को मोहाली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा आयोजित लोक नीति में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में "मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर पॉलिसी मेकर्स" पर व्याख्यान दिया।

4 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा आयोजित बी. आर. अम्बेडकर व्याख्यान श्रंखला में “आडिट के सिद्धांत - विनियामक कार्यों का आडिट” पर एक संयुक्त व्याख्यान दिया।

21 जून, 2019 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा मसूरी में आयोजित IAS अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पंचम चरण पर “सार्वजनिक अर्थशास्त्र और नियामक डिजाइन सहित विनियमन पर संयुक्त सत्र में व्याख्यान दिया।

24-25 अप्रैल, 2019 को शिमला में नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड एकाउंट्स द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं को "भारतीय अर्थव्यवस्था" पर बातचीत में व्याख्यान दिया।

13 अप्रैल, 2019 को एनएमआईएमएस विश्वविद्यालय, मुंबई में विधि संकाय के लिए "प्रतिभूति धोखाधड़ी और हमें इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए" पर विचार विमर्श में शामिल हुये।

3 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में कैग द्वारा आयोजित कैग अधिकारियों के लिए “जीडीपी मापन में मुद्दे” पर कैग - रा लो वि नी सं कार्यशाला में भाग लिया और परिचयात्मक टिप्पणी दी।

10 जनवरी, 2020 को रा लो वि नी सं, नई दिल्ली में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु के सहयोग से "गणतंत्र को मजबूत करने" पर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय - रा लो वि नी सं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

9 से 10 दिसंबर, 2019 तक नई दिल्ली केंद्र में शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "चेन्नई 2015: प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मापने के लिए एक नया दृष्टिकोण" सम्मेलन में भारत के शहरी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने पर चर्चा में भाग लिया|

1-2 दिसंबर, 2019 से नई दिल्ली में सीयूटीएस-सीआइआरसी द्वारा आयोजित 6वें द्विवार्षिक सम्मेलन “विकासशील देशों में प्रतिस्पर्धा और नियामक व्यवस्था के मामले में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन अर्थव्यवस्था” में "इंटरफेस इन कॉम्पिटिशन रिजीम एंड सेक्टर स्पेसिफिक रेमेडीज इन ऑनलाइन इकोनॉमी: चैलेंजेज एंड अपॉर्च्युनिटीज ऑन ऑप्शंस" सत्र में भाग लिया।

29 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में प्रोफेसर लैंट प्रिट्चेट द्वारा आयोजित " गड्ढे में भारत की अर्थव्यवस्था: खुदाई जारी रखें?" सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा आयोजित चर्चा में भाग लिया।

18 से 20 अक्टूबर, 2019 को कोच्चि, केरल में आईडीएफसी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित " अर्थ डायलॉग्स: स्टेट कैपेसिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स: "नाइटकैप कन्वर्सेशन रिबूटिंग द इंडियन स्टेट " पर सत्र के लिए एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

10-11 अक्टूबर, 2019 को शिमला में फ्रेडरिक नौमन फाउंडेशन द्वारा आयोजित "डिजिटलीकरण" के सत्र में चर्चाकार के रूप में; "गोपनीयता विनियमन के दृष्टिकोण" पर सत्र में मध्यस्थ के रूप में भाग लिया; और सम्मेलन में समापन टिप्पणियां दीं।

सेंटर ऑफ़ फ़ाइनेंस, लॉ एंड पॉलिसी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशिगन, 2-3 अक्टूबर, 2019 से ऐन आर्बर, मिशिगन में सेंटर फॉर फ्यूचर कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित सेंट्रल बैंक ऑफ़ फ़्यूचर कॉन्फ्रेंस में "सेंट्रल बैंक अपॉर्च्युनिटीज़ टू इनक्लूज़न" पैनल में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

19 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 6वीं तिमाही इकॉनमिस्ट्स हडल में "भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका" पर अपने दृष्टिकोण को शामिल किया और साझा किया।

12 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में ओमिडयार नेटवर्क द्वारा एवं ओमिडयार नेटवर्क द्वारा आयोजित "भारत में चीनी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र - नवाचार, प्रतियोगिता और शासन" विषय पर एक चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

3 अगस्त, 2019 को पटना में अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र द्वारा आयोजित आईजीसी – आई डी एस के समर स्कूल इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2019 में "द एक्सचेंज रेट रिजीम" पर विचार रखे।

6 जुलाई, 2019 को तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के छात्रों और मिड-कैरियर पेशेवरों के लिए "भारत में विनियमन के लिए राज्य क्षमता निर्माण" पर वेबिनार में भाग लिया ।

13-17 जुलाई 2019 को बेसल, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अर्थशास्त्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित “विश्व स्वास्थ्य कांग्रेस: स्वास्थ्य अर्थशास्त्र में नई ऊंचाइयों” सम्मेलन में “स्वास्थ्य के लिए सामान्य वस्तुओं के वित्तपोषण पर भारत के दृष्टिकोण” में भाग लिया

6-4इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईसीईडी) द्वारा 9 से 10 जून 2019 तक जयपुर में आयोजित आईसीईडी:सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रोड अहेड, पर मंथन सत्र में वक्ता के रूप में भाग लिया

4 - 6 अप्रैल, 2019 को द्वारा अनुसंधान, चेन्नई आयोजित डेटा-संचालित वित्त पर अनुसंधान सम्मेलन में "प्रतिस्पर्धा और बाजार की शक्ति के दुरुपयोग के मुद्दों" पर मुख्य सत्र में चर्चा के रूप में भाग लिया।

3 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा "वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर वुमेन" में वक्ता के रूप में भाग लिया गया।

1 अप्रैल 2019 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित डेटा प्रोटेक्शन पर राउंडटेबल में "डेटा प्रोटेक्शन: ए सेक्टोरल डीप डाइव" सत्र में मध्यस्थ के रूप में भाग लिया।

समितियों एवं कार्य समूहों की सदस्यता

सदस्य (2017-2020), दूरसंचार विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ और लेखा मामलों पर दूरसंचार विभाग।

निदेशक मंडल (1993), सी एम आई ई प्रा. लि.|

निदेशक मंडल (2006), गुजरात राज्य उर्वरक और रसायन लिमिटेड।

निदेशक मंडल (2014), नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

निदेशक मंडल (2017), ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड|

एच.के. अमरनाथ

हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए “विकेंद्रीकरण और लोक वित्त प्रबंधन” और निहित बजटीय सब्सिडी: अवधारणाएं और अनुमान समस्याएं पर व्याख्यान दिए |

पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के लिए "पंचायती राज और भारत में विकेंद्रीकरणरीकरण और लोक वित्त प्रबंधन" पर व्याख्यान दिया |

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अधिकारियों के लिए "विकसित राज्य केंद्र संबंधों" पर व्याख्यान दिया।

5-6 मार्च, 2020 को बजट अध्ययन केंद्र, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन, केरल द्वारा आयोजित "भारत के दक्षिणी राज्यों में सामाजिक क्षेत्र का खर्च और राजकोषीय प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी" में राज्यों के संसाधनों पर राजकोषीय संघवाद में परिवर्तन का प्रभाव - दक्षिणी राज्यों के विशेष संदर्भों पर एक पत्र प्रस्तुत किया

लेखा चक्रबर्ती –

वित्त कनाडा, जीबीए+ के लिए कनाडा सरकार द्वारा बजट की बैठकों के लिए आमंत्रित किया गया जिसमे उनकी मुलाकात अवा यास्केल, एसोसिएट उपवित्त मंत्री, ग्लेन पुरवेस, एलिसन मैकडरमोट और मिशेल कोवेसेविक सहित अन्य टीम के सदस्यों के साथ हुई ।

13 जून 2019 को अर्थशास्त्र विभाग और सार्वजनिक मामलों के स्कूल, कार्लटन विश्वविद्यालय, ओटावा, में "लैंगिक समानता के लिए राजकोषीय नीति: अनुभवजन्य साक्ष्य" विषय पर वक्ता के रूप में आमंत्रित।

जून 2019 को कार्लटन विश्वविद्यालय, ओटावा में छात्रों के लिए अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, उनके मेजर के रूप में इतिहास और कंप्यूटर विज्ञान विभाग, बिजनेस स्टडीज में अर्थशास्त्र के साथ उनके माइनर के रूप में छात्रों के लिए वक्ता के रूप आमंत्रित।

30 मई, 2019 को महाराजा महिला कॉलेज, त्रिवेंद्रम के छात्रों के लिए "लोक वित्त और लोक विकल्प" के लिए व्याख्यान आमंत्रित|

मई 2019 भारतीय आवास केंद्र में 15 वें वित्त आयोग और मानव विकास संस्थान, "विकास और क्षेत्रीय विकास" एवं 'राजकोषीय संघवाद और क्षेत्रीय असमानताएं " पर (चेयरपर्सन: एम गोविंदा राव) सत्र पर आयोजित बैठक में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित|

29 अप्रैल, 2019 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नयी दिल्ली में, शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित लैंगिक समानता के लिए व्याख्यान "सतत विकास लक्ष्यों और नीति प्रभावशीलता" के निमित्त आमंत्रित किया गया।

29 अप्रैल, 2019 को भारत और कनाडा को जोड़ने पर सम्मेलन: इंडो शास्त्री इंस्टीट्यूट, आईआईसी, सतत विकास लक्ष्यों के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण पर जेंडर इक्वलिटी के लिए एसडीजी और पॉलिसी इफ़ेक्टिविटी सत्र में वक्ता के रूप में आमंत्रित|

5 अप्रैल, 2019 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में आर्थिक नीति, कनाडा उच्चायोग की बैठक में भाग लिया।

अन्य प्रासंगिक जानकारी

8 जनवरी 2019 को अर्थशास्त्र विभाग, अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए।

जून-जुलाई 2019 तक कनाडा में शोध करने के लिए इंडो-कनाडा अवार्ड (SICI-MHRD-DFAIT) प्राप्त किया।

सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान, जर्मनी|

सदस्य (2018), फुलब्राइट चयन बोर्ड, यूएस गैर-एसटीईएम फुलब्राइट फैलोशिप|

विजिटिंग प्रोफेसर उप्साला विश्वविद्यालय स्वीडन।

बाहरी परीक्षक, पीएचडी थीसिस, सीईएसपी, जेएनयू, नई दिल्ली और मुंबई विश्वविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटरसैंड, जोहान्सबर्ग|

समीक्षक, एप्लाइड इकोनॉमिक्स, (EPW) स्प्रिंगर जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नीति (टेलर और फ्रांसिस के संदर्भ में)

विजिटिंग प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी।

2019 सलाहकार, पीएचडी विद्वान, दिल्ली विश्वविद्यालय, लिंग समानता के लिए राजकोषीय नीति: शिक्षा क्षेत्र।

लेखों की प्रस्तुति –

अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, 2019 मीटिंग्स, अटलांटा में "लैंगिक समानता (सह-लेखक) के लिए व्यापक आर्थिक प्रभावशीलता" लेख प्रस्तुत किया।

फरवरी 2018 "राजकोषीय नीति के लिए राजकोषीय नीति: अनुभवजन्य साक्ष्य", राजकोषीय मामलों के विभाग, आईएमएफ, में लेख प्रस्तुत किया|

अनुसंधान संबद्धता

जनवरी 2019 फरवरी-अर्थशास्त्र विभाग, अमेरिकी विश्वविद्यालय, में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए।

प्रताप रंजन जेना

नियुक्तियां

लेखा महानियंत्रक , व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय नीति निर्माण", समन्वय और संवर्ग प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की समिति की समितिके सदस्य के " |शामिल हुए रूप में

विश्व बैंक के लिए सहकर्मी समीक्षक

हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही आकलन पर उनके अध्ययन के लिए विश्व बैंक के सहकर्मी समीक्षक के रूप में शामिल हुए। कार्यप्रणाली और डेटा और सूचना की आवश्यकता पर काम करने के लिए आयोजित प्रारंभिक बैठकों में भाग लिया।

लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय "नीति निर्माण, समन्वय और संवर्ग प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की समिति की समिति" के सदस्य के रूप में शामिल हुए|

सदस्य, सार्वजनिक क्षेत्र में नवाचार पर समिति "रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

सदस्य, ज्ञान केंद्र की समिति - सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

आमंत्रित व्याख्यान

07 नवंबर 2019 को "पीएफएम प्रदर्शन मापन ढांचा", सार्वजनिक व्यय प्रबंधन पर आईटीईसी प्रशिक्षण (आई एन जी ए एफ)|

25 फरवरी 2020 जयपुर, "एस डी जी के लिए वित्त पोषण और संस्थागत विकास", "एस डी जी - द कॉन्सेप्ट एंड ऑडिट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट(कैग) 28 जनवरी, 2020, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जिंदल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में " लोक वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शन मापन ढांचा"।

मीता चौधरी

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) द्वारा आयोजित स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ और सतत वित्तपोषण पर फ्लैगशिप कोर्स में "भारत में सार्वजनिक बजट प्रबंधन में सुधार" पर एक व्याख्यान के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (एच एस पी एच), हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में मसूरी। यह कोर्स , लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी में 19 से 23 अगस्त, 2019 के बीच आयोजित किया गया था।

10 जुलाई 2019 को रा लो वि नी सं में लोक वित्त पर एक पाठ्यक्रम में भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्त पोषण पर एक व्याख्यान दिया|

16 दिसंबर, 2019 को रा लो वि नी सं में लोक वित्त पर एक कोर्स में आईसीएएस प्रोबेशनर्स के लिए भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्त पोषण पर एक व्याख्यान दिया|

13 दिसंबर, 2019 को रा लो वि नी सं में सार्वजनिक अर्थशास्त्र पर एक पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्तपोषण पर व्याख्यान दिया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के लिए विशेषज्ञ समूह की सदस्यता|

सच्चिदानंद मुखर्जी

21, 23 और 29 जनवरी 2020, को रा लो वि नी सं पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक वित्त के रूप में भारत में अप्रत्यक्ष करों के संसाधन जुटाने, संरचना और डिजाइन और भारत में वस्तु और सेवा कर की उभरती चुनौतियों पर तीन व्याख्यान दिए।

14 जनवरी 2020 भुवनेश्वर, ओडिशा, सरकार के सरकारी अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीएसटी की ओर एक यात्रा, मधुसूदन दास क्षेत्रीय वित्तीय प्रबंधन अकादमी, वित्त विभाग, बांग्लादेश, भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों पर एक व्याख्यान दिया।

10 दिसंबर 2019, को आई सी ए एस प्रोबेशनर्स के लिए रा लो वि नी सं के लिए लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत में वस्तु और सेवा कर की उभरती चुनौतियों पर एक व्याख्यान दिया।

3-4 दिसंबर, 2019 को भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण V), भारतीय राजस्व सेवा (IRS, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, C & CE) के अधिकारियों को अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के अनुपालन लागत और उभरते हुए चुनौतियों के अनुपालन लागत के निर्धारकों पर पांच व्याख्यान दिए।

9 जुलाई 2019 को भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) प्रोबेशनर्स, रा लो वि नी सं, नई दिल्ली, के लिए लोक वित्त पर पाठ्यक्रम में भारत में वस्तु और सेवा कर की उभरती चुनौतियों पर एक व्याख्यान दिया।

29 मई 2019 को असिस्टेंट कमिश्नर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़, नागपुर, के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2019 में मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी, पब्लिक फ़ाइनेंस, और थ्योरी के सिद्धांतों पर तीन व्याख्यान दिए।

आमंत्रित सेमिनार

17 अप्रैल 2019 को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, नई दिल्ली भारत के लिए कम कार्बन ऊर्जा सुरक्षा पथ की खोज में एशिया-प्रशांत ऊर्जा सहयोग की भूमिका पर एक संगोष्ठी की।

20 दिसंबर 2019 को भारत में स्टेट फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च (रीजनल ऑफिस), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता में जीएसटी मुआवजे के संभावित प्रभाव पर एक संगोष्ठी की।

पत्रिकाओं की समीक्षा

प्रान्जन- जर्नल ऑफ सोशल एंड मैनेजमेंट साइंसेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट), पुणे ,(दक्षिण एशियाई आर्थिक जर्नल (सेज इंडिया)

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट (सेज इंडिया)

एशियन जियोग्राफर (टेलर एंड फ्रांसिस)

सर्वक्षण (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

विकास और परिवर्तन की समीक्षा (ऋषि भारत)

पर्यावरण अर्थशास्त्र और नीति के जर्नल (टेलर और फ्रांसिस समूह)

आमंत्रित पैनेलिस्ट

27 सितंबर 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जल सहयोग - 21 वीं सदी की चुनौतियों के अवसर पर भारतीय जल सप्ताह -2019 में "सतत जल संसाधन विकास को सुनिश्चित करने में संघीय सरकार की केंद्रित भूमिका" पर सत्र में चर्चा ।

17 मई 2019 को एसोचैम, होटल ताज महल, नई दिल्ली, और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर का संयुक्त रूप से "राजकोषीय नीति रोडमैप पर राष्ट्रीय सम्मेलन"।

रेणुका साने

18 2019 मार्च 18 मार्च 2019 को प्रौद्योगिकी नीति टीम, एनएमआईएमएस द्वारा आयोजित एक आईसीटी नियामक के लिए विनियामक प्रथाओं और आर्थिक विश्लेषण पर कार्यशाला में "उपभोक्ता संरक्षण के अर्थशास्त्र" पर विचार रखे।

23 मार्च 2019 को एक संकाय विकास कार्यक्रम, एनएमआईएमएस विश्वविद्यालय के लिए "अंडरस्टैंडिंग पेंशन्स एंड इंश्योरेंस" पर विचार प्रस्तुत किए|

27 मार्च 2019 को आईबीसी पर सीआईआई प्रशिक्षण कार्यशाला में "भारत में व्यक्तिगत दिवालिया कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना" पर व्याख्यान दिया।

12 मार्च 2019 को सीएफए संस्थान में `भारत में पेंशन प्रणाली 'पर बातचीत की|

18 मई 2019 को इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित "कौन उपभोक्ता को बचाता है: भारतीय वित्त का मामला" पर एक वेबिनार प्रस्तुत किया।

7 जून 2019 को डेटा गवर्नेंस नेटवर्क (ऋषभ बेली के साथ) के तहत आईडीएफसी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कार्यशाला में एक पेपर, "डेटा सुरक्षा में डेटा फ़िड्यूशियर्स" प्रस्तुत किया गया|

5 सितंबर, 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, मुंबई द्वारा आयोजित रिटायरमेंट बेनेफिट्स (16 CIRB) में 16 वें सेमिनार में भारत में पेंशन प्रणाली पर बात की।

8 जनवरी 2020 को सीएफए इंस्टीट्यूट, मुंबई द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में `एन्युइटीज मार्केट्स इन इंडिया 'पर विचार रखे।

9 जनवरी 2020 को आईआईसीए द्वारा आयोजित फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स की कार्यशाला में 'राज्य और सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत की भूमिका' पर व्याख्यान दिया।

9 जनवरी, 2020 को आईआईसीए द्वारा आयोजित भारतीय नियामकों के फोरम की कार्यशाला में `विनियमन में लागत लाभ विश्लेषण 'पर व्याख्यान दिया।

28 जनवरी 2020 को रा लो वि नी सं में भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में `बाजार की विफलता' पर व्याख्यान दिया।

6 मार्च 2020 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित "एमएसएमई और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड" विषय पर सेमिनार में एक वक्ता के रूप में आमन्त्रित।

फिनटेक पर संचालन समिति के लिए अनुसंधान सचिवालय की सदस्य | 2 सितम्बर 2010 को वित्त मंत्रालय ने `फ़िनटेक पर संचालन समिति की रिपोर्ट' जारी की |

संगोष्ठी / सेमिनार

4 सितंबर 2019 को डेटा गवर्नेंस नेटवर्क रिसर्च वर्कशॉप का आयोजन किया गया|

'डेटा प्रोटेक्शन' पर स्मृति पारशेरा और फ़ैज़ा रहमान के साथ एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। गोलमेज सम्मलेन का आयोजन रा लो वि नी सं द्वारा सी जी ए पी के सहयोग से किया गया ।

10-11 अक्टूबर 2019 को शिमला में ऋषभ बेली, फ़ैज़ा रहमान और स्मृति परशेरा के साथ संयुक्त रूप से "डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नीतिगत मुद्दों की खोज" पर एक कार्यशाला आयोजित की।

एपीयू और अजय शाह के साथ "रिपब्लिक को मजबूत बनाना" सम्मेलन रा लो वि नी सं में आयोजित किया

सदस्य

इन्सॉल्वेंसी और दिवालियापन से निपटने के लिए व्यक्तियों के संबंध में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए रणनीति और दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए काम करने के लिए इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप के लिए नामित|

पेंशन सलाहकार समिति के सदस्य, पी एफ आर डी ए

पैनलिस्ट

11 मई 2019 को रांची में ज्यूडिशियल एकेडमी में "लॉ एंड इनकॉल्वेंसी ऑफ इनसॉल्वेंसी" पर आई बी बी आई सम्मेलन में "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में पैनलिस्ट|

5 सितम्बर 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, मुंबई द्वारा आयोजित रिटायरमेंट बेनिफिट्स में वर्तमान मुद्दों पर 16वें सेमिनार में भारत में वार्षिकी बाजारों पर सत्र में पैनलिस्ट

२६ से २९ फरवरी 2020 के दौरान मुंबई में वित्तीय क्षेत्र में CAFRAL इवेंट' CAFRAL एंड वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेट इंटरवेंशन में क्रेडिट आवंटन और फर्म प्रदर्शन पर सत्र में पैनलिस्ट

रुद्राणी भट्टाचार्य

16 दिसंबर, 2019 विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए 'सार्वजनिक अर्थशास्त्र' में 13वीं रिफ्रेशर कोर्स में खाद्य मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर व्याख्यान दिया

19 दिसंबर, 2020 को अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत में खाद्य मुद्रास्फीति पर व्याख्यान: मौद्रिक और संरचनात्मक नीतियों की भूमिका पर व्याख्यान दिया

28 जनवरी, 2020 को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौद्रिक नीति प्रसारण पर व्याख्यान दिया

6 दिसंबर 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नई दिल्ली में एक सेमिनार में विषय 'क्या मौद्रिक नीति खाद्य मुद्रास्फीति में स्थिरता ला सकती है? उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साक्ष्य' पर व्याख्यान प्रस्तुत किया|

16 नवंबर, 2019 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में एनसीएईआर की मध्य-वर्ष आर्थिक समीक्षा में भारत की तिमाही आर्थिक वृद्धि के वर्तमान स्तिथि और भविष्य के पूर्वानुमान पर व्याख्यान दिया |

13 मार्च 2020 को व्यापार अर्थशास्त्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैंपस और टीचिंग लर्निंग सेंटर (पीएमएमएनएमटीटी के तहत), रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा आयोजित मैक्रोइकॉनॉमिक सिद्धांत और नीति में उन्नत विषय 'संकाय विकास कार्यक्रम में मैक्रोइकॉनॉमिक मॉडल' में अनुभवजन्य मुद्दों पर व्याख्यान दिया |

22 नवंबर, 2019 को इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा मद्रास क्रिश्चियन विश्वविद्यालय, चेन्नई में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस 'ऑन ग्रोथ एंड स्टैबिलिटी' पर बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए व्याख्यान दिया |

13 जनवरी 2020 को ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित वाईसरीगल हॉल, क्लैरिजेस होटल, नई दिल्ली में चौथा 'इंडिया थिंक टैंक फ़ोरम में आर्थिक विकास और विकास के रीथिंकिंग मॉडल' में चर्चा की |

5 फरवरी 2020 को नई दिल्ली के इम्पीरियल होटल में रियो टिंटो द्वारा आयोजित क्लोज ग्रुप पैनल डिस्कशन पर भारत के दीर्घकालिक विकास अनुमानों पर चर्चा में प्रस्तुति |

8-12 जुलाई, 2019 को भारतीय आर्थिक सेवा 2019 बैच के अधिकारियों, के लिए लोक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया |

अन्य सूचनाएं

आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कार्यालय के अधीन डब्ल्यूपीआई (2011-12) की वर्तमान श्रृंखला के पुनरीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक और वैचारिक मुद्दों पर उपसमूह के सदस्य के रूप में नियुक्त।

निम्नलिखित पत्रिकाओं के लिए आमंत्रित समीक्षक के रूप में समीक्षात्मक पत्र: आरबीआई समसामयिक पेपर, आर्थिक मॉडलिंग, मात्रात्मक अर्थशास्त्र के जर्नल,

आईआईएमबी प्रबंधन की समीक्षा, भारतीय विकास और विकास की समीक्षा, समष्टि अर्थशास्त्र और उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में वित्त

"अवसर और विकास में चुनौतियां," सिमंती बंदोपाध्याय और मौसमी दत्ता (सम्पादित), स्प्रिंगर, 2019 नामक पुस्तक के लिए एक आमंत्रित समीक्षक के रूप में कुछ अध्यायों की समीक्षा की

सुकन्या बोस

12 अप्रैल, 2019, रा लो वि नी सं, दिल्ली में "आरटीई के लिए संसाधन की आवश्यकता: आगे का रास्ता" (प्रियंता घोष के साथ) सेमिनार में रिपोर्ट की प्रस्तुति |

सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली के परामर्श पर 21 जून 2019 को ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा , "कुशल रिसोर्सिंग और प्रभावी शासन" में पैनलिस्ट |

22 अगस्त 2019, को एसटीसी बिल्डिंग, नई दिल्ली में, "शिक्षा के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय आवश्यकता: भारत के 15 वें वित्त आयोग को प्रस्तुत एक नोट" में वित्त आयोग के सदस्यों के साथ चर्चा की |

23 अगस्त 2019 को "क्या भारत पाँच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है?'' विषय पर वित्त और निवेश प्रकोष्ठ, अर्थशास्त्र विभाग आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष व्याख्यान में पैनलिस्ट।

21 सितंबर 2019, को शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा आयोजित कार्यशाला में "शिक्षा बजट के रुझान, अंतराल और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मुद्दों: लिंग और इक्विटी लेंस के साथ बजट का विश्लेषण" में शामिल।

11 दिसंबर, 2019, को 10 वीं अंतर्राष्ट्रीय सीईएसआई सम्मेलन, जेएनयू में पेपर प्रजेंटेशन किया "भारत में सरकारी से निजी स्कूलों में अंतरण: एक वैचारिक सोच की ओर" सुकन्या बोस और अरविंद सरदाना।

18 दिसंबर, 2019 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आरटीई फोरम और सीबीजीए द्वारा एनईपी लोक प्रावधान के चश्मे से प्रायोजित परामर्श में "ड्राफ्ट एनईपी और इसके वित्त के लिए प्रश्न", के अंतर्गत प्रस्तुति।

17 जनवरी 2020 को सीबीजीए द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित "द बजट ट्रेल्स: जिला स्तर पर धन प्रवाह में सुधार और विकास योजनाओं में उपयोग के लिए राजकोषीय प्रशासनिक सुधार" में पैनलिस्ट।

13 फरवरी 2020, पश्चिम बंगाल के कल्याणी विश्वविद्यालय के व्यापार, निवेश और वित्त, राष्ट्रीय सम्मेलन, में पत्र प्रस्तुति "भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र: हाइमन मिंस्की के लेंस का उपयोग करते हुए कुछ प्रतिबिंब"।

संगोष्ठी का आयोजन

12 अप्रैल, 2019 को रा लो वि नी सं, दिल्ली में "आरटीई के लिए संसाधन की आवश्यकता: आगे का रास्ता" शीर्षक से एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

रा लो वि नी सं में व्याख्यान

12 जुलाई, 2019 को 'स्कूल शिक्षा और नेशनल एजुकेशन पालिसी' पर व्याख्यान प्रस्तुति, भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी (प्रशिक्षु) के लिए।

13 दिसंबर 2019 को विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए तेरहवाँ रा लो वि नी सं रिफ्रेशर कोर्स के लिए "प्राथमिक शिक्षा और संसाधन प्रश्न", में व्याख्यान की प्रस्तुति|

16 दिसंबर, 2019 को भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए "प्राथमिक शिक्षा और संसाधन का प्रश्न" पर व्याख्यान।

29 जनवरी, 2020 को 'शिक्षा पर सार्वजनिक संसाधन: संस्थानों की भूमिका विषय पर व्याख्यान, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए

मई 2019 को फिनिश स्कूल प्रणाली के प्रशासन, शासन और वित्त को समझने पर हेलसिंकी विश्वविद्यालय और युवास्कुले विश्वविद्यालय, फिनलैंड में संकाय के साथ बातचीत

राष्ट्रीय आरटीई फोरम की 10 वीं स्टॉकटेकिंग रिपोर्ट में योगदान दिया

केंद्र सरकार के बजट पूर्व परामर्श के लिए शिक्षा बजट पर प्रस्तुत नोट।

मनीष गुप्ता

20 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के होटल ओबेरॉय में राज्य बजट 2019-20 का विश्लेषण। राज्य के वित्त में मुद्दों पर आधे दिन के सेमिनार का आयोजन

20 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के होटल ओबेरॉय में रा लो वि नी सं द्वारा आयोजित आधे दिन के सेमिनार में राज्य बजट 2019-20 का विश्लेषण राज्य वित्त में मुद्दों पर रा लो वि नी सं अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किया|

27-28 अगस्त 2019 के दौरान केरल के कोच्चि में रा लो वि नी सं द्वारा आयोजित संघवाद पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में चर्चा में उपस्थिति|

7-8 सितंबर, 2019 के दौरान BRAC सेंटर, ढाका, बांग्लादेश में एशिया नेटवर्क फॉर इकोनॉमिक मॉडलिंग (SANEM) द्वारा दक्षिण एशिया में विश्व बैंक समूह द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया में उप-विषयक वित्त और स्थानीय सेवा वितरण पर चौथे दक्षिण एशिया आर्थिक नेटवर्क सम्मेलन में "स्थानीय सरकार के वित्त और सेवा वितरण को सुदृढ़ करना: भारत में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका" को प्रस्तुत किया।

27 जनवरी से 7 फरवरी, 2020 के दौरान रा लो वि नी सं, इथियोपिया के बिशॉफ्टू में मेल्स जेनावी लीडरशिप अकादमी और फोरम ऑफ फेडरेशन द्वारा आयोजित इंटरगवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशंस पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में इंटरगवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशंस से जुड़े मुद्दों पर कई व्याख्यान दिए|

2-6 दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा सेवा अधिकारियों के लिए उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया।

27 जनवरी 2020 को ओ पी. जिंदल विश्वविद्यालय, हरियाणा द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के लिए आयोजित "लोक वित्तीय प्रबंधन" पर 5 दिवसीय प्रमाणपत्रीय कार्यक्रम में "राज्य वित्त आयोगों" पर एक व्याख्यान दिया।

ओ पी जिंदल विश्वविद्यालय, हरियाणा द्वारा 27 जनवरी 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन पर 5 दिवसीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम में "भारत में राजकोषीय संघवाद के बदलते स्वरूप" पर एक व्याख्यान प्रस्तुत।

25 नवंबर 2019 को ओ पी जिंदल विश्वविद्यालय, हरियाणा द्वारा सीएजी अधिकारियों के लिए आयोजित लोक नीति और शासन पर सर्टिफिकेट कार्यक्रम में "राज्य वित्त आयोगों" पर एक व्याख्यान दिया।

12 जुलाई 2019 को संस्थान द्वारा आयोजित इंडियन इकोनॉमिक सर्विस प्रोबेशनर्स के लिए लोक वित्त पर पाठ्यक्रम में "स्थानीय सरकार के वित्त में मुद्दे" पर एक व्याख्यान दिया।

11 जुलाई 2019 को संस्थान द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा परिवीक्षा के लिए आयोजित लोक वित्त पर पाठ्यक्रम में "केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध" पर एक व्याख्यान दिया।

2-6 दिसंबर 2019 के दौरान संस्थान द्वारा भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा सेवा अधिकारियों के लिए आयोजित उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम में 6 दिसंबर 2019 को "ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन लोकल गवर्नेंस फ़ाइनेंस इन इंडिया" विषय पर व्याख्यान दिया।

19 दिसंबर 2019 को संस्थान द्वारा यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए आयोजित 13 वें रिफ्रेशर कोर्स में "स्थानीय सरकार के वित्त में मुद्दे" नामक विषय पर व्याख्यान दिया।

20 दिसंबर 2019 को संस्थान द्वारा उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर लोक वित्त और नीति" में आईसीएएस प्रोबेशनर्स के लिए आयोजित दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में "स्थानीय सरकार के वित्त में मुद्दे" पर एक व्याख्यान दिया।

21 जनवरी 2020 को संस्थान द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित लोक वित्त पाठ्यक्रम में "केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध" पर एक व्याख्यान|

24 जनवरी 2020 को संस्थान द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित लोक वित्त में पाठ्यक्रम में "स्थानीय निकाय वित्त" पर एक व्याख्यान|

13-17 फरवरी 2015 के दौरान वित्त विभाग, बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में रा लो वि नी सं द्वारा आयोजित मधुसूदन दास रीजनल एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भुवनेश्वर में "स्थानीय सरकार की योजना और वित्त: भारतीय अनुभव" विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

जेएनयू , नई दिल्ली में प्रस्तुत एम.फिल शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया।

सताद्रू सिकदर

4 फरवरी, 2020 को इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फ़ाइनेंस में भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा सेवा अधिकारीयों के लिए अकाउंटिंग एंड बजट मॉड्यूल 'के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बजट प्रक्रिया, पी एफ एम् और एम् टी ई एफ में प्रस्तुति दी ।

4 फरवरी, 2020 को इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फ़ाइनेंस में भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा सेवा अधिकारीयों के लिए अकाउंटिंग एंड बजट मॉड्यूल 'के प्रशिक्षण कार्यक्रम में' बजट साइकिल, फॉर्म्युलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ़ बजट' में प्रस्तुति दी।

21 जनवरी, 2020 को भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा सेवा प्रोबेशनर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के लिए लोक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में "उपकर से संबंधित मुद्दे" की प्रस्तुति दी ।

21 जनवरी, 2020 को भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा सेवा प्रोबेशनर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के लिए लोक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में "सार्वजनिक व्यय सरकारी बजट संरचना का वर्गीकरण" में प्रस्तुति।

20 दिसंबर, 2019 को भारत सरकार के सिविल अकाउंट सर्विसेज प्रोबेशनर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के लिए लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'सरकारी बजट संरचना और अभ्यास' के कार्यक्रम में शामिल

8-12 जुलाई, 2019 को भारतीय आर्थिक सेवा प्रोबेशनर्स, के लिए " लोक वित्त " के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नकद अंतरण : ऐतिहासिक विचार और नीतिगत अनुभव" की प्रस्तुति

राधिका पाण्डेय

28 जनवरी, 2020 को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर एक व्याख्यान दिया।

15 जनवरी, 2020 को भुवनेश्वर में रा लो वि नी सं और आईपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के सरकारी अधिकारियों के लिए भारत में `वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर एक व्याख्यान दिया।

18 दिसंबर, 2019 को `सार्वजनिक मुद्दों और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर आईसीएएस प्रोबेशनर्स के लिए दो-सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में` पूंजी नियंत्रण 'पर एक व्याख्यान दिया।

12 दिसंबर, 2019 को `वित्तीय मुद्दों और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर आईसीएएस प्रोबेशनर्स के लिए दो-सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में` भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर एक व्याख्यान दिया।

17 दिसंबर, 2019 को रा लो वि नी सं द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स में `भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर एक व्याख्यान 'दिया

समितियों की सदस्यता

30 अप्रैल, 2019 को एम् सी ए -21 डेटाबेस के व्यापक उपयोग के लिए क्षेत्रों / मुद्दों की पहचान करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का सदस्य नियुक्त किया गया

दिनेश कुमार नायक

19 दिसंबर 2019 को रा लो वि नी सं, नई दिल्ली में भारतीय सिविल लेखा सेवा प्रोबेशनर्स के लिए आयोजित " लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दे और चुनौतियां" प्रशिक्षण कार्यक्रम में "वित्तीय वैश्वीकरण और शासन-विधि का योगदान" विषय पर विचार प्रदान किए।

सदस्यता

सदस्य, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिसर्च एसोसिएशन (इंडिया)|

सदस्य, इंडियन पोलिटिकल इकॉनमी एसोसिएशन

सदस्य, द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी|

सदस्य, इंडियन सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स

सदस्य, साउथ एशियन नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स

समीक्षक, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनजेमेंट, बंगलुरु, मैनेजमेंट रिव्यु

भावेश हजारिका

अनुसंधान परियोजना

किसानों और निर्यातकों पर कॉफी बोर्ड द्वारा विस्तारित विभिन्न सब्सिडी के प्रभाव का आकलन करना - कॉफी बोर्ड, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित। (एन. आर. भानुमूर्ति के साथ)

"प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के शासन मापदंडों का मूल्यांकन", ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित (एन.आर. भानुमूर्ति के साथ)

परियोजनाओं का समापन

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के तहत रोजगार सृजन का आकलन और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, (एन.आर. भानुमूर्ति के साथ)

जारी परियोजनायें

गर्भवती महिला मजदूरों के बीच बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर सशर्त नकद अंतरण का प्रभाव मध्य प्रदेश से साक्ष्य: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित (एन.आर. भानुमूर्ति के साथ)

दिए गए व्याख्यान

12 दिसंबर, 2019 को रा लो वि नी सं, नई दिल्ली में " लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर भारतीय सिविल लेखा सेवा प्रोबेशनर्स के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में "सार्वजनिक खरीद" पर व्याख्यान दिया

13 मई 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली द्वारा आयोजित "हू वीव्स: द जेंडर क्वेश्चन इन द हैंडलूम इंडस्ट्री" के पैनलिस्ट।

लेख एवं पत्र प्रकाशन

पत्रिका, सेमिनार एवं सम्मेलन पत्र

- "प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी भारत में रोजगार सृजन" शहरी भारत, 39 (2) (जुलाई से दिसंबर, 2019 को जारी) pp.46-63, ISSN 0970-9045, (डी.के. नायक के साथ)।
- "ग्रामीण में अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों में लिंग आधारित आय विषमता: हथकरघा उद्योग में बिना शर्त मात्रा अपघटन पर दृष्टिकोण" यूरेशियन बिजनेस रिव्यू 2020 10.441-473, (स्प्रिंगर)।
- "सामाजिक-सांस्कृतिक प्रासंगिकता के उद्यमी प्रेरणाएं: असम में हथकरघा उद्योग में एक खोजपूर्ण विश्लेषण" एशियन जर्नल ऑफ़ वीमेन स्टडीज़, 25 (3), 317-351 (टेलर एंड फ्रांसिस)। (के. गोस्वामी और के. हांडिक के साथ)।
- सुधार के बाद के समय में अरुणाचल प्रदेश राज्य का वित्त (नायक आदि द्वारा सम्पादित) "इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया: इमर्जिंग रियलिटीज़ (PP. 224-245)। नई दिल्ली: ओम प्रकाशन। आईएसबीएन: 9789388937252. (ए.के. दास के साथ)।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य, कुरुक्षेत्र, 67 (10), 23-28। (एन.आर. भानूमुर्ति के साथ)

तकनीकी रिपोर्ट

"प्रधानमंत्री आवास योजना के शासन मापदंडों का मूल्यांकन", ग्राहक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

किसानों और निर्यातकों के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा विस्तारित विभिन्न सब्सिडी के प्रभाव का आकलन। ग्राहक : कॉफ़ी बोर्ड, भारत सरकार, 2019|

भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत कार्यान्वयन और परिणामों का आकलन, ग्राहक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत रोजगार सृजन का आकलन। ग्राहक, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार।

सेमिनार सम्मेलन, संगोष्ठी/जिनमें भाग लिया

7-8 दिसंबर को आई जेड ए-डीएफआईडी द्वारा काठमांडू में आयोजित लघु पाठ्यक्रम "कार्यक्रम मूल्यांकन" के अंतर्गत "किफायती (पर्याप्त) आवास योजना - पी एम् ए वाई के माध्यम से सतत विकास की दिशा में गरीबों के जीवन को बदलने में भारत के प्रयास" भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम -

5-8 दिसंबर 2019 को श्रम अर्थशास्त्र संस्थान, बॉन, जर्मनी द्वारा आयोजित काठमांडू DFID, नेपाल, IZA शॉर्ट कोर्स ऑन प्रोग्राम इवैलुएशन, के अवसर पर उपस्थिति|

9-12 अप्रैल, 2019 को जेएनयू, में दिल्ली आर स्कूल, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, भू-स्थानिक डेटा और अनुसंधान के कार्यक्रम में उपस्थिति।

सदस्यता

समीक्षक, लघु व्यवसाय और उद्यमिता जर्नल |(टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप)

समीक्षक, मात्रात्मक अर्थशास्त्र |जर्नल (स्प्रिंगर)

रंजन कुमार मोहन्ती

13 जनवरी 2020 को नई दिल्ली के सरकारी लेखा और वित्त संस्थान में "भारत में राजकोषीय-मौद्रिक नीति लिंकेज" और "चयनित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लोक वित्तीय प्रबंधन" पर दो व्याख्यान दिए।

नेशनल पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली में 9-20 दिसंबर, 2019 को भारतीय सिविल लेखा (आईसीएएस) प्रशिक्षण कार्यक्रम में "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं" पर एक व्याख्यान दिया।

2 अगस्त 2019 को एनआईटी राउरकेला, ओडिशा द्वारा आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण को मजबूत बनाने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान पद्धति पर 5 दिनों की क्षमता निर्माण कार्यशाला में "राष्ट्रीय वित्तीय मिशन के तहत लोक वित्तीय प्रबंधन" पर एक व्याख्यान दिया।

15 फरवरी 2020 को जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में "उद्योग 4.0 व्यवसाय और प्रबंधन में वैश्विक परिवर्तन" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पत्र "भारत में ब्याज दर निर्धारित करने में राजकोषीय नीति की भूमिका पर पुनर्विचार: एक एस वी ए आर दृष्टिकोण" प्रस्तुत किया।

8 से 10 जनवरी, 2020 को भारत के मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, तमिलनाडु में आयोजित इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी के 56 वें वार्षिक सम्मेलन में भारत में ब्याज दर के निर्धारण में राजकोषीय नीति की भूमिका पर पुनर्विचार: एक एस वी ए आर दृष्टिकोण नामक एक पत्र प्रस्तुत किया।

11-14 अक्टूबर, 2019 को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर, मिशिगन, यूएसए में स्कूल फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा आयोजित द्वितीय वार्षिक स्थिरता और विकास सम्मेलन (SDC) के दौरान एक पेपर प्रस्तुत किया "स्वास्थ्य परिणामों के सुधार में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय कितना प्रभावी है? भारतीय राज्यों से एक अनुभवजन्य साक्ष्य "

29-30 जुलाई 2019 को भुवनेश्वर, ओडिशा में भारतीय आर्थिक और वित्तीय अध्ययन संघ और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेवियर यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 23 वें द्विवार्षिक सम्मेलन 2019 में "भारत के इको-मैक्रोइकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स: ए डाटा एनवलपमेंट एनालिसिस दृष्टिकोण" की जांच के दौरान एक पेपर प्रस्तुत किया।

6 नवंबर, 2019 को शेरेटन होटल, नई दिल्ली में और 7 नवंबर, 2019 को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली में "इम्पैक्ट इवैल्यूएशन (3 आई ई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल" दिल्ली एविडेंस वीक सम्मेलन में भाग लिया

11 अक्टूबर, 2019 को पर्यावरण और स्थिरता स्कूल, मिशिगन विश्वविद्यालय, एन आर्बर, मिशिगन, यूएसए में "मात्रात्मक विश्लेषण: मेटा-विश्लेषण" पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया।

29 जुलाई - 2 अगस्त 2019 को एनआईटी राउरकेला, ओडिशा में आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण को मजबूत करने के लिए एप्लाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी पर 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में भाग लिया।

6 से 9 जुलाई 2019 के दौरान 5 वीं "समर स्कूल इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स" , में भाग लिया जो कि इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित थी

प्रशिक्षण कार्यक्रम -

9-20 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए लोक अर्थशास्त्र में आयोजित 13 वीं रिफ्रेशर कोर्स के कोर्स समन्वयक

जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ फ़ाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, विज़न: द जर्नल ऑफ़ बिज़नेस पर्सपेक्टिव, जर्नल ऑफ़ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनोमिया इंटरनैज़ेनेल और इंजीनियरिंग में गणित संबंधी समस्याओं के कई पत्रों की समीक्षा की

अमेय सप्रे

संशोधन के चार साल बाद, भारत के राष्ट्रीय लेखा अनुमान के संशोधन पर बहस का पुनर्मूल्यांकन", इंडिया पॉलिसी फोरम, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च (एनसीएईआर, नई दिल्ली, जुलाई 2019) पत्र प्रस्तुत किया

आमंत्रित व्याख्यान

अप्रैल, 2019 को एस एन ए और सकल घरेलू उत्पाद अनुमान के मुद्दे, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी

जून, 2019 को विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में मुद्दे, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी

दिसंबर, 2019 को पब्लिक इकोनॉमिक्स में 13 वां रिफ्रेशर कोर्स में यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स का आधार (रा लो वि नी सं)

दिसंबर, 2019 को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए "छाया अर्थव्यवस्था का अनुमान" सार्वजनिक अर्थशास्त्र में 13 वां रिफ्रेशर कोर्स (रा लो वि नी सं)

जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए लोक वित्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम का परिचय, (रा लो वि नी सं)|

3 मार्च, 2020 को सकल घरेलू उत्पाद के मुद्दों पर सीएजी - रा लो वि नी सं प्रशिक्षण कार्यक्रम में "जीडीपी का संकलन", विषय पर व्याख्यान दिया

सुरांजलि टन्डन

ब्रिटिश उच्चायोग और चेवेनिंग, मुंबई द्वारा फरवरी 2020 में "ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया" गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की

फरवरी 2020, दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट कराधान नीति, विधान और प्रशासन में वर्तमान विकास पर आईएमएफ के एस ए आर टी टी एसी सम्मेलन में पैनलिस्ट

जनवरी 2020 को पास्केल पिस्टन, लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित बैठक "अंतर्राष्ट्रीय कराधान और डिजिटल अर्थव्यवस्था सुधार के लिए वैश्विक चुनौतियां" विषय पर चर्चा में भाग लिया

दिसंबर 2019, कार्नेगी इंडिया, बैंगलोर द्वारा आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में वक्ता

नवंबर 2019 में ग्रन्थम रिसर्च इंस्टीट्यूट लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स और रा लो वि नी सं के सहयोग से "न्यायोचित संक्रमण का वित्तपोषण " पर सम्मेलन का आयोजन किया

अक्टूबर 2019 में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नीतिगत मुद्दों की खोज में शीर्षक बैठक में "डिजिटलाइजेशन से उत्पन्न कर चुनौतियां" पर पत्र प्रस्तुत किया

अक्टूबर 2019 को ग्लोबल टैक्स सिंपोजियम, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स , में "भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद" पर पत्र की प्रस्तुति

अगस्त 2019 में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन, बैंगलोर द्वारा आयोजित सम्मेलन में "डिजिटलाइजेशन से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियाँ" प्रस्तुत की गईं|

जुलाई 2019 को क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी, लंदन में आयोजित बीईपीएस मॉनिटरिंग ग्रुप और आईसीटीडी द्वारा "डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान" पर कार्यशाला में एक सत्र का आयोजन और अध्यक्षता की।

अप्रैल 2019 को विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, द्वारा आयोजित डिजिटल इकोनॉमी के राउंड टेबल टैक्सेशन के पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया

हरि नायडू

नई दिल्ली, (2019-2020) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान में भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा , भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा और भारतीय सिविल लेखा सेवा परिवीक्षाधीन "सार्वभौम ऋण बाजार नीति " विषय पर व्याख्यान दिया

11 सितंबर, 2019 को स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप , अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली में "विमुद्रीकरण : प्रमुख मुद्दे एवं चिंताएं" विषय पर व्याख्यान दिया।

10 अक्टूबर, 2019 को स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में "वस्तु एवं सेवा कर" विषय पर व्याख्यान दिया।

19-21 नवम्बर, 2019 को 113 वें राष्ट्रीय कर संघ सम्मेलन, ताम्पा, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में "भारतीय राज्यों की कर राजस्व क्षमता: स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का मामला" विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया

8 से 10 जनवरी 2020 तक मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै द्वारा आयोजित "भारतीय अर्थमितीय सोसायटी का 56 वां वार्षिक सम्मेलन" में "भारतीय राज्यों की कर राजस्व क्षमता: स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का मामला" विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया

5 से 7 जनवरी 2020 तक "द इंडियन इकॉनोमेट्रिक सोसाइटी" के सहयोग से अर्थशास्त्र विभाग, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय द्वारा "टाइम सीरीज़ अर्थमिति पर उन्नत कार्यशाला" का आयोजन में भाग लिया

सदस्य, नेशनल टैक्स एसोसिएशन, यूएसए

अमनदीप कौर

संस्थान के परिसर में 9-20, 2019 को आयोजित लोक वित्त और नीति में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर आईसीएएस प्रशिक्षुओं के लिए दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में "पावर डेट एंड फेडरलिज्म" पर 20 दिसंबर 2019 को व्याख्यान दिया|

20 - 31 जनवरी, 2020 को संस्थान के परिसर में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईएएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित लोक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में "विद्युत क्षेत्र में संसाधन आवंटन: राज्य वित्त पर प्रभाव" पर 30 जनवरी, 2020 को एक व्याख्यान दिया

9 - 20 दिसंबर, 2019 से पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में आईसीएएस (इंडिया सिविल अकाउंट्स सर्विसेज) प्रोबेशनर्स पर "पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में उभरते मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रा लो वि नी सं की आर एंड टी बिल्डिंग में आयोजित किया गया

अनुलंग्नक

अनुलंग्नक– I अध्ययनों की सूची 2017-18

निष्पादित परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (ओं) / रिसर्च टीम
1	"भारत में डिजिटल संचार संवर्धन हेतु ज्ञान भागीदारी के लिए प्रस्तावः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका" -(सितम्बर 2019 अक्टूबर 2019)	दूरसंचार विभाग	पूरा हुआ	अजयशाह, ईला पटनायक , स्मृति परशीरा , रिषभ बेली, फ़ैज़ा रहमान, वरुण सेन बहल
2	उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के निष्पादन लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए समझौता	नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक (सीएजी)	पूरा हुआ	अजय शाह, ईला पटनायक , अमय सप्रे, शुभो रॉय, हरलीन कौर, महिमा गुप्ता, मनप्रीत सिंह, प्रमोद सिन्हा, रचना शर्मा, समीर पेठे, शेफाली मल्होत्रा, सुप्रिया कृष्णन।
3	ट्राई - एन आई पी एफ पी रिसर्च प्रोग्राम का कार्यान्वयन	भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)	पूरा हुआ	अजय शाह, स्मृति परशीरा , मयंक मिश्रा, फ़ैज़ा रहमान, सुदीप्तो बनर्जी, देवेंद्र दामले, रिषभ बेली, सारंग मोहरिर , आशिम कपूर, रचना शर्मा, सुदीप्तो बनर्जी, विशाल त्रेहान, सृष्टि शर्मा।
4	एमसीए अनुसंधान कार्यक्रम	कारपोरेट मामलों के मंत्रालय	पूरा हुआ	ईला पटनायक, प्रतीक दत्त, सुदीप्तो बनर्जी, कार्तिक सुरेश, मेधा राजू, शुभ रॉय रॉय, राधिका पांडे
5	प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण शासन (PMAY-G) के अभिशासन मापदंडों का मूल्यांकन	विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ग्राम्य।	पूरा हुआ	एन.आर. भानुमूर्ति , एच् के अमरनाथ , भाबेश हज़ारिका, कृष्ण शर्मा, कनिका गुप्ता, तन्वी ब्राम्हे
6	वर्ष 2016-17 राज्य एफआर बी एम अधिनियम का सिक्किम सरकार द्वारा किये गए अनुपालन की समीक्षा	सिक्किम सरकार	पूरा हुआ	प्रताप रंजन जेना

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (औं) / रिसर्च टीम
7	सिक्किम के लिए मध्यम अवधी राजकोषीय योजना 2020 -21 से 2022-23	तक सिक्किम सरकार	पूरा हुआ	प्रताप रंजन जेना
8	"कैपिटल मार्केट्स के कराधान" पर अध्ययन	वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामले विभाग	पूरा हुआ	आर कविता राव, सुरांजलि टंडन, डी पी सेनगुप्ता
9	"मैक्रो-फिस्कल लिंकेजेज़ पर अध्ययन "	15 वीं वित्त आयोग	पूरा हुआ	एनआर भानुमूर्ति, सुकन्या बोस, साक्षी सतीजा
10	राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों का अवलोकन	15वाँ वित्त आयोग	पूरा हुआ	पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता
11	भारत में वस्तु और सेवा (जी एस टी) कर लागू के राजकोषीय आशय	15वाँ वित्त आयोग	पूरा हुआ	सच्चिदानंद मुखर्जी, आर कविता राव
12	स्वास्थ्य और उसके वित्तपोषण पर शोध एवं नीतियों में सुधार पर एक अध्ययन	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	पूरा हुआ	अजय शाह, ईला पटनायक, शुभो रॉय, शेफाली मल्होत्रा, हरलीन कौर, रचना शर्मा, संहिता सपटणेकर , महिमा गुप्ता, मनप्रीत सिंह, समीर पेठे, सुप्रिया कृष्णन, मधुर मेहता।, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मौमिता दास।
13	एक प्रभावी राष्ट्रीय काउंसिल फॉर वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण (" NCVET ") की स्थापना के लिए संगठन डिजाइन और आंतरिक प्रक्रियाएं	ओमिड्यार नेटवर्क सेवा	पूरा हुआ	अजय शाह, ईला पटनायक, प्रतीक दत्ता, सारंग मोहरिर, सुदीप्तो बनर्जी, कार्तिक सुरेश, मेधा राजू
14	भारतीय राज्यों के लिए कर प्रयास और कर संग्रहण दक्षता मापने सम्बन्धी शोध (जून 2017- जून 2019)	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	पूरा हुआ	हरि नायडू
15	भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 71 वें दौर के सर्वेक्षण से स्वास्थ्य पर घरेलू खर्च का विश्लेषण	विश्व स्वास्थ्य संगठन	पूरा हुआ	मिता चौधरी, जय देव दुबे, बिदिशा मंडल
16	"किसानों और निर्यातकों पर कॉफी बोर्ड द्वारा प्रदत्त विभिन्न सब्सिडियों का किसानों और निर्यातकों पर प्रभाव का आकलन"	कॉफी बोर्ड	पूरा हुआ	एन.आर. भानुमूर्ति , भाबेश हज़ारिका, प्रिया केशरी

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (औं) / रिसर्च टीम
17	भारत में उभरती प्रौद्योगिकियों के नियमन पर एक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए एँफ़ एन एँफ़ के साथ समझौता ज्ञापन	फ्रेडरिक नौमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम	पूरा हुआ	रेणुका साने, रिषभ बेली, स्मृति पारशीरा , फ़ैज़ा रहमान
18	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस - डिजिटल आइडेंटिटी रिसर्च इनिशिएटिव (डीआईआरआई)	इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नस	पूरा हुआ	रेणुका साने, स्मृति पारशेरा
19	त्रिपुरा सरकार के लिए अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ जीएसडीपी अनुपात का एक तुलनात्मक कर अध्ययन (नवंबर 2019)	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	पूरा हुआ	सच्चिदानंद मुखर्जी, सताद्रू सिकदर, शिवानी, विभा कुमारी
20	अनुसंधान परियोजना (मैक्रोइकॉनॉमिक्स): वित्तीय संरचना, संस्थागत गुणवत्ता और मौद्रिक नीति संचरण: एक मेटा-विश्लेषण	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	पूरा हुआ	श्रुति त्रिपाठी, सबर्णी चौधरी, सहाना रॉय चौधरी
21	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नीति का संशोधित मसौदा	रा लो वि नी सं -डीईए, वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन राय
22	मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के साथ समीक्षा बैठक के लिए रिपोर्ट 19 वीं जून 2019	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन राय
23	भुगतान एवं निबटारा प्रणाली ड्राफ्ट विधेयक और भारतीय रिजर्व बैंक के असंतोष टिप्पणी पर उत्तर	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन राय
24	स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) ग्लोबल के साथ संप्रभु वार्षिक क्रेडिट की समीक्षा बैठक के लिए रिपोर्ट	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन रॉय
25	बैंक पुनर्पूंजीकरण का बैंकों की वैधानिक तरलता अनुपात, अग्रिम और उनके द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त स्तर-1 पूंजी पर प्रभाव का अध्ययन	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन रॉय
26	घरेलू अवसंरचना निवेश रिपोर्ट	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन रॉय

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (ओं) / रिसर्च टीम
27	ऋण और वित्तीय बाजार अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर नोट	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन राय
28	इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशिओं (आईसीओआर) की पुनः गणना	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन राय
29	बांड बाजार को मजबूत बनाने पर नोट	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन राय
30	शीर्षक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में प्याज की कीमतों की भूमिका पर नोट	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन राय
31	वित्तीय विकास सूचकांक रैंकिंग में सुधार के लिए रोडमैप	रा लो वि नी सं -डीईए वित्त मंत्रालय	पूरा हुआ	रथिन राय

चल रही परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (ओं) /रिसर्च टीम
1	सशर्त नकद अंतरण का गर्भवती महिलाओं मजदूरों के बीच बेहतर स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर प्रभाव : मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना मध्य प्रदेश से साक्ष्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सरकार मध्य प्रदेश	जारी	भाबेश हज़ारिका, रंजन मोहंती, दिनेश नायक, एनआर भानुमूर्ति , कनिका गुप्ता, कनिका कुमार, अंशु शुक्ला
2	संस्थान में संकाय के लिए लोक वित्त जानकारी डाटाबैंक अद्यतन करना	रा लो वि नी सं	जारी	एच अमरनाथ, दीवान चंद, रोहित दत्ता
3	ऑनलाइन डाटाबेस निर्माण और शुरू करना	रा लो वि नी सं	जारी	एच अमरनाथ, रोहित दत्ता
4	नियंत्रक और महालेखा परीक्षकः अनुसंधान कार्यक्रम	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	जारी	ईला पटनायक, मेधा राजू, हरलीन कौर, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, रचना शर्मा, राधिका पांडे

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (औं) /रिसर्च टीम
5	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने हाल ही में एक परियोजना शुरू की है, जो भारत में 'विशेष क्षेत्रों में गंभीर मुद्दों' का अध्ययन करने के लिए है।	सामाजिक विज्ञान अनुसंधान भारतीय परिषद (आईसीएसएसआर)	जारी	ईला पटनायक, आशिम कपूर, रचना शर्मा, समीर पेठे, शेफाली मल्होत्रा, चिराग आनंद
6	त्रिपुरा सरकार की ऋण स्थिरता पर एक अध्ययन	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	मनीष गुप्ता, स्मृति मेहरा
7	त्रिपुरा राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति पर एक अध्ययन	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	मनीष गुप्ता, समप्रीत कौर
8	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय पहलू: :प्रभाव और भविष्य के लिए सीख	नीति आयोग(ट्रांस्फोर्मिंग भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान)	जारी	मिता चौधरी, रंजन कुमार मोहंती
9	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रोजगार सृजन के आकलन पर अध्ययन	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	जारी	एन आर भानुमूर्ति , दिनेश कुमार नायक, अशोक भाकर, भाबेश हज़ारिका, कनिका गुप्ता, तन्वी ब्रह्मे
10	वर्ष 2017-18 राज्य एफआर बी एम अधिनियम का सिक्किम सरकार द्वारा किये गए अनुपालन की समीक्षा	सिक्किम सरकार	जारी	प्रताप रंजन जेना
11	वर्ष 2018-19 राज्य एफआर बी एम अधिनियम का सिक्किम सरकार द्वारा किये गए अनुपालन की समीक्षा	सिक्किम सरकार	जारी	प्रताप रंजन जेना
12	गृह मंत्रालय- रा लो वि नी सं रिसर्च प्रोग्राम	गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार	जारी	रथिन राय, मिता चौधरी, अमय सप्रे, रत्नेश
13	राजस्व विभाग के लिए पारदर्शिता ऑडिट	वित्त मंत्रालय भारत सरकार	जारी	सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला, विभा कुमारी
14	डी आई पी ए ऍम में विनिवेश की प्रक्रिया पर रिसर्च इनपुट	डी आई पी ए ऍम	जारी	रेणुका साने, सुदीप्तो बनर्जी, कार्तिक सुरेश, सृष्टि शर्मा, सारंग मोहरिर

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (औं) /रिसर्च टीम
15	"भूमि बाजार को बेहतर बनाने हेतु"	ओमिड्यार नेटवर्क	जारी	ईला पटनायक, देवेंद्र दामले, विशाल त्रेहन, तुषार आनंद, विराज जोशी
16	न्याय चुनौती के लिए डेटा	वयम फोरम फॉर सिटीजनशिप	जारी	ईला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद, विराज जोशी, विशाल त्रेहान, सिद्धार्थ श्रीवास्तव
17	भारत में वित्तीय बाजारों का कराधान	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	आर कविता राव, सुरंजलि टंडन, डीपी सेनगुप्ता, आदित्य रेड्डी, अक्षय गर्ग
18	कर नीति और आकलन का मूल्यांकन	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	आर कविता राव
19	लैंगिक समानता और लिंग बजट का शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए राजकोषीय खर्च पर प्रभाव एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक अध्ययन - (सितंबर 2017 - अगस्त 2020)	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	लेखा चक्रवर्ती
20	बच्चों के लिए लोक वित्त: राज्य स्तरीय विश्लेषण - गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक - (मई 2019 - जनवरी 2022)	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, जेनेट फरीदा याकूब, अनिंदिता घोष
21	अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय नीति। अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी (फरवरी 2019 - अगस्त 2021) के साथ अनुसंधान सहयोग	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	लेखा चक्रवर्ती, मारिया फ्लोरो (सलाहकार: अमेरिकी विश्वविद्यालय)
22	भारत में स्वास्थ्य व्यय का लोक वित्तपोषण: आगे की राह	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	मिता चौधरी, रंजन कुमार मोहंती, श्रुति त्रिपाठी, प्रीतम दत्ता जम्मू, जय देव दुबे, बिदिशा मंडल, सुनेत्रा घटक, राशि मित्तल, रजनी पांडे
23	इथियोपिया में वित्तीय संघवाद (जून 2019 - जून 2021 दो वर्ष लगभग)	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	रथिन राय, लेखा चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (औं) /रिसर्च टीम
24	अंतर सरकारी राजकोषीय संबंध प्रमाणन कार्यक्रम (सहयोगी संस्थाएं : रा लो वि नी सं, भारत, फोरम ऑफ़ फेडरेशन, कनाडा और मेलेस ज़ेनावी नेतृत्व अकादमी, इथियोपिया)	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	रथिन रॉय, लेखा चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता
25	भारत में उभरती प्रौद्योगिकियों के नियमन पर एक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए एंफ़ एन एंफ़ के साथ समझौता ज्ञापन	फ्रेडरिक नौमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम	जारी	रेणुका साने, ऋषभ बेली, स्मृती पार्शीरा ओंमकार, फैजा रहमान
26	-ओमिड्यार - आईडीएफसी फाउंडेशन - : निम्नांकित के लिए डेटा गवर्नेंस नेटवर्क: 1) गोपनीयता नीतियों की समझ को क्या संचालित करता है ;2) डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के लिए एजेंसी डिजाइन ;3) वर्तमान निगरानी संबंधित कानून ;4) विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के उपयोग के आसपास गोपनीयता के मुद्दों का अध्ययन करना (ड्रोन, सीसीटीवी, चेहरे की पहचान, सेल टॉवर ट्रैकिंग, एन्क्रिप्शन उपकरण, आदि)	आईडीएफसी फाउंडेशन और ओमिड्यार नेटवर्क	जारी	रेणुका साने, स्मृती पार्शीरा, रिषभ बेली, फ़ैज़ा रहमान
27	भारत के लिए उपभोक्ता वित्त में शिकायत निवारण प्रबंधन ढांचे की ओर	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	रेणुका साने, विमल बालासुब्रमण्यम, मिथिला एक सारा, कुषाण बिस्वास, सुरेश कुमार, उत्कर्ष
28	राज्य जैव विविधता रणनीति का विकास और कार्य योजनाओं (एस बी सैपस) को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए संसाधन संग्रहण रणनीति,	यूएनडीपी	जारी	रीता पांडे, गरिमा जसूजा , अनुजा मल्होत्रा, प्रिया यादव
29	भारत सरकार-यूएनडीपी की "सुरक्षित हिमालय परियोजना" के तहत राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना और विकास संसाधन संग्रहण रणनीतियाँ (एस बी सैपस) सिक्किम में लागू करने के लिए	यूएनडीपी	जारी	रीता पांडे, गरिमा जसूजा , अनुजा मल्होत्रा, प्रिया यादव

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (औं) /रिसर्च टीम
30	भारत में त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद विकास की स्तिथि का आंकलन (एनसीएईआर के साथ सहयोग)	(एनसीएईआर के साथ सहयोग)	जारी	रुद्राणी भट्टाचार्य, सुदीप्तो मंडल (एनसीएईआर), बोर्नेलि भंडारी (एनसीएईआर)
31	सी पी आई मुद्रास्फीति का लघु अवधि पूर्वानुमान	रा लो वि नी सं	जारी	रुद्राणीi भट्टाचार्य, मृगाक्षी कपूर (बिट्स पिलानी)
32	क्या ई-एन ए एम् भारत में फलों और सब्जियों के बाजार को एकीकृत करने में सफल है : - एक वेक्टर त्रुटि संशोधन मॉडल से साक्ष्य	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	रुद्राणी भट्टाचार्य, सब्रानी चौधरी
33	क्या भारतीय मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को अवलम्बित करती है ?	प्रोफेसर पी आर ब्रह्मानंद अनुसंधान अनुदान, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु, 2018-19	जारी	रुद्राणी भट्टाचार्य
34	त्रिपुरा के राज्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए संभव उपायों पर अध्ययन	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	सच्चिदानंद मुखर्जी, शिवानी बडोला, विभा कुमारी
35	सरकारी स्कूलों से छात्रों के बहिर्गमन की विवेचना	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अनुसंधान अनुदान, 2018	जारी	सुकन्या बोस, प्रियंता घोष, मनोहर बोडा, अरविंद सरदाना
36	लिंग संवेदनशील बजट का स्कूल शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन	नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन	जारी	सुकन्या बोस
37	भारत में कर विवादों का विश्लेषण	बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	जारी	सुरांजलि टंडन, आदित्य रेड्डी, अक्षय गर्ग

नयी परियोजनाओं की पहल

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	परियोजना स्थिति	लेखक (ओं) /रिसर्च टीम
1	प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में इक्विटी की लागत पर अध्ययन (ए ए आई हवाई अड्डों और अन्य प्रमुख निजी हवाई अड्डों)	प्रायोजित ए ई आर ए	नई पहल	अजय शाह
2	भारत में चिकित्सा नैतिकता का विनियमन और प्रशासन - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी)	डी एस टी	नई पहल	ईला पटनायक; रेणुका साने
3	उत्तराखंड सरकार के वित्तीय प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए (एन आई पी एफ पी) और पंडित दीन दयाल उपाध्याय केंद्र के बीच सहयोग	उत्तराखंड सरकार	नई पहल	रथिन रॉय
4	जीएसटी के राजस्व प्रभाव का विश्लेषण दिल्ली सरकार एन सी टी के लिए	दिल्ली एन सी टी की सरकार	नई पहल	सच्चिदानंद मुखर्जी
5	वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के कारण छावनी बोर्डों (सीबी) को राजस्व के नुकसान पर अध्ययन।	रक्षा मंत्रालय भारत सरकार	नई पहल	सच्चिदानंद मुखर्जी
6	महाराष्ट्र के राजस्व मैं वृद्धि - जी एस टी राजस्व	महाराष्ट्र सरकार	नई पहल	सच्चिदानंद मुखर्जी
7	भारतीय अर्थव्यवस्था की रियल टाइम व्यापक आर्थिक निगरानी के लिए एक मॉडल (मासिक आधार पर अर्थव्यवस्था की निगरानी)	वित्त मंत्रालय, सरकार। भारत, नई दिल्ली	नई पहल	प्रमोद सिन्हा
8	विश्व बैंक: भारत में घरों पर आपदाओं के प्रभाव का विश्लेषण "	एन आई पी एफ पी	नई पहल	ईला पटनायक।
9	वित्तीय बाजारों में कराधान संरचना पर अध्ययन -	एन आई पी एफ पी	नई पहल	आर कविता राव; सुरांजलि टंडन
10	पर्यावरणीय राजकोषीय अंतरण	संघ केफोरम, ओटावा।	नई पहल	लेखा चक्रवर्ती; अमनदीप कौर

अनुलंग्नक – II रा लो वि नी सं कार्यशील पेपर श्रृंखला

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक
1	भारत के लिए निम्न-कार्बन ऊर्जा सुरक्षा पथ की खोज: एशिया-प्रशांत ऊर्जा सहयोग की भूमिका; (संख्या 259, अप्रैल 2019)	सच्चिदानंद मुखर्जी
2	चौराहे पर भारतीय राजकोषीय संघवाद: कुछ विचार ; (नं। 260, अप्रैल 2019) लेख	लेखा चक्रवर्ती
3	उभरती अर्थव्यवस्था में उप राष्ट्रीय लोक वित्त का अभ्यास: केरल में राजकोषीय लक्ष्यवेधन ; (संख्या 261, अप्रैल 2019)	रुज़ेल श्रेष्ठ; लेखा चक्रवर्ती
4	केंद्रीय बैंक में कितनी इक्विटी पूंजी होनी चाहिए। ?; (नं। 262, अप्रैल 2019)	ईला पटनायक; राधिका पांडे
5	राज्य वित्त आयोग: वे स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने में कितने सफल रहे हैं?; (नं 263, अप्रैल 2019)	मनीष गुप्ता;पिनाकी चक्रवर्ती
6	राजकोषीय नियमों के तहत अस्तित्व : ओडिशा राज्य के लिए राजकोषीय प्रबंधन प्रतिक्रिया और संसाधनों के आवंटन विकल्प; (नं 264, मई 2019)	प्रताप रंजन जेना
7	भारत में 2001-16 के दौरान लोक वित्त और वित्तीय प्रबंधन की अवस्था ; (नं। 265, मई 2019)	सच्चिदानंद मुखर्जी
8	भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का विश्लेषण; (नं। 266, मई 2019)	सुरंजलि टंडन; देवेंद्र दामले
9	भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार; (नं। 267) मई 2019)	राधिका पांडे; ईला पटनायक
10	दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीति चक्रीयता; (नं। 268, मई 2019)	राधिका पांडे; ईला पटनायक
11	भारत में व्यापार चक्र की स्थिति को मापने विषयक ; (नं। 269, मई 2019)	राधिका पांडे; ईला पटनायक; अजय शाह
12	भारत में शिक्षा की वापसी की दर: कुछ अंतर्दृष्टियां ; (सं। 270, जून 2019)	सतद्रु सिकदर
13	भारत में बचत और पूंजी निर्माण; (सं। 271, जून 2019)	ईला पटनायक; राधिका पांडे
14	जैव विविधता:वित्तपोषण : वित्तीय संस्थाओं की भूमिका ; (संख्या 2 ,2, जुलाई 2019)	रीता पांडे; रेणुक साणे
15	मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी प्रभावशीलता और असमानता: एशिया पैसिफिक में जेंडर बजट की प्रभावकारिता; (नहीं। 273 जुलाई 2019)	लेखा चक्रवर्ती
16	वित्तीय संरचना, संस्थागत गुणवत्ता और मौद्रिक नीति संचरण: एक मेटा-विश्लेषण; (नं 274, जुलाई 2019)	रुद्राणी भट्टाचार्य; श्रुति त्रिपाठी; सहाना रॉय
17	क्या राज्यों में जीएसटी मुआवजा अवधि के दौरान जीएसटी संग्रह में अनुमानित वृद्धि को बनाए रखने की क्षमता है?; (नं 275, जुलाई 2019)	सच्चिदानंद मुखर्जी

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक
18	भारत में राज्य उत्पाद कर के लिए फ्रंटियर विश्लेषण ; (नं 276, जुलाई 2019)	सुरांजलि टंडन; आर कविता राव
19	ओईसीडी देशों में पी एफ एम के अनुरूप लिंग बजट निर्धारण: स्वीडन से अनुभवजन्य साक्ष्य; (नं 277, अगस्त 2019)	लेखा चक्रवर्ती
20	भारतीय राज्यों की कर राजस्व दक्षता: स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का मामला; (नहीं। 278, अगस्त 2019)	श्री हरि नायडू
21	भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र में मांग और कर संग्रह का अनुमान; (नं 279, सितंबर 2019)	सच्चिदानंद मुखर्जी
22	भारत में सब नेशनल सरकारों के बजट विश्वसनीयता: 28 राज्यों के राजकोषीय पूर्वानुमान त्रुटियों का विश्लेषण; (नं 280, सितंबर 2019)	लेखा चक्रवर्ती; पिनाकी चक्रवर्ती; रूज़ेल श्रेष्ठ
23	इष्टतम संगामिति - राजकोषीय हस्तांतरण के संदर्भ में एक प्रश्न; (नं। 2 2019, अक्टूबर 2019)	अशोक लाहिड़ी
24	सब्सिडी, मेरिट गुड्स एंड द फिस्कल स्पेस फ़ॉर रिवाइविंग ग्रोथ: एन एस्पेक्ट ऑफ़ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया; (सं। 2 ,2, नवंबर 2019)	सुदीप्तो मंडल; सतादू सिकदर
25	भारतीय राज्यों में सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अनुभव: एक राजकोषीय परिप्रेक्ष्य; (सं।) 283, नवंबर 2019)	मीता चौधरी; श्रुति त्रिपाठी; जय देव दुबे
26	भारत में बजट साख: पी ई एफ ए फ्रेमवर्क के माध्यम से मूल्यांकन; (संख्या 284, दिसंबर 2019)	प्रताप रंजन जेना; सतादू सिकदर
27	चेन्नई 2015 प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को मापने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण। ; (नंबर 285, दिसंबर 2019)	ईला पटनायक; रेणुका साने; अजय शाह
28	पोषण - सार्वजनिक व्यय की समीक्षा: गुजरात से साक्ष्य; (सं। 286, दिसंबर 2019)	लेखा चक्रवर्ती; अमनदीप कौर; रूजेल श्रेष्ठ; कोमल जैन; जैननेट फरीदा जैकब; अनिंदिता घोष
29	राजकोषीय नीति, हस्तांतरण और भारतीय अर्थव्यवस्था; (संख्या 287, दिसंबर 2019)	एन आर भानुमूर्ति; सुकन्या बोस; साक्षी सतीजा
30	तेलंगाना राज्य वित्त का विश्लेषण आर्थिक विकास के लिए ऋण परिपक्वता अवधि का विस्तार; (संख्या 288, दिसंबर 2019)	अनिंदिता घोष, लेखा चक्रवर्ती
31	कर चोरी और बेहिसाब आय :: एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण; (संख्या 289, दिसंबर 2019)	अमय सप्रे
32	1990-91 से 2013-14 के दौरान भारतीय राज्यों की कृषि-पर्यावरणीय स्थिरता। ; (सं। 290, जनवरी 2020)	सच्चिदानंद मुखर्जी
33	भारतीय राज्यों के वित्त पर जीएसटी क्षतिपूर्ति अवधि की समाप्ति के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति की वापसी का संभावित प्रभाव; (सं। 291, जनवरी 2020)	सच्चिदानंद मुखर्जी

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक
34	एस डी जी 2030 के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक पालिसी सुसंगति : एशिया प्रशांत से साक्ष्य; (सं। 292, जनवरी 2020) लेख	लेखा चक्रवर्ती
35	राजकोषीय विवेक किस लिए? कर्नाटक राज्य का वित्तीय विश्लेषण ; (सं। 293, जनवरी 2020)	जेनेट फरीदा जैकब ; लेखा चक्रवर्ती
36	क्या भारत में कर प्रणाली तटस्थ है?: चुनिंदा निधियों के कराधान का विश्लेषण; (सं। 294, जनवरी 2020)	सुरांजलि टंडन
37	23 दिसंबर 2019 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एन आई पी एफ पी अध्यक्ष डॉ विजय केलकर द्वारा दिया गया दीक्षांत भाषण ।; (नं। 295, जनवरी 2020) के	डॉ विजय केलकर
38	भारत में ब्याज दरों के निर्धारण में राजकोषीय नीति की भूमिका का पुनरीक्षण; (सं। 296, फरवरी) 2020)	रंजन कुमार मोहंती; एन आर भानुमूर्ति
39	नई मौद्रिक नीति रूपरेखा - इसका क्या अर्थ है; (सं। 297, फरवरी 2020)	सी रंगराजन
40	भारत में जलवायु परिवर्तन संवेदनशील सार्वजनिक व्यय: एक अनुभवजन्य विश्लेषण; (नं 298, फरवरी 2020)	अमनदीप कौर; लेखा चक्रवर्ती
41	एस्केप क्लॉज़ के पश्चात राजकोषीय समेकन ए कॉल फॉर एक्सेसिवे डेफिसिट प्रोसीजर ; (कोई । 299, मार्च 2020)	लेखा चक्रवर्ती
42	स्वास्थ्य परिणाम के सुधार में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय कितना प्रभावी है? भारतीय राज्यों से अनुभवजन्य साक्ष्य; (नंबर 300, मार्च 2020)	रंजन कुमार मोहंती; दीपक कुमार बेहरा
43	भारतीय जीएसटी का प्रदर्शन आकलन: अनुपालन अंतराल और राजस्व वृद्धि का राज्य-स्तरीय विश्लेषण; (संख्या 301, मार्च 2020)	सच्चिदानंद मुखर्जी

अनुलंग्नक – III आंतरिक सेमिनार श्रृंखला

दिनांक	विषय
शुक्रवार ;10 मई, 2019	"वैश्विक मूल्य श्रृंखला और प्रभावी विनिमय दरें" (संयुक्त रूप से ज़ी वांग और शांग-जिन के साथ)
शुक्रवार;14 जून, 2019	नकद आधारित घरेलु अर्थव्यवस्था में प्राइस स्टिकीनेस : भारत में भोजन कीमतों से साक्ष्य :
शुक्रवार;21 जून, 2019	आपूर्ति-पक्ष और माँग-नेतृत्व में वृद्धि का सिद्धांत: आर्थिक विचार आधारित दृष्टिकोण का इतिहास
गुरुवार;27 जून, 2019	भ्रष्टाचार और स्टॉक मूल्य अस्थिरता: फर्म-स्तरीय साक्ष्य
शुक्रवार;26 जुलाई, 2018	औपचारिक वित्त, गरीबी और मानसिक स्वास्थ्य: भारत से प्रायोगिक साक्ष्य
मंगलवार; 06 अगस्त, 2019	रूटिंग मनी, नॉट पैकेट्स
शुक्रवार; 09 अगस्त, 2019	बिना स्कूलों के गांवों में साक्षरता को बढ़ावा कैसे मिलता है ?: भारतीय गांवों का एक अध्ययन
मंगलवार; 20 अगस्त, 2019	राज्य स्तरीय वित्त के मुद्दे : 2018 -19 के राज्य बजटों की समीक्षा
गुरुवार; 03 अक्टूबर, 2019	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत के संबंध:पच्चीस वर्ष परिप्रेक्ष्य में 1991 - 2016
बुधवार; 23 अक्टूबर 2019	साक्ष्य / प्रमाण:विज्ञान और वायु प्रदूषण के लिए सामाजिक प्रतिक्रिया
शुक्रवार; 25 अक्टूबर, 2019	जलवायु परिवर्तन का न्यूनीकरण कैसे करें
शुक्रवार;15 नवंबर, 2019	प्राकृतिक आपदाओं से निपटना - समुदाय और बाजार की सिकुड़ती भूमिका, और राज्य का विस्तार
सोमवार; 09 दिसंबर, 2019	ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक
मंगलवार;10 दिसंबर, 2019	जनतंत्र में करों का औचित्य
शुक्रवार;13 दिसंबर, 2019	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी: परिप्रेक्ष्य और क्षेत्र अनुभव
शुक्रवार;13 दिसंबर, 2019	क्या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम बीमा लागत बढ़ा देते हैं ?: मेडिकेयर एक अध्ययन
गुरुवार;16 जनवरी, 2020	लिंग आधारित विश्लेषण की त्रिविधा
मंगलवार;21 जनवरी, 2020	ब्रैक्जिट मेल्टडाउन: पॉपिज्म एंड द डायनेमिक्स ऑफ़ ग्लोबल डेक्लाइन
बुधवार; 04 मार्च, 2020	"वन हंड्रेड होम्स" - ए विजुअल सर्वे ऑफ इंडिया
गुरुवार;12 मार्च, 2020	अगली पीढ़ी के न्याय मंच: विजन, कार्यान्वयन और कानूनी ढांचा

अनुलंग्नक– IV शासी निकाय के सदस्यों की सूची

संस्थान के शासी निकाय की दिनांक 18 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में आगामी चार वर्षों अर्थात 5 अप्रैल, 2020 से 4 अप्रैल, 2024 तक की अवधि के लिए शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया।

(शासी निकाय यथा 10 नवम्बर 2020)

1. डॉ उर्जित पटेल — अध्यक्ष
   अध्यक्ष, रा लो वि नी सं
   18/2, सत्संग विहार मार्ग,
   स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू)
   नई दिल्ली 110067

नियम 7(बी)(i) के अंतर्गत (तीन नामांकन वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए हैं)

2. श्री अजय भूषण पांडे — सदस्य
   राजस्व सचिव
   वित्त मंत्रालय
   भारत सरकार
   नार्थ ब्लाक
   नई दिल्ली-110001

3. श्री तरुण बजाज — सदस्य
   सचिव (आर्थिक कार्य)
   वित्त मंत्रालय
   भारत सरकार
   नार्थ ब्लाक
   नई दिल्ली-110001

4. डा. कृष्णामूर्ति सुब्रमणियम — सदस्य
   मुख्य आर्थिक सलाहकार
   वित्त मंत्रालय
   भारत सरकार

नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली-110001

नियम 7(बी)(ii) के अंतर्गत (एक नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा)

5. डा. राजीव रंजन — सदस्य
परामर्शदाता एवं कार्यालय प्रभारी
आर्थिक विश्लेषण एवं नीति अनुसंधान विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुम्बई-400 001

नियम 7(बी)(iii) के अंतर्गत (एक नामांकन योजना आयोग द्वारा)

6. सुश्री अन्ना राय — सदस्य
सलाहकार
नीति आयोग
संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

नियम 7(बी)(iv) के अंतर्गत (तीन नामांकन राज्य सरकारों द्वारा)

7. श्री समीर कुमार सिन्हा, IAS — सदस्य
प्रमुख सचिव
वित्त विभाग
असम सरकार
असम सचिवालय
दिसपुर, गुवाहाटी 781 005

8. श्री राजेश कुमार सिंह, IAS — सदस्य
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
केरल सरकार
सचिवालय
तिरुवनंतपुरम 695 001

9. श्री मनोज सौनिक, आईएएस — सदस्य
अपर मुख्य सचिव (वित्त)
वित्त विभाग
महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय
मुंबई 400 032

नियम 7(बी)(vi) के अंतर्गत (एक नामांकन आईसीआईसीआई बैंक से)

10. श्री प्रसन्ना बी — सदस्य
वैश्विक प्रमुख - बाज़ार (विपणन , व्यापर एवं अनुसंधान)
आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक टावर्स
बांद्रा – कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व
मुम्बई-400 051

नियम 7(बी)(vii) के अंतर्गत (दो नामांकन संस्थानों से)

11. डॉ निरंजन हीरानंदानी — सदस्य
अध्यक्ष
एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
5, सरदार पटेल मार्ग
चाणक्य पुरी
(निकट होटल डिप्लोमेट)
नई दिल्ली-110 021

12 डॉ संगीता रेड्डी — सदस्य
अध्यक्ष
फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-110 001

नियम 7(बी)(viii) के अंतर्गत (दो विख्यात अर्थशास्त्री)

13. प्रोफेसर शैबल गुप्ता — सदस्य
निदेशक
एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआई)
बीएसआईडीसी कालोनी
ऑफ बोरिंग पाटलीपुत्र रोड
पटना 800 013

14. डॉ माला लालवाणी — सदस्य
प्रोफेसर राजनितिक अर्थशास्त्र
मुंबई विश्वविद्यालय
मुंबई

नियम 7(बी)(ix) के अंतर्गत (तीन प्रतिनिधि सहयोगी संस्थानों से)

15. डा. शेखर शाह — सदस्य
महानिदेशक
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनिमक रिसर्च
11, परिसिला भवन
आई.पी.एस्टेट, रिंग रोड
नई दिल्ली – 110 002

16. सुश्री यामिनी अय्यर — सदस्य
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी
सेन्टर फार पालिसी रिसर्च
धर्म मार्ग, चाणक्य पुरी
नई दिल्ली 110 021

नियम 7(बी)(x) के अंतर्गत (एक सदस्य शासी निकाय से लिया जाना)

17 सीए तरूण जे.घिया — सदस्य
आईसीएआई के परिषद सदस्य
द्वारा उप सचिव (परिषद कार्य)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीएआई भवन
आई.पी.मार्ग, नई दिल्ली-110 002

नियम 7(बी)(xi) के अंतर्गत (संस्थान के निदेशक (पदेन)

18. डॉ पिनाकी चक्रबर्ती — सदस्य
निदेशक, रा लो वि नी सं,
नई दिल्ली

नियम 7(बी)(xii) के अंतर्गत (रोटेशन में संस्थान से एक फैल्लो)

19. डा. आर. कविता राव — सदस्य
प्रोफेसर, रा लो वि नी सं,
नई दिल्ली

विशेष आमंत्रित

1. श्री प्रमोद चन्द्र मोदी
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक , नई दिल्ली -110 001

2. श्री एम अजीत कुमार
अध्यक्ष
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110 001

अनुलंग्नक –V मूल्य अंकित प्रकाशनों की सूची

प्रकाशनों की सूची
इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया 1973-74 आर.जे. चिल्लिाह एंवआर.एन.लाल (1978) भा. रूपए 10/- हिन्दी अंक (1981) भा. रूपए 20/-
ट्रेन्ड्स एंड इश्यूज इन इंडियन फेडरल फाइनेंस* आर.जे. चिल्लिाह एंवएसोसिएट्स (एलायड पब्लिशर्स) (1981) भा. रूपए 60/-
सेल्ज टैक्स सिस्टम इन बिहार* आर.जे. चिल्लिाह एंवएम.सी.पुरोहित (सौम्मेया पब्लिकेशंस) (1981) भा. रूपए 80/-
मिजरमेंट ऑफ टैक्स इफेक्ट ऑफ स्टेट गर्वनमेंट्स 1973-76* आर.जे. चिल्लिाह एंवएनसिन्हा (सौम्मेया पब्लिकेशंस) (1982) भा. रूपए 60/-
इम्पेक्ट ऑफ पर्सनल इंकम टैक्स अनुपम गुप्ता एवं पवन के अग्रवाल (1982) भा. रूपए 35
रिसोर्स मोबीलाइजेशन इन द प्रावेट कारपोरेट सेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीडीलाल , श्रीनिवस माथुर एवं केके अत्री (1982) भा. रूपए 50/-
फिसकल इंसेटिव्स एंड कारपोरेट टैक्स सेविंग्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसीडीलाल (1983) भा. रूपए 40/-
टैक्स ट्रिटमेंट ऑफ प्रावेट ट्रस्ट्स के श्रीविनासन (1983) भा. रूपए 140/-
सेंट्रल गर्वनमेंट एक्सपेंडिचर : ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड इम्पेक्ट(1950-51 to 1978-79) केएनरेड्डी, जेवीएमशर्मा एवंएनसिन्हा (1984) भा. रूपए 80/-
एंटरी टैक्स एस एन अल्टरनेटिव टू ऑक्ट्राय एम.जी राव (1984) भा. रूपए 40/- पेपरबैक, भा. रूपए 80/- हार्डकवर
इंफरमेशन सिस्टम एंड इवेजन ऑफ सेल्स टैक्स इन तमिलनाडु आर.जे. चिल्लिाह एंवएम.सी.पुरोहित (1984) भा. रूपए 50/-
इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटिज इन इंडिया, प्लास्टिक एंड कॉटन टैक्सटाइल फैब्रिक्स ए.बागची एट ला (1986) भा. रूपए 180/-
आस्पेक्टस ऑफ ब्लैक इकॉनामी इन इंडिया(''ब्लैक मनी रिपोर्ट'' के नाम से भी ज्ञात) शंकर एन आचार्य एंड एसोसिएट्स, आरजे चेल्लिाह के योगदान के साथ (1986) पुन:मुद्रित अंक भा. रूपए 270/-
इंफलेशन एकाउंटिंग एंड कारपोरेट टैक्सेशन तपस कुमार सेन (1987) भा. रूपए 90/-
सेल्स टैक्स सिस्टम इन वैस्ट बंगालएबागची एवं एसकेदास (1987) भा. रूपए 90/-
रूरल डेवलपमेंट एलाउंस (आयकर अधिनियम, 1961 का खंड 35सीसी): समीक्षा एचकेसोंधी एवं जेवीएम शर्मा (1988) भा. रूपए 40/-
सेल्स टैक्स सिस्टम इन दिल्ली आर.जे. चिल्लिाह एंवके.एन.रेड्डी (1988) भा. रूपए 240/-
इनवेस्टमेंट एलाउंस (आयकर अधिनियम, 1961 का खंड 32ए): एक अध्ययन जे वी एम शर्मा एवं एच के सोंधी (1989) भा. रूपए 75/- पेपर बैक भा. रूपए 100/- हार्डकवर

प्रकाशनों की सूची
स्टीमुलेटिव इफेक्ट ऑफ टैक्स इंसेटिव फार चेरिटेबल कंट्रीब्यूशंस: ए स्टडी ऑफ इंडियन कारपोरेट सेक्टर पवन के अग्रवाल (1989) भा. रूपए 100/-
प्राइसिंग फार पोस्टेज सर्विसेज इन इंडिया राघवेन्द्र झा, एम.एन. मूर्ति एवंसत्य पाल (1990) भा. रूपए 100/-
डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया – ट्रेन्ड्स एंड इश्यूज उमा दत्ता राय चौधरी एवं अमरेश बागची (सम्पादित) (1990) भा. रूपए 240/-
सेल्स टैक्सेशन इन मध्य प्रदेश एमगोविन्द राव, के.एन.बालासुब्रामनियन एवं वी बी तुलसीधर (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) भा. रूपए 125/-
द आपरेशन ऑफ मोडवेट ए.वी.एल.नारायण, अमरेश बागचीतथा आर.सी.गुप्ता, (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) भा. रूपए 250/-
फिस्कल इंसेटिव्स एंड बैलेंस्ड रिजनल डेवलपमेंट: एन इवेन्यूेशन ऑफ सेक्शन 80एचएच पवन के अग्रवालएवंएचकेसोंधी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991) भा. रूपए 195
डायरेक्ट टैक्सेज इन सैलेक्टिड कंट्रीज:ए प्रोफाइल (भाग । एवं ॥) भा. रूपए 100/-
इफेक्टिव इंसेटिव्स फॉर अल्युमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया मोनोग्राफ सिरिज - । बीगोलदार (1991) भा. रूपए 100/-
सर्वे ऑफ रिसर्च ऑन फिस्कल फेडरेलिज्म इन इंडिया मोनोग्राफ सिरिज - ॥ एम.गोविन्द रावएवंआर.जे. चिल्लिाह (1991) भा. रूपए 100/-
रेवन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शंस:इवेल्यूएशन एंड मेथेडोलॉजी वी.जी.राव, संशोधन एवं सम्पादन अतुल शर्मा (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1992) भा. रूपए 195/-
सेल्स टैक्स सिस्टम इन इंडिया: ए प्रोफाइल (1991) भा. रूपए 150/-
स्टेट फाइनेंसिस इन इंडिया अमरेश बागची, जेएलबजाज एवं विलियम एबर्ड (सम्पादित) (1992) भा. रूपए 450/-
फिस्कल पॉलिसी फार नेशनल कैप्टिल रिजन महेश सी पुरोहित, सी.साई कुमार, गोपीनाथ प्रधान एवं ओपी बोहरा (1992) भा. रूपए 225
इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन इन द मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर मोनोग्राफ सीरिज ।।।, हशीम एन सलीम (1992) भा. रूपए 150/-
सेल्स टैक्स सिस्टम इन इंडिया: ए प्रोफाइल(1993) भा. रूपए 150/-
द नाइन्थ फाइनेंस कमीशन:इश्यूज एंड रिकमंडेशंस (ए सेलेक्शन ऑफ पेपर्स) (1993) भा. रूपए 490/-
डायरेक्ट टैक्सेज इन सैलेक्टिड कंट्रीज: ए प्रोफाइल (भाग।।।) समेकन कर्ता के कानन एवं ममता शंकर (1993) भा. रूपए 80/-
इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट वेरियेशंस इन इकॉनोमि डेवलमेंट एंड स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग (मोनोग्राफ सीरिज ।V) (1993) उमा दत्ता राय चौधरीभा. रूपए 200/-
टैक्स प्लानिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, अमरेश बागची एवं निकोलस स्ट्रन (सम्पादन) (1994) (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) भा. रूपए 435/-
रिफार्मस ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड टैक्सिज इन इंडिया: इश्यूज एंड आप्शन स्टडी टीम (1994) भा. रूपए 250/-

प्रकाशनों की सूची
प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर : जनरेशन एंड रिजनरेशन ऑफ वैल्थ्स उमा दत्ता राय चौधरी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1996) भा. रूपए 395/-
कंट्रोलिंग पोल्युशनः इंसेटिव्स एंड रेग्यूलेशंस शेखर मेहता, सुदिप्तो मंडलएवंयू शंकर (सेग पब्लिकेशंस) (1997) भा. रूपए 250/-
इंडिया : टैक्स पालिसी फार द नाइन्थ फाइव ईयर प्लान (1997-98 से 2001-02)#(वित्तीय संसाधनों के संचालन समूह की कर नीति पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट – अध्यक्ष पार्थसारथी शोम) (सैंटेक्स पब्लिकेशंस प्रालि) (1997) भा. रूपए 350/-
वैल्यु एडिड टैक्स इन इंडियाःए प्रोग्रेस रिपोर्टपार्थसारथी शोम (सम्पादित) (सैंटेक्स पब्लिकेशंस प्रालि) (1997) भा. रूपए 250/-
फिस्कल पालिसी पब्लिक पालिसी एंड गर्वनेंस पार्थसारथी शोम (सम्पादित) (सैंटेक्स पब्लिकेशंस प्रालि) (1997) भा. रूपए 400/-
गर्वनमेंट सब्सिडिज इन इंडिया डीकेश्रीवास्तवएवंतपस के सेन (1997) भा. रूपए 285
इकॉनोमी इंस्ट्रूमेंट्स फार एनवार्यनमेंट सस्टेनिबिल्टी यूशंकरएवंओम प्रकाश माथुर (1998) भा. रूपए 150/-
इंडियाः द चैलेंज ऑफ अर्बन गर्वनेंस ** ओम प्रकाश माथुर (सम्पादित) (1999) भा. रूपए 400/-
स्टेट फिस्कल स्टडीज-असम डीकेश्रीवास्तव,सौमन चट्टोपाध्यायएवंटीएसरंगामनार (1999) भा. रूपए 200/-
स्टेट फिस्कल स्टडीज-पंजाब इंदिरा राजारमण,एचमुखोपाध्यायएवंएचकेअमरनाथ (1999) भा. रूपए 200/-
स्टेट फिस्कल स्टडीज-केरलडीकेश्रीवास्तव, सौमन चट्टोपध्यायएवंप्रताप रंजन जेना (1999) भा. रूपए 200/-
दिल्ली फिस्कल स्टडीओम प्रकाश माथुरएवं टीएसरंगामनार (2000) भा. रूपए 250/-
फिस्कल फेडरेलिज्म इन इंडिया कांटैम्परेरी चैलेंजिस बिफोर द इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन डीकेश्रीवास्तव (सम्पादित) (हरआनन्द पब्लिकेशंस प्रालि) (2000) भा. रूपए 695
स्टेट फिस्कल स्टडीज-हरियाणा तपस के सेन, आरकविता राव (2000) भा. रूपए 200/-
कंट्रोल ऑफ पब्लिक मनी : द फिस्कल मशीनरी इन डेवलपिंग कंट्रीज * ए प्रेमचन्द (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) (2000) भा. रूपए 745
प्राइमर आन वैल्यु एडिड टैक्स # आर.जे. चिल्लिाह , पवन के अग्रवाल, महेश सी पुरोहितएवंआरकविता राव (हर आनन्द पब्लिकेशंस प्रालि) (2001) भा. रूपए 195/-
सेन्ट्रल बजटरी स्टडीज इन इंडिया डीकेश्रीवास्तवएवंएचके अमर नाथ (2001) भा. रूपए 170/-
एप्रोच टू स्टेट म्यूनिसीपल फिसकल रिलेशंस : आप्शंस ऑन पर्ससपेक्टिव्स ओम प्रकाश माथुर (2001) भा. रूपए 200/-
ट्रेड एंड इंडस्ट्रीः एस्से बॉई एनआईपीएफपी फोर्ड फाउंडेशन फैल्लो एके गुहा, केएलकृष्णानंद, अशोक के लाहिरी (सम्पादित) (विकास पब्लिशिंग हाउसप्रालि) (2001) भा. रूपए 450/-
ट्रांसफर प्राइसिंग एंड रेग्यूलेशंस फार इंडियाः एप्रुवल एंड आल्टरनेटिव्स आरकेबजाज के सहयोग से एसपीसिंह एवंअमरेश बागची (यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रालि) (2002) भा. रूपए 395/-

प्रकाशनों की सूची
डिस्क्रिमनेट्री टैक्स ट्रिटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायज-ए-वाएज फोरेन प्रोडक्ट्स: एन एस्सेसमेंट पवन के अग्रवालतथावीसेल्वाराजु (2002) भा. रूपए 200/-
द प्रेक्टिस एंड पालिटिक्स चह रेग्युलेशन: रेग्युलेटरी गर्वनेंस इन इंडिया इलैक्ट्रिसिटी – नवरोज के दोबाश एवं डी नरसिम्हा राव भा. रूपए 290/- (भंडार में उपलब्ध: 32)
टैक्लिंग पावर्टी कंसट्रेंट्स आन ह्यूमन डेवलपमेंट: फाइनेसिंग स्ट्रैटरजिस इन मध्य प्रदेश (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट) मोनोग्राफ सीरिज) – तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीतथाअनित मुखर्जी (2007) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 56)
फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन तमिलनाडु:कंसोलिडेंग एंड बिल्डिंग अपोन एचिवमेंट (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीतथा अनित मुखर्जी (2008) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध22)
इंटर स्टेट इक्विलाइजेशन ऑफ हैल्थ एक्सपिंडिचर इन इंडिया यूनियन –एम; गोविन्द राव तथा मीता चौधरी (2008)भा. रूपए 75/- (भंडार में उपलब्ध 94)
ट्रैप्पड इन कंफर्ट जोन ऑफ डिनायल 50 ईयर्स ऑफ एक्सपिंडिचर मैनेजमेंट इन इंडिया– ए प्रेमचन्द (2008) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 86)
फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन एंड जैंडर बजटिंग – एम गोविन्द राव, लेखाचक्रबर्ती, अमरेश बागची (2008) भा. रूपए 250/- (भंडार में उपलब्ध 96)
फिस्कल रिफार्मस, पर्सिस्टेंट पावर्टी एवं ह्यून डेवलपमेंट: द केस ऑफ ओडिश (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीएवंप्रोतिवा कुण्डु (2008) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 98)
डिलिंग विद फिस्कल कंस्ट्रेंस आन पब्लिक फाइनेंसिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन वैस्ट बंगाल (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीएवंप्रोतिवा कुण्डु(2009)भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध148)
प्रोस्पैक्ट्स एंड पालिसिज फार लो कार्बन इकॉनामिक ग्रोथ ऑफ इंडिया – रामप्रसाद सेनगुप्ता (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध: 114)
पालिसी इंस्ट्रूमेंट फार एचिविंग लो कार्बन एंड हाई ग्रोथ इन इंडिया– यूशंकर (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 120)
राजस्थान – फोरकास्टिंग इकॉनोमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कंकरेंटली (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीएवं सुरजीत दास(2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध147)
इंडिया – पब्लिक एक्सपिंडिचर एंड फाइनेंसियल एकाउंटेबिल्टी – पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट पर्फार्मेंस एस्सेसमेंट रिपोर्ट - प्रताप रंजन जेना (2010)भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध: 29)
रिर्सोसेज फार सस्टेनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एचके अमर नाथ, मीता चौधरीएवं सुरजीत दास (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध142)

प्रकाशनों की सूची
रेपिड ट्रांसिशन ऑफ ए यंग स्टेट टू मैच्युरिटी: रिर्सोसेज फार ह्यूमन डेवलपमेंट इन (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन,एचकेअमरनाथ,मीता चौधरी एवं सुरजीत दास (2010)भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 151)
फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन केरल : इश्यूज एंड चैलेंजिस (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज) – पिनाकी चक्रबर्ती, लेखा चक्रबर्ती, एचके अमर नाथ, एवं सोना मित्रा (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 153)
मार्चिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एक्रास महाराष्ट्र विद इट्स इकॉनमिक डेवलपमेंट (फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरिज)– तपस के सेन, एच के अमरनाथ, मीता चौधरी एवं सुरजीत दास (2010) भा. रूपए 150/- (भंडार में उपलब्ध 157)
अनस्पैंट बैलेंसेज एंड फंड फ्लो मैकेनिज्म अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) – एन आर भानुमूर्ति, एच के अमर नाथ, अखिलेश वर्मा तथा आदर्श गुप्ता (2014)भा. रूपए 200/- (भंडार में उपलब्ध 98)
मध्य प्रदेश स्टेट एमडीजी रिपोर्ट 2014-15 – एनआरभानुमूर्ति, एचकेअमरनाथ, सुकन्या बोस, परम चक्रवर्ती, एवं अकराज्योति जेना (2015) (भंडार में उपलब्ध 98)
डायर्वजेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स इन मध्य प्रदेश : द रोल ऑफ फिस्कल पालिसी एंड गर्वनेंस – एनआरभानुमूर्ति, एचकेअमरनाथ, मनीष प्रसाद, शिनॉयचक्रबर्ती, एवंऋचा जैन (2017) (भंडार में उपलब्ध 37)
एमर्जिंग इश्यूज इन स्टेट फाइनेंसेज पोस्ट फोर्टिन्थ फाइनेंस कमीशन: एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स 2016-17 - मनीष गुप्ता, लेखा चक्रबर्तीएवंपिनाकी चक्रबर्ती (2018) (भंडार में उपलब्ध165)
एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स 2017-18: एमर्जिंग इश्यूज (इम्पेक्ट ऑफ पावर सेक्टर डेब्ट-उदय ऑन स्टेट फाइनेंस)पिनाकी चक्रबर्ती, मनीष गुप्ता, लेखा चक्रबर्ती, अमनदीप कौर (2018) भा. रूपए 200/-

- सह-प्रकाशन / संबंधित प्रकाशक के पास उपलब्ध

सह-प्रकाशन / एनआईपीएफपी के पास उपलब्ध

** केवल फोटोकापी पुस्तक उपलबध

ड्राफ्ट/धनादेश की प्राप्ति पर प्रकाशन प्रेषण डाक शुल्क भा. रूपए 30/- प्रति प्रति

नोट : क्रम संख्या 1 से 38, 40,41,54 तथा 61 पर दर्शाए गए प्रकाशन बिक्री के लिए अब उपलब्ध नहीं हैं।

अनुलंग्नक –VI *रा लो वि नी सं संकाय सदस्यों की प्रकाशित सामग्री*

भानुमूर्ति, एनआर

1. "कॉफी क्षेत्र पर सब्सिडी का प्रभाव" पर पुस्तक, कॉफी बोर्ड, 2019 द्वारा प्रकाशित (भाबेश हज़ारिका के साथ)

2. "वित्तीय वैश्वीकरण और दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास", दक्षिण एशिया आर्थिक जर्नल, सेज , मार्च 2020 (लोकेन्द्र कुमावत के साथ)

3 "भारत में भौतिक अवसंरचना, वित्तीय विकास और आर्थिक विकास के बीच गतिशील संबंध का विश्लेषण", Vol.33, No.4, 2019, पीपी 381-403, एशियाई आर्थिक पत्रिका, (रंजन कुमार मोहंती के साथ)

4. "भारतीय राज्यों में सार्वजनिक व्यय की दक्षता का आकलन" , आगामी, जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स , वायली । (रंजन कुमार मोहंती के साथ) ।

5. "ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बदलता परिदृश्य" , कुरुक्षेत्र, अगस्त, 2019, P.2.2-28 (भाबेश हजारिका के साथ)

भट्टाचार्य, रूद्राणी

6. भट्टाचार्य, रुद्राणी और जैन, ऋचा, (2019), "क्या मौद्रिक नीति खाद्य मुद्रास्फीति को स्थिर कर सकती है? उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से साक्ष्य ", आर्थिक मॉडलिंग, (लिंक: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999318310265)

7. भट्टाचार्य, रुद्राणी, जैन, ऋचा, और सिंह, अभिषेक, (2019) , "भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में मार्क-अप शॉक के योगदान को मापने सम्बन्धी", IIMB प्रबंधन की समीक्षा, वॉल्यूम 31, नंबर 2, पीपी: 167-181।

8. भट्टाचार्य, रुद्राणी, चक्रवर्ती, परमा और मुंडले सुदीप्तो, (मई, 2019), "भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान: ए टाइम वेरियिंग पैरामीटर रिग्रेशन एप्रोच", मैक्रोइकॉनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन इमर्जिंग मार्किट इकॉनॉमीज, टेलर और फ्रांसिस जर्नल्स , वॉल्यूम 12, (3), पृष्ठ 205-228, सितंबर।

9. बनर्जी, शेषाद्री और भट्टाचार्य, रुद्राणी, (14 दिसंबर, 2019), "भारत में सूक्ष्म स्तर मूल्य निर्धारण व्यवहार: एविडेंस फ्रॉम कंस्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर", इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली वॉल्यूम 54, संख्या 49।

10. सेन गुप्ता, अभिजीत, भट्टाचार्य, रुद्राणी और सिकदर सताद्रू (नवंबर, 2019), "समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचा निर्माण",मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में 22 नवंबर, 2019 को द इंडियन इकॉनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा आयोजित विकास और स्थिरता के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत ।

सुकन्या बोस

11. बोस, एस, पी घोष और ए सरदाना (2019): "शिक्षा के अधिकार को क्या हासिल करना चाहिए ?" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक एंगेज , वॉल्यूम। 54, अंक संख्या 18, 04 मई, 2019 https://www.epw.in/engage/article/what-does-right-education-need-achieve

12. बोस, सुकन्या (2019) गोविंद भट्टाचार्य, "भारत के विशेष श्रेणी राज्य", जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, वॉल्यूम 4, अंक 2 पृष्ठ 216-221

13. बोस, एस, और ए सरदाना (2019) "मसौदा एनईपी और वित्त का सवाल, कोन्फ़्लुएन्स" , जुलाई http://confluence.ias.ac.in/the-draft-nep-and-the-question-of-finances/

चक्रबर्ती, लेखा

14. "ओडिशा द्वारा लोक वितीय प्रबंधन मे मार्ग दर्शन" अमनदीप कौर और लेखा चक्रवर्ती

15. चक्रवर्ती, लेखा , थॉमस इसाक और आर मोहन के साथ (2020) "भारतीय संघवाद में चुनौतियां", (वीटो तानजी की समीक्षा के साथ) लेफ्ट वर्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली

16. लेखा चक्रवर्ती, (अमनदीप कौर, रुजेल श्रेष्ठ, जेनेट फरीदा जैकब, अनिंदिता घोष के साथ): "पोषण-लोक व्यय की समीक्षा: गुजरात से साक्ष्य", रा लो वि नी सं प्रकाशन, नई दिल्ली

17. एच। विनोद, एच करुण और लेखा चक्रवर्ती। (2020) "भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश को प्रोत्साहन: MEBOOT कार्यप्रणाली का उपयोग कर अर्थमितीय अनुमान : हैंडबुक ओन स्टेटिस्टिक्स R का उपयोग, ऋषिकेश डी विनोद और सीआर राव द्वारा संपादित जनवरी 2020 https://www.bookdepository.com/Financial-Macro-Micro-Econometrics-Using-R-42-Hrishikesh-D-Vinod/9780128202500

18. लेखा चक्रवर्ती, वी नैय्यर और कोमल जैन (2020) "जेंडर बजट की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: प्रयोगसिद्ध साक्ष्य", हैंडबुक ऑन जेंडर, डाइवर्सिटी एंड फेडरलिज्म - इंटरनेशनल हैंडबुक ऑन जेंडर सीरीज़, जिल विकर्स, और ओंटारियो, जोन ग्रेस, और चेरिल एन। कोलियर द्वारा सम्पादित, प्रकाशन दिनांक: जून 2020 आईएसबीएन: 978 1 78811 929 एडेड: सी 432 पी, https: //www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-on-gender-diversity-and-federalism-9781788119290.html

19. लेखा चक्रवर्ती, भारतीय राजस्व, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम । 55 अंक 5, फरवरी। 1, 2020

20. लेखा चक्रवर्ती, एस्केप क्लॉज के बाद राजकोषीय समेकन , इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली , वॉल्यूम पोस्ट। 55, अंक 9, फेब 29, 2020

21. अभिषेक आनंद और लेख चक्रवर्ती, ऋणात्मक ब्याज दरों विषयक (इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली मे प्रकाशनाधीन)

22. लेखा चक्रवर्ती और इमैनुअल थॉमस, 2020 "कोविद -19 और मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता: राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत प्रतिक्रिया" इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, मई 2020.

23. चक्रवर्ती, लेखा (जे स्टॉटस्की और पी गांधी के साथ), 2019, "इंटरगवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर एंड जेंडर इक्वेलिटी: इम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम इंडिया, वर्किंग पेपर IDRC GRoW सीरीज़ मैकगिल यूनिवर्सिटी, मॉन्ट्रियल, कनाडा।

24. चक्रवर्ती, लेखा, 2019। चौराहे पर भारतीय राजकोषीय संघवाद, लेवी अर्थशास्त्र संस्थान, वर्किंग पेपर सीरीज 937

25 चक्रवर्ती, लेखा, 2019। मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी प्रभावशीलता और असमानता: एशिया पैसिफिक में जेंडर बजट की प्रभावकारिता (18 जनवरी, 2019)। । (मैरियन इन्ग्राम और यादवेंद्र सिंह के साथ), लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, वर्किंग पेपर्स सीरीज 920 (2019)

लोकप्रिय लेखन

26. विद्या बी रामजी और लेखा चक्रवर्ती।: 'प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण न्याय संगतता के लिए एक पहल', द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 2020

27. लेखा चक्रवर्ती और इमैनुएल थॉमस, 2020, भारत-अमेरिका संबंध: व्यापार और निवेश बढ़ाने का उचित समय - द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 5 मार्च, 2020

28. लेखा चक्रवर्ती डेटा फंडामेंटलिज़्म: द राइज़ ऑफ़ डेटा सेल्फ-सेंसरशिप थ्रेशोल्ड्स 'द फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस', 25 फरवरी, 2020 में प्रकाशित

29. लेखा चक्रवर्ती: "कलयाणकारी उपायों और मुफ्त वितरण योजनाओं में क्या अंतर है?" द हिंदू के जयंत श्रीराम से बातचीत । द हिंदू पार्ले में पॉडकास्ट का लिंक https: //www.theleu है। com / podcast / is-the-the-idea-of-free-a-elitist-construct-a-hindu-parley-podley / article30870980.ec

30. लेखा चक्रवर्ती "क्या पर्याप्त राजकोषीय अंतर और सामाजिक आर्थिक संदर्भ ही कल्याणकारी नीतियों का आधार होना चाहिए?"। यह लेख 'द हिंदू', 21 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था

31. लेखा चक्रवर्ती "द हर्डर हिट हाफ व्हाई इंडिया नीड्स ऐ जेण्डरड एप्रोच टु कोविद -19 ", 2020 मई फोर्ब्स

32. लेखा चक्रवर्ती: "भारत में जेंडर बजटिंग की एक विशाल छलांग" (पब। 09/02/2020 बिजनेस स्टैंडर्ड)

33. लेखा चक्रवर्ती (हरिकृष्णन एस के साथ) "भारत में लॉकडाउन की राज्यार्थ व्यवस्था" 'द' मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट ब्लॉग में , द लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ बार्ड कॉलेज, 2 जून, 2020

34. लेखा चक्रवर्ती सीतारमण को एक उच्च राजकोषीय घाटे की पूरी संभावना का फायदा उठाने का मौका मिला, पब। 01/02/2020, द वायर

मीता चौधरी

35. मीता चौधरी, "निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा: आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन के लिए निहितार्थ" [प्रीतम दत्ता के साथ] इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली (प्रकाशनाधीन)

36. मीता चौधरी, (रंजन कुमार मोहंती के साथ) "वित्तीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पहलू: भविष्य के लिए प्रभाव और विचार " अनुसंधान रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी गई (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया)

37. मीता चौधरी, रिसर्च रिपोर्ट (जे देव दुबे और बिदिशा मोंडल के साथ)"71 वें दौर से स्वास्थ्य पर घरेलू खर्च का विश्लेषण" विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सौंपी गई नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन इंडिया की रिपोर्ट।

प्रताप रंजन जेना

38. प्रताप रंजन जेना , "विकास की दृष्टि और सक्षम नीति विकल्प: केंद्रीय बजट 2019-20 का मैक्रोइकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य", चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल, अगस्त 2019

39. प्रताप रंजन जेना (डॉली गौड़ और डॉ.दिप्ती रंजन महापात्रा के साथ) , "नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स: ड्रैग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस रिसर्च , प्रकाशन के लिए स्वीकृत ।

40 प्रताप रंजन जेना , "भारत में में राजकोषीय संघवाद एवं लोक वित्तीय प्रबंधन के समकालीन मुद्दे", भारत में संघवाद मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट और उसके बाद " सम्मेलन , नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला में 24-25 जून 2019 को आयोजित

41 प्रताप रंजन जेना , (गोपाल चंद और डॉ.दिप्सी रंजन महापात्रा के साथ) "इंडियन एयरपोर्ट्स की दक्षता: एक गैर-पैरामीट्रिक माप" CA CCF द्वारा , 23 जनवरी 2020, एमिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

रंजन कुमार मोहंती

42 रंजन कुमार मोहंती 2019 "भारत में भौतिक अवसंरचना, वित्तीय विकास और आर्थिक विकास के बीच गतिशील संबंध का विश्लेषण", Vol.33, No.4, 2019, पीपी 381-403, एशियाई आर्थिक पत्रिका, (भानुमूर्ति, एनआर के साथ)

43. रंजन कुमार मोहंती "भारतीय राज्यों में सार्वजनिक व्यय की दक्षता का आकलन" , आगामी, जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स , वायली । भानुमूर्ति, एनआर के साथ) ।

45. बेहरा, डी के, आर के मोहंती, यू. दास, (2020), "भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की चक्रीयता: राजकोषीय हस्तांतरण और घरेलू राजस्व संग्रहण की भूमिका" , अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, वॉल्यूम। 67, नंबर 1, पीपी: 87-110।

46. मोहंती, आर के , एस पांडा, बी भुयान (2020), "क्या प्रतिरक्षा व्यय और इसकी संरचना भारत में आर्थिक विकास को प्रभावित करती है?", मार्जिन: एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के जर्नल, वॉल्यूम। 14, नंबर 1, पीपी: 62-85।

47. पात्रा, एस के, आर के मोहंती, (2019), "क्या दक्षिण एशियाई देशों के बीच फेल्डस्टीन-होरीओका पहेली अस्तित्व में है? एक रेजीम स्विचिंग दृष्टिकोण", जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स , https://doi.org/10.1002.pa.206

48. रंजन कुमार मोहंती (मीता चौधरी के साथ) "वित्तीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पहलू: भविष्य के लिए प्रभाव और विचार " अनुसंधान रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी गई (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया)

सच्चिदानंद मुखर्जी

49. मुखर्जी, एस (2020), "राजस्व अनिश्चितता की उपस्थिति में अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण: भारत में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का मामला", जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट पालिसी एंड प्रैक्टिस वॉल्यूम 5 (1): 74 -102।

50. मुखर्जी, एस (2020), "भारत के लिए लो-कार्बन एनर्जी सिक्योरिटी के मार्ग की खोज:-एशिया-पैसिफिक एनर्जी कोऑपरेशन का योगदान"

भारद्वाज, संजय (सं०) भारतीय ऊर्जा सुरक्षा: अंतर-क्षेत्रीय सहयोग। एनर्जी सिक्योर सोसाइटी, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली में ।

51. मुखर्जी, एस और डी। चक्रवर्ती (2020), "ट्रेड एंड एनवायरनमेंट: इश्यूज एंड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स", डे, प्रबीर और अजीतवा राय चौधरी (सं०), "विश्व व्यापार संगठन के 25 वर्ष और भारत ", ऋषि प्रकाशन: नई दिल्ली।

52. राव, आर कविता और एस। मुखर्जी (2019)," भारत में वस्तु और सेवा कर का विकास ", नई दिल्ली: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (आईएसबीएन: 9781108473965), अप्रैल 2019.

53. मुखर्जी, एस (2020), "जीएसटी के कारण राजस्व हानि के लिए छावनी बोर्डों का मुआवजा", इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली , 55 (2): 15-18, 11 जनवरी 20 20.

54. मुखर्जी, एस (2020), "भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र में मांग और कर संग्रह का अनुमान", जर्नल ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वॉल्यूम। 12, नंबर 1 (डीओआई: 10.1177 / 0974930620903558), 11 फरवरी 2020.

55. मुखर्जी, एस (2019), "क्या राज्यों में जीएसटी मुआवजा अवधि के दौरान जीएसटी संग्रह में अनुमानित वृद्धि को बनाए रखने की क्षमता है?", रिव्यु ऑफ़ मार्किट इंटीग्रेशन , वॉल्यूम। 11, नंबर 1 (डीओआई: 10.1177 / 0974929219882130), 4 नवंबर 2019

56. मुखर्जी, एस (2019), "जीएसटी में अनुपालन के मुद्दे - सीएजी की रिपोर्ट पर चिंतन ,इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 54 (47) : 22-24।, 30 नवंबर 2019

57. मुखर्जी, एस (2019), "भारतीय राज्यों में मूल्य वर्धित कर दक्षता: पैनल स्टोचस्टिक फ्रंटियर विश्लेषण", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 54 (22): 40-50, 1 जून 2019 ।

58. मुखर्जी, एस और आर कविता राव (2019), "वैल्यू एडेड टैक्स और अनौपचारिकता: भारत में राज्य वैट के तहत उद्यमों के पंजीकरण के निर्धारक", मार्जिन-द जर्नल ऑफ़ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च , 13 (1) : 21-48।

59. मुखर्जी, एस (2020), "COVID-19: भारत में अनिश्चितताओं को कैसे कम करें, आत्मविश्वास बढ़ाएँ और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करें?" भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए COVID-19 की चुनौतियां: व्यापार और विदेश नीति प्रभाव, आसियान-भारत केंद्र (AIC) - इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (EEPC), नई दिल्ली, अध्याय 14, पीपी .65-69

कॉन्फ्रेंस पेपर्स

60. मुखर्जी, एस (2019), " एग्री एनवायर्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ़ इंडियन एग्रीकल्चर : भारतीय राज्यों का 1990-91 से 2013-14 तक का विश्लेषण", विकास अर्थशास्त्र में समकालीन मुद्दों पर XXIXth वार्षिक आम सम्मेलन में प्रस्तुत शोध पत्र , 16-17 दिसंबर 2019, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता।

61. मुखर्जी, एस (2019), "व्यापार और पर्यावरण: मुद्दे और उभरते परिप्रेक्ष्य", इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) और एक्जिम बैंक सेमिनार में प्रस्तुत किया गया शोध पत्र विश्व व्यापार संगठन के 25 वर्ष और भारत: एक पूर्वव्यापी अवलोकन , 5-6 सितंबर 2019, नई दिल्ली।

62. मुखर्जी, एस (2019), "भारत के लिए लो-कार्बन एनर्जी सिक्योरिटी के मार्ग की खोज:-एशिया-पैसिफिक एनर्जी कोऑपरेशन का योगदान", अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में शोध पत्र प्रस्तुत "इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी: इंटर-रीजनल कोऑपरेशन टू एनर्जी सिक्योर सोसाइटी", स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (SIS), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली, 19 मार्च 2019

दिनेश कुमार नायक

63. नायक, डी के, और बी। हजारिका (2019), "पीएमएवाई (यू) के माध्यम से शहरी भारत में रोजगार सृजन," अर्बन इंडिया , वॉल्यूम 39 (2) (जुलाई-दिसंबर, 2019) pp.46-63। ISSN 0970-9045

64. नायक, डी के (2019), "सीजनल माइग्रेशन एंड स्पेसिअल डायवर्सिफिकेशन ऑफ़ लेबर मार्केट," IASSI त्रैमासिक, 38 (3), pp.33-4-422। PrintISSN: 0970-9061, ऑनलाइन ISSN: 0974-018X

राधिका पांडे

65. राधिका पांडे, गुरन के पसरीचा, ईला पटनायक और अजय शाह, `पूंजी नियंत्रण के लिए प्रेरणाएँ और उनकी प्रभावशीलता '6 नवंबर, 2019 को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ फ़ाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में प्रकाशित।https: //onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijfe.1795

66. राधिका पांडे, अमय सप्रे और प्रमोद सिन्हा, 60 `हम फर्मों की बदलती आर्थिक गतिविधियों के बारे में क्या जानते हैं? ' स्टडीज इन माइक्रोइकॉनॉमिक्स में 11 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित : https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2321022218869790

67. राधिका पांडे, राजेश्वरी सेनगुप्ता, आतमीन शाह और भार्गवी ज़वेरी, "एक बड़ी, उभरती हुई अर्थव्यवस्था में विदेशी संस्थागत निवेशकों पर कानूनी प्रतिबंध ; एक व्यापक डेटासेट - डेटा इन ब्रीफ, वॉल्यूम 28, फरवरी, 2020 में प्रकाशित https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919311746

68. राधिका पांडे, राजेश्वरी सेनगुप्ता, आतमिन शाह और भार्गवी झवेरी, "भारत में विदेशी संस्थागत निवेश पर पूंजी नियंत्रण का क्रम-विकास", IGIDR वर्किंग पेपर, WP-2019-034, दिसंबर 2019: https: //ifrogs.org/PDF/WP-2019p34.pdf

ईला पटनायक

69. सुप्रिया कृष्णन और ईला पटनायक, "भारत में स्वास्थ्य और आपदा जोखिम प्रबंधन" एमिली यिंग यांग चैन और राजीब शॉ, द्वारा संपादित पुस्तक 'पब्लिक हेल्थ एंड डिजास्टर्स- हेल्थ इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन एशिया', में स्प्रिंगर सिंगापुर, पृष्ठ 155-184, फरवरी 2020.

70. ईला पटनायक "भारत में घरेलू वित्तीय बचत पर कर छूट का प्रभाव" (राधिका पांडे और रेणुका साने के साथ), द इंडिया पॉलिसी फोरम, प्रकाशित, वॉल्यूम 15 (15 फरवरी 2020 को जारी)।

71. ईला पटनायक और राधिका पांडे, 2019 "बैंकिंग सुधार : पुणे इंटरनेशनल सेंटरइंडिया पब्लिक पॉलिसी एजेंडा"

72 ईला पटनायक, राधिका पांडे, गुरन के पसरीचा और अजय शाह, `पूंजी नियंत्रण के लिए प्रेरणाएँ और उनकी प्रभावशीलता '6 नवंबर, 2019 को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ फ़ाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में प्रकाशित।https: //onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijfe.1795

रथिन राय

73. 2019 “चेंजिंग फिस्कल डायानामिक्स”, सेमिनार, जनरल, नई दिल्ली में, 30 अप्रैल 2019

अजय शाह

74. अजय शाह और विजय केलकर , "गणतंत्र की सेवा में: आर्थिक नीति की कला और विज्ञान" पेंगुइन एलन लेन , दिसंबर 2019

75. अजय शाह, "स्वास्थ्य के लिए साझा वस्तुओं हेतु वित्त संग्रहण: भारत से एक सार्वजनिक प्रशासन परिप्रेक्ष्य", सनिता सपत्नेकर, हरलीन कौर और शुभो रॉय के साथ हेल्थ सिस्टम एंड रिफॉर्म्स , वॉल्यूम 5, अंक 4, पृष्ठ 391-396, अक्टूबर 2019.

76. अजय शाह, शुभो रॉय, बीएन श्रीकृष्ण और सोम शेखर "भारत में विनियमन के लिए राज्य क्षमता का विकास "। देवेश कपूर और माधव खोसला द्वारा संपादित भारत में विनियमन: डिजाइन, क्षमता व प्रदर्शन। ऑक्सफोर्ड: हार्ट प्रकाशन, अप्रैल 2019।

रेणुका साने

77. रेणुका साने "भारत में घरेलू वित्तीय बचत पर कर छूट का प्रभाव" (राधिका पांडे और ईला पटनायक के साथ), द इंडिया पॉलिसी फोरम, प्रकाशित, वॉल्यूम 15 (15 फरवरी 2020 को जारी)।

78. रेणुका साने, "अकाउंटिंग स्कैंडल के अनुलवन में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग"; इमर्जिंग मार्केट्स रिव्यू 18 अगस्त 2019

79. रेणुका साने और सुज़ैन थॉमस, "भागीदारी से पुनर्खरीद तक: लो इनकम हाउसहोल्ड्स एंड माइक्रो-इंश्योरेंस" वॉल्यूम 87, अंक 3, पहली बार प्रकाशित: 28 जून 2019, द जर्नल ऑफ़ रिस्क एंड इंश्योरेंस। https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jori.12288

अमय सप्रे

80. सप्रे, अमेय, आर नागराज और राजेश्वरी सेनगुप्ता (2019) "संशोधन के चार साल बाद, भारत के राष्ट्रीय लेखा अनुमान के संशोधन पर बहस का पुनर्मूल्यांकन", इंडिया पॉलिसी फोरम, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च (एनसीएईआर, नई दिल्ली, जून 2019)

81. सप्रे, अमेय और सेनगुप्ता, राजेश्वरी (2019) जीडीपी माप, नवाचारी भारत 2019-2024, पुणे इंटरनेशनल सेंटर प्रकाशन, अप्रैल, 2019

सताद्रू सिकदर

82. सताद्रू सिकदर, "सब्सिडी, मेरिट गुड्स एंड द फिस्कल स्पेस फॉर रिवाइविंग ग्रोथ: भारत में सार्वजनिक व्यय का एक पहलू" (सुदीप्तो मुंडले के साथ) इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली , 1 फरवरी, 2020, वॉल्यूम। LV सं। 5, पीपी। 52 से 60.

83. सताद्रू सिकदर, "इंक्लूसिव फिस्कल एडजस्टमेंट फॉर रिवाइविंग ग्रोथ : 2019-20 के बजट का आकलन", (सुदीप्तो मुंडले के साथ) इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 21 सितंबर, 2019, वॉल्यूम। LIV नं। 38, पीपी। 32 से 36.

84. सताद्रू सिकदर, "इंक्लूसिव फिस्कल एडजस्टमेंट फॉर रिवाइविंग ग्रोथ : 2019-20 के बजट का आकलन", (सुदीप्तो मुंडले के साथ), भारत में अर्थव्यवस्था: महान मंदी? भारत में आर्थिक विकास (EDI), वॉल्यूम? 248, उमा कपिला, अकादमिक फाउंडेशन, 2020 द्वारा संपादित।

85. सताद्रू सिकदर, "समावेश को चुनौती: भारत में स्कूली पढ़ाई कैसी हो रही है?" (प्रवीण झा, पूजा पार्वती के साथ), लोकतंत्र, शिक्षा और विकास: न्याय संगतता और समावेश से संबंधित मुद्दे, एन वी वर्गीज और एम बंद्योपाध्याय, द्वारा संपादित: शिप्रा प्रकाशन और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NIEPA), नई दिल्ली, नवंबर 2019.

सुरांजली टंडन

86. सुरांजली टंडन, अंतर्राष्ट्रीय कर में बहुपक्षवाद को चुनौती: दो उपायों की एक कहानी, अंक 4, 2019, ब्रिटिश टैक्स रिव्यू।

87. सुरांजली टंडन, "उदारीकृत भारत में विनिमय दर और वाणिज्यिक व्यापार", रूटलेज।

श्रुति त्रिपाठी

88. श्रुति त्रिपाठी, राज्य वित्त का मूल्यांकन: जम्मू और कश्मीर (2006-07 से 2016-17) 15 वें वित्त आयोग के लिए प्रस्तुत किया गया
URL:https://fincomindia.nic.in/ShowContent.aspx?uid1=11&uid2=6&uid3=0&uid4=0&uid5=0&uid6=0&ui d7=0

अनुलंग्नक –VII स्टाफ सदस्यों की सूची *(दिनांक 31.3.2020 तक)*

संकाय

1.	डा. रथिन राय	निदेशक
2.	डा. (सुश्री) आर.कविता राव	प्रोफेसर
3.	डा.(सुश्री) ईला पटनायक	प्रोफेसर
4.	डा. अजय शाह	प्रोफेसर
5.	डा. पिनाकी चक्रबर्ती	प्रोफेसर (छुट्टी पर)
6.	डा.एन.आर.भानुमूर्ति	प्रोफेसर
7.	डा. प्रताप रंजन जेना	एसोसिएट प्रोफेसर
8.	डा.(सुश्री) लेखा एस. चक्रबर्ती	प्रोफेसर (23.05.2019 को शामिल हुए)
9.	डा.(सुश्री) मीता चौधरी	एसोसिएट प्रोफेसर
10.	डा.सच्चिदानंद मुखर्जी	एसोसिएट प्रोफेसर
11.	डा. एच.के.अमरनाथ	एसोसिएट प्रोफेसर
12.	डा. रेणुका साने	एसोसिएट प्रोफेसर
13.	डा. मुकेश कुमार आनन्द	एसोसिएट प्रोफेसर
14.	डा. मनीष गुप्ता	सहायक प्रोफेसर
15.	डा.रूद्राणी भट्टाचार्य	सहायक प्रोफेसर
16.	डॉ सुधांशु कुमार	सहायक प्रोफेसर (31 अगस्त, 2019 को इस्तीफा दिया)
17.	डा. भारती भूषण दास	सहायक प्रोफेसर (अवकाश पर)
18.	डा. सुकन्या बोस	सहायक प्रोफेसर
19.	डा. अमय सप्रे	सहायक प्रोफेसर (20.7.2018 को कार्यभार ग्रहण)
20.	डा. सुरांजली टंडन	सहायक प्रोफेसर (16.7.2018 को कार्यभार ग्रहण)
21.	डॉ सताद्रु सिकदर	सहायक प्रोफेसर
22.	डॉ रंजन कुमार मोहंती	सहायक प्रोफेसर
23.	डा. श्रुति त्रिपाठी	अर्थशास्त्री
24.	डा. दिनेश कुमार नायक	अर्थशास्त्री
25.	डा. ए.श्री हरी नायुडु	अर्थशास्त्री
26.	डा. भाबेश हजारिका	अर्थशास्त्री
27.	सुश्री अमनदीप कौर	अर्थशास्त्री

प्रशासनिक स्टाफ

1.	सुश्री अलका माट्टा	सचिव
2.	श्री अशोक कुमार खण्डूडी	वरिष्ठ प्रसाशनिक अधिकारी
3.	श्री प्रवीण कुमार	निजी सचिव
4.	श्री विक्रम सिंह चौहान	निदेशक के निजी सचिव
5.	श्री परविंदर कपूर	निजी सचिव
6.	श्री बी एस रावत	लेखा अधिकारी
7.	सुश्री प्रोमिला राजवंशी	आशुलिपिक ग्रेड.।
8.	सुश्री कविता इस्सर	आशुलिपिक ग्रेड.।
9.	श्री अनुरोध शर्मा	आशुलिपिक ग्रेड.।
10.	श्री दर्शन सिंह पंवार	आशुलिपिक ग्रेड.॥ (01.01.2020 से प्रतिनियुक्ति पर)
11.	सुश्री अमिता मनहास	आशुलिपिक ग्रेड.॥
12.	श्री कपिल कुमार आहूजा	आशुलिपिक ग्रेड.॥
13.	सुश्री उषा माथुर	आशुलिपिक ग्रेड.॥
14.	सुश्री रूचि आनन्द	सहायक
15.	श्री वसीम अहमद	स्टैनो-टाइपिस्ट
16.	सुश्री दीपिका राय	सहायक
17.	श्री शुभम कुमार वर्मा	लिपिक (वित्त)
18.	सुश्री मोनिका माथुर	स्वागत अधिकारी एवं टेलीफोन आपरेटर
19.	श्री राजू	ड्राइवर
20.	श्री परशु राम तिवारी	ड्राइवर
21.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	फोटोकापी आपरेटर
22.	श्री के.एन. मिश्रा	होस्टल अटैंडेंट
23.	श्री किशन सिंह	होस्टल अटैंडेंट
24.	श्री शिव बहादुर	माली
25.	श्री शिव प्रताप	माली
26.	श्री रमेश कुमार	माली
27.	सुश्री कमला तिवारी	मैसेंजर
28.	श्री हरीश चन्द	मैसेंजर
29.	श्री अजय कुमार	मैसेंजर
30.	श्री मुकेश	मैसेंजर
31.	श्री राजेन्द्र कुमार	मैसेंजर
32.	श्री बिशम्बर पांडे	वॉचमैन
33.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	वॉचमैन

34.	सुश्री समरीन बद्र	संपादक (31/05/2019 को कार्यमुक्त)
35.	सुश्री इंद्रा हसीजा	सहायक (31.03.2020 को सेवानिवृत्त)
36.	श्री जे एस रावत	कार्यकारी अधिकारी (31.01.2020 को सेवानिवृत्त)

कमप्यूटर यूनिट

1.	श्री एन.के. सिंह	ईडीपी प्रबंधक
2.	श्री जगदीश आर्य	अनुसंधान अधिकारी (संचार) 31.05.2019 को सेवानिवृत्त
3.	श्री रोबी थामस	अधीक्षक

पुस्तकालय स्टाफ

1.	सुश्री सारिका गौड़	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2.	श्री पी.सी.उपाध्याय	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
3.	सुश्री मन्जू ठाकुर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
4.	सुश्री आजाद कौर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
5.	श्री राजन ढाका	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचारक
6.	श्री नदीम अली	कनिष्ठ पुस्तकालय परिचारक
7.	श्री पूर्ण सिंह	मैसेंजर
1.	डा. मौहम्मद आसिफ मुस्तफा खान	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (26/12/2019 को कार्यमुक्त)
2.	श्री शिवा चिदाम्बरम	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (29/01/2020 को कार्यमुक्त)

अकादमिक स्टाफ – संविदारत

1.	श्री डी.पी.सेनगुप्ता	फैल्लो-I (31.12.2019 को कार्यमुक्त)
2.	श्री शुभो राय	फैल्लो-I (12.09.2019 को कार्यमुक्त)
3.	डा. राधिका पांडे	फैल्लो-I
4.	श्री प्रमोद सिन्हा	फैल्लो-II
5.	सुश्री रचना शर्मा	फैल्लो-II
6.	श्री जय देव दुबे	फैल्लो-II
7.	सुश्री शिवांगी त्यागी	अनुसंधान फैल्लो (22.05.2019 को कार्यमुक्त)
8.	सुश्री स्मृति परिशरा	फैल्लो-II (20.03.2020 को कार्यमुक्त)

9.	श्री नेल्सन चौधरी	अनुसंधान फैल्लो (01.08.2019 को कार्यमुक्त)
10.	श्री दीवान चन्द	फैल्लो-II
11.	सुश्री शालिनी मित्तल	अनुसंधान फैल्लो (30.04.2019 को कार्यमुक्त)
12.	श्री देवेन्द्र डामले	अनुसंधान फैल्लो
13.	श्री अशिम कपूर	अनुसंधान फैल्लो
14.	सुश्री फैजा रहमान	अनुसंधान फैल्लो
15.	सुश्री हरलीन कौर	अनुसंधान फैल्लो
16.	श्री प्रतीक दत्ता	फैल्लो-II (06.05.2019 को कार्यमुक्त)
17.	श्री मयंक मिश्रा	अनुसंधान फैल्लो (31.12.2019 को कार्यमुक्त)
18.	श्री विशाल त्रेहान	अनुसंधान फैल्लो
19.	श्री सुदिप्तो बैनर्जी	अनुसंधान फैल्लो
20.	सुश्री बिदिशा मंडल	अनुसंधान फैल्लो
21.	सुश्री भाव्या शर्मा	अनुसंधान फैल्लो (09.07.2019 को कार्यमुक्त)
22.	सुश्री तानवी ब्राह्मे	अनुसंधान फैल्लो
23.	सुश्री कनिका गुप्ता	अनुसंधान फैल्लो
24.	श्री प्रीतम दत्ता	फैल्लो-II
25.	सुश्री प्रिया	अनुसंधान फैल्लो
26.	श्री राकेश कुमार सिंह	अनुसंधान फैल्लो (30.06.2019 को कार्यमुक्त)
27.	श्री अशोक भाक्कर	अनुसंधान फैल्लो (30.09.2019 को कार्यमुक्त)
28.	सुश्री प्रिया केशरी	अनुसंधान फैल्लो (30.06.2019 को कार्यमुक्त)
29.	सुश्री साक्षी सतीजा	अनुसंधान फैल्लो (31.07.2019 को कार्यमुक्त)
30.	सुश्री राशि मित्तल	अनुसंधान फैल्लो
31.	सुश्री डी.प्रियदर्शिनी	फैल्लो-II
32.	सुश्री अमृता पिल्लै	अनुसंधान फैल्लो
33.	श्री अनमोल राठौड़	अनुसंधान फैल्लो
34.	श्री रघुनाथ शेषाद्री	अनुसंधान फैल्लो
35.	श्री सुभामोय चक्रबर्ती	अनुसंधान फैल्लो (31.12.2019 को कार्यमुक्त)
36.	श्री ऋषभ बेली	फैल्लो-II
37.	श्री सारंग मोहारिर	अनुसंधान फैल्लो
38.	सुश्री मनप्रीत कौर	अनुसंधान फैल्लो
39.	सुश्री सवरीन कौर नन्दा	अनुसंधान फैल्लो
40.	श्री रत्नेश	वरिष्ठ फैल्लो
41.	डॉ. रीता पांडे	वरिष्ठ फैल्लो
42.	सुश्री मधुर मेहता	अनुसंधान फैल्लो
43.	मोहम्मद अजरूद्दीन खान	अनुसंधान फैल्लो

44.	श्री राहुल चक्रवर्ती	अनुसंधान फैल्लो
45.	सुश्री रूजेल श्रेष्ठ	अनुसंधान फैल्लो
46.	श्री शुभम गुप्ता	अनुसंधान फैल्लो (17.06.2019 को कार्यमुक्त)
47.	श्री अभिषेक	अनुसंधान फैल्लो (31.01.2020 को कार्यमुक्त)
48.	सुश्री सुनेत्रा घटक	अनुसंधान फैल्लो
49.	श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव	अनुसंधान फैल्लो
50.	सुश्री श्रृष्टि शर्मा	अनुसंधान फैल्लो
51.	श्री रोहित दत्ता	अनुसंधान फैल्लो
52.	सुश्री मेधा राजू	अनुसंधान फैल्लो
53.	श्री कार्तिक सुरेश	अनुसंधान फैल्लो
54.	सुश्री मोमिता दास	अनुसंधान फैल्लो (20.01.2020 को कार्यमुक्त)
55.	सुश्री मानसी बेरा	अनुसंधान फैल्लो (01.10.2019 को कार्यमुक्त)
56.	सुश्री रजनी पांडे	अनुसंधान फैल्लो (19.7.2019 को शामिल)
57.	श्री वरुण सेन बहल	अनुसंधान फैल्लो (1.4.2019 से 29.02.2020)
58.	सुश्री श्रेया सुब्रमण्यन	अनुसंधान फैल्लो (10.4.2019 से 4.9.2019)
59.	श्री तुषार आनंद	अनुसंधान फैल्लो
60.	सुश्री त्रिशे गोयल	स्वतंत्र परामर्शदाता
61.	श्री पुनीत मिश्रा	अनुसंधान फैल्लो (04.04.2019 को कार्यमुक्त)
62.	सुश्री कुसन विश्वास	अनुसंधान फैल्लो (04.07.2019 को शामिल हुए)
63.	सुश्री जेनेट फरीदा जैकब	अनुसंधान फैल्लो (19 में शामिल) .07.1019)
64.	सुश्री सबरनी चौधरी	अनुसंधान फैल्लो (24.7.2019 को शामिल हुए)
65.	सुश्री वंदना टी आर	अनुसंधान फैल्लो (4.8.2020 को कार्यमुक्त)
66.	श्री नीरव पंड्या	स्वतंत्र विधिक परामर्शदाता
67.	सुश्री हर्षिता कंबोज	प्रशिक्षु (5.8.2019 को कार्यमुक्त)
68.	सुश्री अनिन्दिता घोष	अनुसंधान फैल्लो (19.8.2019 को शामिल हुए)
69.	सुश्री गुनतास कौर उप्पल	26.8.2019 कोरिसर्च फेलो (शामिल हुए)
70.	सुश्री वंशी शर्मा	अनुसंधान फैल्लो (28.8.2019 को शामिल हुए)
71.	श्री मयंक जैन	अनुसंधान फैल्लो (23.9.2019 को शामिल हुए)
72.	सुश्री संपत कौर	अनुसंधान फैल्लो (30.10.2019 को शामिल हुए)
73.	सुश्री विभा कुमारी	अनुसंधान फैल्लो (1.11.2019 को शामिल हुई)
74.	सुश्री शिवानी बडोला	अनुसंधान फैल्लो (1.11.2019 को शामिल हुए)
75.	श्री गणेश गोपालकृष्णन	अनुसंधान फैल्लो (4.11.2019 को शामिल हुए)
76.	सुश्री स्मृति मेहरा	अनुसंधान फैल्लो (3.12.2019 को शामिल हुए)
77.	श्री प्रियन्ता घोष	अनुसंधान फैल्लो (10.12.2019 को शामिल हुए)
78.	सुश्री मिथिला ए सारा	अनुसंधान फैल्लो (13.01.2020 में शामिल हुए)

79.	सुश्री अमानी बशी	अनुसंधान फैल्लो (3.2.2020 में शामिल हुए)
80.	श्री मनोहर बोड़ा	अनुसंधान फैल्लो (3.2.2020 पर शामिल हुए)
81.	सुश्री कनिका कुमार	अनुसंधान फैल्लो (18.02.2020 को शामिल हुए)
82.	सुश्री मौलश्री सिंह	अनुसंधान फैल्लो (05.03.2020 में शामिल हुए)
83.	सुश्री अंशु शुक्ला	अनुसंधान फैल्लो (05.03.2020 को शामिल हुए)
84.	श्री उत्कर्ष	अनुसंधान फैल्लो (09.03.2020 में शामिल हुए)
85.	सुश्री। आयुषी जैन	अनुसंधान फैल्लो (12.03.2020 को शामिल हुए)
86.	श्री विराज जोशी	अनुसंधान फैल्लो
87.	सुश्री अनुजा मल्होत्रा	अनुसंधान फैल्लो (03.06.2019 को शामिल हुए)
88.	सुश्री गरिमा जसूजा	अनुसंधान फैल्लो (03.06.2019 को शामिल हुए)
89.	सुश्री नमिता गोयल	अनुसंधान फैल्लो (03.06.2019 को शामिल हुई)

प्रशासनिक स्टाफ

संविदारत

1.	सुश्री लता बालासुब्रामनियन	कार्यक्रम सहायक
2.	श्री कौशल पयाल	सलाहकार (प्रशासन)
3.	श्री कुलदीप सिंह	डेटा एंटरी आपरेटर
4.	सुश्री दीपिका गुप्ता	सलाहकार (लेखा)
5.	श्री हरि शंकर गुप्ता	सलाहकार (प्रशासन) (19.11.2019 को शामिल हुए)
6.	श्री मनेश वी एम	आईटी (सलाहकार) (31.7.2019 को शामिल हुए)
7.	श्री सुरेश कुमार	सलाहकार (कार्यक्रम सहायक)(10.02.2020 को शामिल हुए)
8.	श्री आर.मनी	सलाहकार (प्रशासन) (27.9.2019 को कार्यमुक्त)
9.	सुश्री मीना	डाटा एंट्री ऑपरेटर

अनुलंग्नक –VIII प्रायोजकों, कारपोरेट, स्थाई एवं साधारण सदस्यों की सूची (दिनांक *31.3.2020* तक)

क. प्रायोजक सदस्य

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. कर्नाटक
5. केरल
6. महाराष्ट्र
7. उड़ीसा
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल

अन्य

1. एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
2. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
3. इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक

ख. स्थाई सदस्य – राज्य / संघ शासित प्रदेश

1. अरूणाचल प्रदेश
2. गोवा, दमन एवं दीव
3. हिमाचल प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. मेघालय
6. मणिपुर
7. नागालैंड
8. हरियाणा

ग. साधारण सदस्य – राज्य / संघ शासित प्रदेश

1. त्रिपुरा

अन्य

1. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

अनुलंग्नक – IX वित्त एवं लेखा

स्थान के लेखापरीक्षक मैसर्स अनिश आशीष एंड कंपनी सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत लेखापरीक्षक संस्थान के वित्तीय वर्ष 2019-20 से सम्बंधित लेखा विवरण

अनिश आशीष एंड कंपनी

के -28, तीसरी मंजिल, सरिता विहार, नई दिल्ली -110076
हैंडसेट: + 91-9818395893, + 91-9810261432
लैंडलाइन: 011-29942700, 011-41033026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान जनरल बॉडी के सभी सदस्य,

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

मत

हमारे द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (इकाई) के अंतर्गत पंजीकृत विनय के वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार संक्षेप सहित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां शामिल हैं।

हमारे मतानुसार, प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2020 की यथास्थिति को इकाई की वित्तीय स्थिति एवं वर्ष के दौरान इसके वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति होती है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

मत का आधार

हमारे द्वारा किया गया लेखापरीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसरण में किया गया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत उल्लेख हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में प्रस्तुत लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में वर्णित है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसरण में हम इकाई से स्वतंत्र हैं तथा हमारे द्वारा अपने अन्य आचार उत्तरदायित्वों का निर्वाह आचार संहिता के अनुरूप किया गया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षण प्रमाण हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन एवं शासी प्रभारियों के उत्तरदायित्व

भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई के इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने के प्रति प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सत्य एवं स्वच्छ स्वरूप में एवं किसी भी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्याकथन, किसी जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनकी प्रस्तुति करने से संबद्ध डिजाइन, आंतरिक नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण किया जाना शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान प्रबंधन सोसायटी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने,गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से संबंद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा इकाईको बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारी ही इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी रखना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं-:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्य परक हों । पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठगांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं ।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना ।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए इकाई की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसीप्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखा परीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परिक्षा प्रमाणों पर

आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम इकाईकी प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित इंडएएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंडएएस वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को हमने उन मामलों का विवरण भी दिया है जिनका समेकन हमारे द्वारा स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया गया था तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

अन्य अपेक्षाओं की रिपोर्ट

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने, वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

(ii) हमारे मतानुसार, इकाई द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण विधि अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है तथा ऐसा इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है; तथा

(iii) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

अनीश आशीष एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर 002535N

---ह./----
आशीष गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या- 503829

यूडीआईएन: 20503829AAAABL3105
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 नवंबर 2020

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 को वित्तीय स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

	अनुसूची #	31.3.2020 की स्थिति	31.3.2019 की स्थिति
कोरप्स/पूंजी निधि तथा देनदारियां			
कोरप्स/पूंजी निधि	1	126,287,325	124,980,947
आरक्षित तथा अधिशेष	2	178,810,714	162,810,714
आस्थगित आय	3	16,887,656	17,442,303
धर्मादा/विनिश्चित निधियां	4	326,361,894	306,795,449
वर्तमान देनदारियां तथा प्रावधान	5	140,739,109	148,817,557
जोड़		**789,086,698**	**760,846,970**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	6	65,240,074	62,226,986
निवेश–धर्मादा/विनिश्चित निधियां	7	353,116,215	340,050,187
निवेश–अन्य	8	210,626,008	161,988,748
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	9	160,104,401	196,581,049
जोड़		**789,086,698**	**760,846,970**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखों के संबंध में टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग हैं ।

कृते राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
बी एस रावत	अलका माट्टा	डॉ पिनाकी चक्रबर्ती	डॉ ऊर्जित पटेल
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अन्नीश आशीष एंड कं०

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002535एन

(आशीष गुप्ता)

सदस्य

सदस्यता सं.503829

यूडीआईएन:20503829AAAABL3105

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 18 नवंबर 2020

राष्टीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

धनराशि रूपए में

	अनुसूची #	31.3.2020 की स्थिति	31.3.2019 की स्थिति
आय			
केंदीय और राज्य सरकारों से अनुदान	10	98,058,997	88,645,450
अकादमिक कार्यकलापों से आय	11	169,025,136	121,679,514
अर्जित ब्याज	12	17,772,546	15,202,870
अन्य आय	13	23,890,633	18,146,342
जोड़		**308,747,312**	**243,674,176**
व्यय			
स्थापना व्यय	14	85,379,889	68,727,375
अकादमिक कार्यकलापों पर व्यय	15	162,794,356	120,371,499
प्रशासनिक व्यय	16	39,620,361	41,323,647
प्रकाशन स्टाक में कमी			53,504
मूल्यह्रास	6	3,365,313	3,111,531
जोड़		**291,159,919**	**233,587,556**
शेष वर्ष के संबंध में व्यय की तुलना में आय की अधिकता के नाते शेष		17,587,393	10,086,620
घटा : पिछली अवधि की मदें		281,015	9,942
अपवाद मद – वेतन बकाया		-	1,209,750.00
कोर्ट केस सेटलमेंट में दी गई राशि (अनुसूची 18 के नोट सं. 3 का संदर्भ देखें)			
व्यय की तुलना में आय की अधिकता		**17,306,378**	**8,866,928**
घटा : अतिरिक्त देनदारी के लिए अंतरित राशि		9,000,000	4,000,000
घटा : साधारण रिजर्व के लिए अंतरित राशि		7,000,000	3,000,000
कोरप्स/पूंजी निधि में ले जाया गया अधिशेष के नाते शेष		**1,306,378**	**1,866,928**
महत्वपूर्ण रेखांकन नीतियां	17		
लेखों के संबंध में टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग हैं ।

कृते राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
बी एस रावत	अलका माट्टा	डॉ पिनाकी चक्रबर्ती	डॉ ऊर्जित पटेल
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अनीश आशीष एंड कं०

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002535एन

(आशीष गुप्ता)

सदस्य

सदस्यता सं. 503829

यूडीआईएन: 20503829AAAABL3105

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 18 नवंबर 2020

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र का भाग है

धनराशि रूपए में

		31.3.2020 की स्थिति		31.3.2019 की स्थिति
अनुसूची 1 . कोरप्स/पूंजी निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	124,980,947.00		123,114,019.00	
जमा : आय और व्यय खाते से अंतरित अधिशेष	1,306,378.00		1,866,928.00	
		126,287,325		124,980,947
जोड़		**126,287,325**		**124,980,947**
अनुसूची-2 : रिजर्व और अधिशेष				
क. अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	62,189,863		58,189,863	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	9,000,000		4,000,000	
		71,189,863		62,189,863
ख. सामान्य रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	100,120,851		97,120,851	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	7,000,000		3,000,000	
		107,120,851		100,120,851
ग. : मृत कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायतार्थ रिजर्व के लिए अंतरित राशि				
पिछले खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि		500,000		500,000
जोड़		**178,810,714**		**162,810,714**
अनुसूची-3 : आस्थगित आय				
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए इमारत के				
निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार से अनुदान				
पिछले खाते के अनुसार	16,758,416		17,127,099	
घटा : ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्ह्रास के समकक्ष राशि				
आय और व्यय खाते को अंतरित	313,879		368,683	
		16,444,537.00		16,758,416.00
पूंजी परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रायोजकों से अनुदान				
पिछले खाते के अनुसार	683,887		655,877	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-		496,034	
घटा : आय और व्यय खाते को अंतरित ऐसी परिसंपत्तियों पर				
मूल्यह्रास के समकक्ष राशि	240,768		468,024	
		443,119.00		683,887.00
जोड़		**16,887,656.00**		**17,442,303.00**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र् का भाग है

अनुसूची-4 : विनिश्चित/धर्मादा निधियां

धनराशि रूपयों में

विवरण	फोर्ड फाउंडेशन धर्मादा निधि	सरकारी धर्मादा निधि	भारतीय रिजर्व बैंक धर्मादा निधि	वैज्ञानिक अनुसंधान निधि	आजीवन सदस्यता निधि	बिमल बागची अवार्ड निधि	जोखन मौर्य निधि	सरकारी कोरप्स निधि	राजा चेलैय्या वार्षिक व्याख्यान माला और भ्रमणकारी प्रोफेसरशिप निधि	जोड़
प्रारंभिक निधि	6,177,924	10,000,000	40,000,000	727,406	420,000	50,000	29,300	120,000,000	20,000,000	
क- निधियों का प्रारंभ	15,771,976	10,000,000	62,181,642	2,407,072	1,385,480	103,721	66,807	182,502,294	32,376,457	306,795,449
ख-निधि में अभिवृद्धियां										
|-निधि में अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
||-निवेशों से आय	1,172,303	805,834	4,856,638	169,895	100,018	7,487	4,443	13,579,317	2,406,761	23,102,696
जोड. -क+ख	**16,944,279**	**10,805,834**	**67,038,280**	**2,576,967**	**1,485,498**	**111,208**	**71,250**	**196,081,611**	**34,783,218**	**329,898,145**
ग-निधि के उद्रदेश्य हेतु उपयोग/व्यय	1,175,293	805,834	173,022	-	-	-	-	953,622.00	428,480	3,536,251
जोड. - ग	**1,175,293**	**805,834**	**173,022**	-	-	-	-	**953,622**	**428,480**	**3,536,251**
वर्ष के अंत में निवल शेष										
वर्ष का - क+ख+ग	**15,768,986**	**10,000,000**	**66,865,258**	**2,576,967**	**1,485,498**	**111,208**	**71,250**	**195,127,989**	**34,354,738**	**326,361,894**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र का भाग है

धनराशि रूपयों में

	31.3.2020 की स्थिति	31.3.2019 की स्थिति
अनुसूची-5 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
क. वर्तमान देयताएं		
1 वस्तुओं और सेवाओं के लिए विविध लेनदार	5,076,221	4,931,724
2 बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	1,605,066	3,216,978
3 अप्रयुक्त परियोजना अनुदान- (देखें अनुसूची-5 - क)	63,941,814	82,708,900
4 सांविधिक देय	4,892,479	5,678,270
6 अन्य वर्तमान देयताएं	18,731,529	15,147,505
जोड़	**94,247,109**	**111,683,377**
ख. प्रावधान		
1 छुट्टी नकदीकरण	46,492,000	37,134,180
जोड़	**46,492,000**	**37,134,180**
कुल जोड़	**140,739,109**	**148,817,557**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची-5 -क-परियोजना अनुदान

(धनराशि रूपयों में)

क्र०स०	विवरण	1 अप्रैल, 2019 को अप्रयुक्त निधि	1 अप्रैल 2019 को वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति	जोड़	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आय और व्यय/खाते में प्रभारित	प्रयुक्त और आस्थगित आय में प्रभारित	जोड़	31 मार्च, 2020को वसूली योग्य	31 मार्च 2020 तक अप्रयुक्त
1	एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम- आर्थिक कार्य विभाग-वित्त मंत्रलय, भारत सरकारए 2017-18	-	86,879	86,879	-		-	-	-	--
2	आर्थिक वैश्वीकरण एवं आर्थिक विकास -आईसीएसएसआर	177,433	-	-	177,433	-	-	-	.	177,433
3	स्वास्थ्य एवं इसके वितीयन के अनुसंधान एवं नीतियों में सुधार – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	21,839,965	-	20,811,750	42,651,715	32,555,737	-	32,555,737	.	10,095,978
4	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- स्वास्थ्य एवं इसके वितीयन के अनुसंधान एवं नीतियों में सुधार – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	3,214,618	-	1,597,065	4,811,683	-	-	-	-	4,811,683
5	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण – यूएनडीपी	512,553	-	-	512,553	-	-	-	-	512,553
6	डिजीटल लैंड के प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन – एनसीईएआर उप-अनुदान	927,993	-	-	927,993	-	-	-	.	927,993
7	एनआईपीएफपी – ट्राई सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम	42,521	-	-	42,521	-	-	-	-	42,521
8	क्या मौद्रिक नीति से भारत में वितीय स्थिरता संभव है-आईसीएसएसआर	161,916	-	-	161,916	-	-	-	-	161,916
9	भारत में स्वास्थ्य पर लोक वितीयन की पद्धति : आगे की दिशा - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	10,245,072	-	24,422,294	34,667,366	25,582,954	-	25,582,954	-	9,084,412
10	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- भारत में स्वास्थ्य पर लोक वितीयन की पद्धति : आगे की दिशा - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	1,321,120	-	653,136	1,974,256	-	-	-	-	1,974,256
11	लोक वितीयन पर नवोपायों के परिणाम - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	30,937,886	-	29,390,094	60,327,980	53,879,072	-	53,879,072	.	6,448,908
12	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- लोक वितीयन पर नवोपायों के परिणाम - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	3,739,328	-	1,715,322	5,454,650	-	-	-	-	5,454,650
13	डेटा रक्षण के लिए सहमति फ्रेमवर्क में सुधार -ओमिदयार नेटवर्क	248,935	-	-	248,935	127,837	-	127,837	-	121,098
14	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण – यूएनडीपी II	187,710	-	-	187,710	-	-	-	-	187,710
	अग्रेषित जमा राशि	**73,557,050**	**86,879**	**78,676,540**	**152,146,711**	**112,145,600**	-	**112,145,600**	-	**40,001,111**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची-5 -क-परियोजना अनुदान

(धनराशि रूपयों में)

क्र०स०	विवरण	1 अप्रैल, 2019 को अप्रयुक्त निधि	1 अप्रैल 2019 को वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति	जोड़	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आय और व्यय/खाते में प्रभारित	प्रयुक्त और आस्थगित आय में प्रभारित	जोड़	31 मार्च, 2020को वसूली योग्य	31 मार्च 2020 तक अप्रयुक्त
	अग्रेनित शेष राशि	73,557,050	86,879	78,676,540	152,146,711	112,145,600	-	112,145,600	-	40,001,111
15	भारत में डिजीटल परिवर्तन के महत्वपूर्ण एवं नव प्रवाहों पर चर्चा के लिए प्लेटफार्म – फ्रिडरिच नौमान्न स्टिफ्टंग	-	-	1,213,624	1,213,624	1,213,624	-	1,213,624	-	-
16	प्रभावशाली राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना के संगठनात्मक डिजाइन एवं आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसंधान अध्ययन में सहयोग-ओमिदयार नेटवर्क	1,272,367	-	1,524,799	2,797,166	2,757,813	-	2,757,813	-	39,354
17	हिमालय संरक्षण के लिए सहायता सेवा, हिमाचल प्रदेश – यूएनडीपी	2,440,336	-	1,423,125	3,863,461	2,728,374	-	2,728,374	-	1,135,087
18	हिमालय संरक्षण के लिए सहायता सेवा, सिक्किम– यूएनडीपी	2,412,960	-	1,423,125	3,836,085	2,695,502	-	2,695,502	-	1,140,583
19	विशेष क्षेत्र अनुसंधान के विशिष्ट मुद्दों पर गृह मंत्रालय के साथ सहयोग कार्यक्रम के संबंध में डिजीटल लाइब्रेरी/दस्तावेज केन्द्र का निर्माण एवं अनुरक्षण – आईसीएसएसआर	1,495,543	-	-	1,495,543	1,795,237	-	1,795,237	299,694	-
20	एनआईपीएफपी – कारपोरेट कार्य मंत्रालय अनुसंधान कार्यक्रम – कारपोरेट कार्य मंत्रालय	1,530,644	-	1,213,054	2,743,698	2,743,698	-	2,743,698	-	-
21	एनआईपीएफपी-आर्थिक कार्य विभाग अनुसंधान कार्यक्रम आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय,भारत सरकार 2018-19		12,275,877	12,275,877	-	-	-	-	-	-
22	एनआईपीएफपी – ट्राई सहयोग अनुसंधान कार्यक्रम III		816,770	2,648,428	1,831,658	1,831,658		1,831,658	-	-
23	भारत में स्वास्थ्य पर हाउसहोल्ड व्यय भारतीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)के 71वें राउंड के प्राइमरी डेटा का विश्लेषण-विश्व स्वास्थ्य संगठन		482,442	702,645	220,203	220,203		220,203	-	-
24	एनआईपीएफपी-आर्थिक कार्य विभाग अनुसंधान कार्यक्रम आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय,भारत सरकार 2019-20	-	-	5,602,488	5,602,488	10,015,658	-	10,015,658	4,413,170	-
25	भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	-	-	13,991,677	13,991,677	1,501,556		1,501,556		12,490,121
26	अनुदान पर ब्याज विनियोजन- भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल – बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन			114,726	114,726					114,726
	अग्रेषित जमा राशि	**82,708,900**	**13,661,968**	**120,810,108**	**189,857,040**	**139,648,923**	-	**139,648,923**	**4,712,864**	**54,920,982**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची-5 -क-परियोजना अनुदान

(धनराशि रूपयों में)

		1 अप्रैल, 2019 को अप्रयुक्त निधि	1 अप्रैल 2019 को वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति	जोड़	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आय और व्यय/खाते में प्रभारित	प्रयुक्त और आस्थगित आय में प्रभारित	जोड़	31 मार्च, 2020को वसूली योग्य	31 मार्च 2020 तक अप्रयुक्त
	अग्रेनित शेष राशि	82,708,900	13,661,968	120,810,108	189,857,040	139,648,923	-	139,648,923	4,712,864	54,920,982
27	डाटा गवर्नेंस नेटवर्क -आई डी एफ सी संस्थान	-	-	6,066,800	6,066,800	4,377,176	-	4,377,176	-	1,689,624
28	आधार पारिस्थितिकी तंत्र में विकलांग व्यक्ति द्वारा भागीदारी- इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस	-	-	381,800	381,800	653,676	-	653,676	271,876	-
29	भूमि और संपत्ति के अधिकारों पर अनुसंधान का समर्थन- III - ओमिड्यार नेटवर्क	-	-	12,957,461	12,957,461	6,127,482	-	6,127,482	-	6,829,979
30	सरकारी स्कूलों से छात्रों के बहिर्गमन के कारणों की जांच - अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी	-	-	847,000	847,000	688,991	-	688,991	-	158,009
31	डेटा फॉर जस्टिस चैलेंज - वयम नागरिकता फोरम			343,220	343,220	-		-		343,220
	जोड़	**82,708,900**	**13,661,968**	**141,406,389**	**210,453,321**	**151,496,248**	-	**151,496,248**	**4,984,740**	**63,941,814**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची 5–ख–केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अप्रयुक्त अनुदान का अथशेष	(71,876,840)	15,068,610
जमा : वर्ष के दौरान वेतन एवं भत्तों के लिए प्राप्त अनुदान	100,000,000	-
वर्ष के दौरान आवर्ती व्यय के लिए प्राप्त अनुदान	-	-
	28,123,160	**15,068,610**
घटा : वेतन और भत्तों के लिए प्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखे आय के रुप में प्रभारित)	966,858,997	80,945,450
आवर्ती व्ययों का अप्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखे आय के रुप में प्रभारित)	-	6,000,000
योग - अप्रयुक्त अनुदान (प्राप्ति योग्य) अनुदान	**(68,635,837)**	**(71,876,840)**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन-पत्र का भाग है

अनुसूची 6 - अचल परिसंपत्तियां

धनराशि रूपयों में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 19 को	अभिवृद्धियां	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 20 को	1 अप्रैल, 19 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 20 तक	31 मार्च 20 को	31 मार्च 19 को
स्वयं की निधियों में से खरीदी गई अचल परिसंपत्तियां										
1 लीजहोल्ड भूमि	18,809,202	-	-	**18,809,202**	-	-	-	-	**18,809,202**	**18,809,202**
2 भवन	33,295,716	-	-	**33,295,716**	12,202,969	808,797	-	13,011,766	**20,283,950**	21,092,747.00
3 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	27,189,327	3,433,139	-	**30,622,466**	25,735,632	1,316,510	-	27,052,142	**3,570,324**	1,453,695.00
4 कार्यालय उपस्कर	9,682,077	334,087	18,686	**9,997,478**	8,463,706	317,805	18,686	8,762,825	**1,234,653**	1,218,371.00
5 फर्नीचर और सज्जा	11,575,052	53,373	-	**11,628,425**	10,763,055	99,141	-	10,862,196	**766,229**	811,997.00
6 होस्टल,पुस्तकालय,कंप्यूटर तथा सेमिनारकक्ष, फर्नीचर	3,641,172	-	-	**3,641,172**	3,638,162	406	-	3,638,568	**2,604**	3,010.00
7 एयर कंडीशनर और वाटर कूलर	6,552,225	392,948	279,298	**6,665,875**	5,778,225	118,444	279,298	5,617,371	**1,048,504**	774,000.00
8 विद्युत संस्थापन	6,770,494	15,650	-	**6,786,144**	6,148,835	70,768	-	6,219,603	**566,541**	621,659.00
9 वाहन	1,205,374	968,760	749,986	**1,424,148**	1,205,372	78,795	749,986	534,181	**889,967**	2.00
10 बागवानी उपस्कार	109,780	-	-	**109,780**	109,780	-	-	109,780	-	-
जोड़	**118,830,419**	**5,197,957.00**	**1,047,970.00**	**122,980,406**	**74,045,736.00**	**2,810,666.00**	**1,047,970.00**	**75,808,432.00**	**47,171,974.00**	**44,784,683.00**
अचल परिसंपत्तियां -चालू पूंजीगत कार्य										
1 चालू पूंजीगत कार्य	-	1,180,444	-	**1,180,444**	-	-	-	-	1,180,444	
जोड़		**1,180,444**		**1,180,444**					**1,180,444**	-
केंद्रीय सरकार से अनुदान में से अधिप्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1 इमारत-अनुसधान प्रशिक्षण केंद्र	21,289,579	-	-	**21,289,579.00**	4,531,163	313,879	-	4,845,042	16,444,537	16,758,416
2 विद्युतीय, अग्नि-शमन और एचवीएसी कार्य-अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	7,298,350	-	397,500.00	**6,900,850.00**	7,298,350	-	397,500	6,900,850	-	-
जोड़	**28,587,929**	-	**397,500.00**	**28,190,429**	**11,829,513**	**313,879**	**397,500**	**11,745,892**	**16,444,537**	**16,758,416**
विभिन्न प्रायोजको से सरकार से अनुदान में से अधिप्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	4,156,385	-	-	**4,156,385.00**	4,024,368	-	-	4,024,368	132,017	132,017
2 कार्यालय उपस्कर	216,380	-	-	**216,380.00**	180,155	17,445	-	197,600	18,780	36,225
3 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-आईसीएसएसआर	51,500	-	-	**51,500.00**	22,965	16,308	-	39,273	12,227	28,535
							-		-	-
जोड़	**4,424,265**	-	-	**4,424,265**	**4,227,488**	**33,753**	-	**4,261,241**	**163,024**	**196,777**
विदेशी अंशदान निधियों में से प्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	9,880	-	-	**9,880.00**	9,880	-	-	9,880	-	-
2 फर्नीचर और सज्जा	1,523,860	-	-	**1,523,860.00**	1,523,860	-	-	1,523,860	-	-
3 बागवानी उपस्कर	624,980	-	-	**624,980.00**	624,980	-	-	624,980	-	-
जोड़	**2,158,720**	-	-	**2,158,720**	**2,158,720**	-	-	**2,158,720**	-	-
विदेशी अंशदान निधियों में से प्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-आईडीआरसी	154,571	-	-	**154,571.00**	146,842	-	-	146,842	7,729	7,729.00
2 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-बीएमजीएफ-II	478,283	-	-	**478,283.00**	136,748	151,456	-	288,204	190,079	341,535.00
3 कार्यालय उपस्कर-एनसीईएआर-उप ग्राण्ट	22,000	-	-	**22,000.00**	8,257	4,180	-	12,437	9,563	13,743
4 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर-बीएमजीएफ-III	162,250	-	-	**162,250.00**	38,147	51,379	-	89,526	72,724	124,103
जोड़	**817,104**	-	-	**817,104**	**329,994**	**207,015**	-	**537,009**	**280,095**	**487,110**
कुल जोड़	**154,818,437**	**6,378,401**	**1,445,470**	**159,751,368**	**92,591,451**	**3,365,313**	**1,445,470**	**94,511,294**	**65,240,074**	**62,226,986**
पिछला वर्ष	154,586,983	2,209,971	1,978,517	154,818,437	91,458,437	3,111,531	1,978,517	92,591,451	62,226,986	-

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्चए 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियांए जो तुलन.पत्र् का भाग है

धनराशि रूपयों में

		31 मार्च 20 को		31 मार्च 19 को
अनुसूची-7 : निवेश-धर्मादा/विनिश्चित निधियां				
दीर्घावधि निवेश				
सरकारी प्रतिभूतियों में		91,813,079		88,513,079
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		198,930,977		181,766,168
वर्तमान निवेश				
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		62,372,159		69,770,940
जोड़		**353,116,215**		**340,050,187**
अनुसूची-8 : निवेश - अन्य				
दीर्घावधि निवेश				
सरकारी प्रतिभूतियों में		73,323,544		65,010,000
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		122,400,963		92,400,963
वर्तमान निवेश				
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		14,823,002		4,504,363
प्रतिभूति जमा के विरूद्ध अनुसूचित बैंक के पास सावधि जमा		78,499		73,422
जोड़		**210,626,008**		**161,988,748**
अनुसूची-9 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम				
क. **वर्तमान संपत्ति**				
1. इनवेंटरीज				
प्रकाशनों का भंडार		90,937		90,937
2. विविध देनदार		342,198		270,988
3. हाथ में नकद शेष -चेक/अप्रदाय सहित		27,308		40,054
4. बैंक शेष				
बचत खाता-अनुसूचित बैंकों के पास				
केनरा बैंक, जीत सिंह मार्ग, खाता संख्या 1484101001555	20,867,497		17,561,482	
केनरा बैंक, जीत सिंह मार्ग, खाता संख्या 1484106026094	74,281		4,966	
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू खाता सं. 10596549875	17,694		17,106	
अनुसूचित बैंकों के पास-चालू खाता				
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू, एफसी खाता सं. 10596547368	21,327,810		19,153,495	
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू चालू खाता सं. 10596547335	43,307		43,956	
		42,330,589		36,781,005
ख ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां,				
1. अग्रिम व अन्य राशि–नकद अथवा समान अथवा				
ख. प्राप्त होने वाली कीमत के रूप में वसूली योग्य:				
क. स्टाफ को उत्सव अग्रिम	-		22,900	
ख. पूर्वप्रदत्त व्यय	3,944,043		9,364,173	
ग. व्यय के लिए स्टाफ को अग्रिम	310,554		555,364	
घ. अन्य अग्रिम	326,712		2,126,145	
ड.. प्रतिभूति जमा	588,719		772,788	
छ. इनपुट कर क्रेडिट	147,107		44,980	
		5,317,135		12,886,350
2. उपार्जित आय				
क. विनिश्चित/धर्मादा निधियों में निवेशों पर आय	4,132,180		2,868,603	
ख. निवेशों पर - अन्य	2,210,646		1,522,175	
ग. राज्य सरकार अनुदान	100,000		500,000	
घ. पाठ्यक्रम कार्यक्रम और परियोजना आय	5,687,387		11,880,645	
ड. परियोजना अनुदान (अनुसूची 5 (क) देखें)	4,984,740		13,661,968	
च. केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान (अनुसूची 5 (ख) देखें)	68,735,837		71,876,840	
	_	85,850,790	_	102,310,231
3. प्राप्ति योग्य दावे				
क आय कर वसूली योग्य		26,145,444		44,201,484
जोड़		**160,104,401**		**196,581,049**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो आय और व्यय खाते का भाग हैं

धनराशि रूपयों में

	31 मार्च, 2020 की स्थिति	31 मार्च, 2019 की स्थिति
अनुसूची-10 : केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान		
क. केंद्रीय सरकार से अनुदान		
वेतन अनुदान - देखें अनुसूची 5-ख	96,858,997	80,945,450
आवर्ती अनुदान-देखें अनुसूची 5-ख	-	6,000,000
जोड़-क	**96,858,997**	**86,945,450**
ख. राज्य सरकारों से अनुदान		
सामान्य सहायता अनुदान		
उड़ीसा सरकार	500,000	500,000
महाराष्ट्र सरकार	100,000	100,000
तमिलनाडु सरकार	100,000	100,000
नागालैंड सरकार	-	500,000
गुजरात सरकार	500,000	500,000
जोड़-ख	**1,200,000**	**1,700,000**
कुल जोड़-क+ख	**98,058,997**	**88,645,450**
अनुसूची-11 : अकादमिक कार्यकलापों से आय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय	17,528,888	15,116,052
प्रयुक्त सीमा तक परियोजना अनुदान - संदर्भ अनुसूची 5-क	151,496,248	106,563,462
जोड़	**169,025,136**	**121,679,514**
अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज		
बैंको/वित्तीय संस्थाओं से अर्जित ब्याज		
अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा पर	1,692,727	1,992,188
अनुसूचित बैंकों के पास बचत खातों पर	692,474	483,922
सरकारी व अन्य प्रतिभूतियों पर	12,601,128	12,648,977
आयकर वापसी पर ब्याज	2,704,397	-
अन्य ब्याज	81,820	77,783
जोड	**17,772,546**	**15,202,870**
अनुसूची-13 : अन्य आय		
प्रकाशनों की बिक्री	200	-
वसूलियां	22,566,398	16,734,897
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ	310,375	71,319
विविध आय	191,810	115,824
मकान किराया वसूलियां	166,678	175,837
रा.जो.वि.नी.सं. स्टाफ से प्राप्त परामर्श फीस	15,254	66,630
देनदारियां बट्टे खाते डाली गईं	-	83,717
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	85,271	61,411
आस्थगित आय से अंतरित राशि (अनुसूची 3 देखें)	554,647	836,707
जोड	**23,890,633**	**18,146,342**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो आय और व्यय खाते का भाग हैं

धनराशि रूपयों में

	31 मार्च, 2020 की स्थिति	31 मार्च, 2019 की स्थिति
अनुसूची-14 : स्थापना व्यय		
वेतन और भत्ते	88,530,623	73,618,153
बोनस	262,504	276,320
पीएफ व पेंशन निधि के लिए अंशदान	8,564,658	7,543,158
उपदान	6,295,114	5,087,313
छुट्टी वेतन	11,499,650	7,679,191
स्टाफ लाभ तथा कल्याण	4,166,366	4,601,304
ईडीएलआई तथा प्रशासनिक प्रभार	188,192	179,490
परामर्श फीस	754,647	1,339,918
	120,261,754	**100,324,847**
घटा : अकादमिक कार्यकलापों को प्रभारित	34,881,865	31,597,472
जोड़	**85,379,889**	**68,727,375**
अनुसूची-15 : अकादमिक कार्यकलापों पर व्यय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना खर्च	11,298,108	13,808,037
परियोजना अनुदान का उपयोग-अनुसूची 5-क देखें	151,496,248	106,563,462
जोड़	**162,794,356**	**120,371,499**
अनुसूची-16 : प्रशासनिक व्यय		
यात्र और सवारी	1,000,766	1,861,234
दरें और कर	1,201,179	2,147,019
विद्युत प्रभार	8,079,869	7,701,241
जल प्रभार	1,112,808	940,124
मुद्रण और लेखन सामग्री	784,342	955,218
टेलीफोन और डाकखर्च	1,451,538	1,525,392
मरम्मत और अनुरक्षण	14,490,865	12,531,239
कार संचालन और अनुरक्षण	262,459	373,483
आडिट फीस	193,718	332,462
ऑडिट फीस-आंतरिक	124,797	142,691
आडिट फीस-पीएफ ट्रस्ट	22,564	18,000
आडिट फीस-उपदान ट्रस्ट	20,000	24,624
विविध व्यय	331,110	381,861
विधिक व्यय	422,876	494,295
विज्ञापन पर व्यय	276,922	186,733
पीएफ की परिपक्वता/उपदान न्यास निवेश पर हानि	95,850	937,167
ब्याज की कमी और अन्य व्यय (पीएफ निधि)	880,766	246,378
पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	8,395,238	9,370,251
प्रकाशनों की लागत	122,460	317,244
बैठक और सेमिनार	226,386	213,406
साधारण/शासी निकाय बैठक	149,949	118,643
बीमा व्यय	139,169	113,379
वसूली योग्य-बट्टे खाते डाला गया	442,500	958,746
व्यावसायिक फीस	198,064	157,256
25 वीं वर्षगांठ पर व्यय	-	90,000
	40,426,195	42,138,086
घटा : धर्मादा/विनिश्चित निधियों के लिए प्रभारित	805,834	814,439
जोड़	**39,620,361**	**41,323,647**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची17–लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों का निर्माण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक अभिसमय के अधीन उपचय आधार पर और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखाकरण मानकों, यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, के अनुसार किया जाता है। सामान्य सदस्यता शुल्क को नकद आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

2. वित्तीय विवरणिकाएं तैयार करने के लिए ऐसे प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों की अपेक्षा होती है जिनसे प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों,राजस्व और व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित होती है। यद्यपि ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी भिन्नताओं को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें परिणाम परिणत होते हैं।

3. दीर्घावधिक निवेशों को ह्रास, अस्थाई के अलावा, के समायोजन के पश्चात उनकी वहन लागत पर अग्रेनित किया जाता है। चालू निवेश लागत और उचित मूल्य में से न्यूनतर के आधार पर अग्रेनित किए जाते हैं। निवेशों की लागत में, यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रीमियम सहित सभी अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

   भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई चेयर ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए दी गई कायिक निधि में से प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों, जब इन्हें प्रीमियम पर अधिग्रहीत किया गया हो, का उल्लेख आरबीआई और संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार आरबीआई काय निधि से उपार्जित ब्याज आय के सापेक्ष किया गया है।

4. प्रकाशनों की मालसूची का मूल्यांकन लागत पर किया गया है। लागत का निर्धारण एफआईएफओ आधार पर किया गया है। दस वर्ष से अधिक पुराने प्रकाशन और परियोजना अनुदानों से वित्तपोषित प्रकाशनों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है।

5. अचल परिसम्पत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया गया है जिसमें अधिग्रहण से संबंधित आनुशंगिक और प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल हैं। अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया गया है।

6. प्रबंधन द्वारा पॉच प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य पर विचार के पश्चात परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर सरल रेखा पद्धति से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। परिसम्पत्तियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है:-

परिसम्पति विवरण	**उपयोज्यता काल**
भवन	60वर्ष
डेटा संसाधन उपकरण	3वर्ष
कार्यालय उपकरण	5वर्ष
फर्निचर एवं जुड़नार	10वर्ष
होस्टल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	8वर्ष
एयर कंडीनर एवं वाटर कूलर	10वर्ष
विद्युत संस्थापनाएं	10वर्ष
वाहन	8वर्ष
बागवानी उपकरण	5वर्ष

7. प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से किसी परिसम्पत्ति का क्षय होने के संबंध में आकलन किए जाते हैं। ऐसे क्षय के किसी संकेत के मामले में, प्रबंधन परिसम्पत्ति द्वारा वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी वाहित राशि से कम है, तो परिसम्पत्ति की वाहित राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और अंतर को अक्षमता हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

8. पुस्तकालय के लिए खरीदी गई पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीद के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. अल्पावधिक कर्मचारी लाभों को आय एवं व्यय के लेखे में छूट न दी गई राशि के व्यय के रूप में सेवाएं प्रदान किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया गया है।

10. रोजगार के बाद के और अन्य दीर्घावधिक लाभों को उस वर्ष के आय व्यय लेखे में छूट न दी गई राशि पर हुए व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए निर्धारित देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर स्वीकृति दी गई है। रोजगार-पश्चात और अन्य दीर्घावधिक लाभों के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को सामान्यतः संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखा पुस्तिकाओं में लेखाबद्ध किया गया है।

12. चिह्नित/वृत्ति निधियों से निवेशों पर आय का उपयोग निधियों के विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है। अप्रयुक्त राशि के शेष को, यदि कोई हो, संबंधित चिह्नित/वृत्ति निधियों में रखा गया है।

13. विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभिक तौर पर देनदारी माना गया है और वर्ष के दौरान उपयोगिता के अुनसार समायोजित किया गया है। अनुदानों को, मूल्यह्रास के योग्य परिसम्पत्तियों के लिए प्रयुक्त सीमा तक, आस्थगित आय माना गया है और इन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक आधार पर आय और व्यय लेखे में स्वीकृति दी गई है। राजस्व व्ययों के लिए प्रयुक्त सीमा तक वेतनों और परियोजना अनुदानों को वर्ष की आय माना गया है। आवर्ती व्ययों के लिए अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

14. प्रावधानों को वहां स्वीकृति दी गई है जब विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देनदारी हो तथा जिसके लिए यह संभव हो कि देनदारी के समाधान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा और विश्वसनीय प्राक्कलन संभव हो सकेगा। देनदारी के समाधान के लिए अपेक्षित प्रावधानों की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और जहां देनदारी के चालू सर्वोत्तम प्राक्कलन के लिए आवश्यक हो, समायोजित किया गया है।

15. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया गया है जब एक संभावित देनदारी या वर्तमान देनदारी हो जिसके लिए संसाधनों का वह बर्हिप्रवाह अपेक्षित हो सकता हो, जो संभावित रूप से अपेक्षित नहीं है। उस वर्तमान देनदारी के संबंध में भी प्रकटीकरण किया जाएगा जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित हो, जहां संबंधित बर्हिप्रवाह का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जाना संभव न हो।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 – लेखांकन नोट

1. आकस्मिक देयताएं / परिसम्पतियां

संस्थान के विरूद्ध एवं संस्थान द्वारा दायर किए न्यायिक मामलों के संबंध में देयता : राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं: शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)

3. केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बैंच, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 4 मार्च, 2011 तथा 14 दिसम्बर, 2018 के क्रमश: न्यायनिर्णय एवं आदेश के अनुसरण के परिणामस्वरूप श्रीमती सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी को पूर्व प्रभाव से केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बैंच के न्यायनिर्णय एवं आदेश में उल्लिखित वेतनमान / वित्तीय उन्नयन प्रदान किए गए थे जिससे उनकी देयताओं के प्रति उन्हें 12,09,750 रूपए की राशि का भुगतान किया गया था।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संज्ञान की गई एवं एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के खंड 22 में अनुपालन में संस्थान में उपलब्ध देयताएं:

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को चुकता न की गई मूल राशि	659126	841677
वर्ष के दौरान ब्याज उपचय की राशि तथा वर्ष के अंत में चुकता न की गई बकाया राशि	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदात्ता को खंड 16 के उपबंधों के अनुसार भुगतान की राशि के साथ चुकता किए गए ब्याज की राशि	-	-
भुगतान किए जाने में देरी की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता किया गया है) जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना चुकता किया गया है।	-	-

वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उससे संबंधित चुकता न किया गया बकाया ब्याज	-	-
आगामी वर्षों में भुगतान न किए जाने के कारण देय बढ़त ब्याज की राशि जो वास्तविक भुगतान किए जाने की तिथि तक के लिए खंड 23 के अंतर्गत कटौती व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को चुकता की जानी है।	-	-

5. संस्थान के प्रबंधन के मतानुसार, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कारोबार के सामान्य क्रम में कम से उस राशि के समान है जिस पर इनका उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो और सभी ज्ञात देयताओं के लए प्रावधान वित्तीय विवरणिका में किया गया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल 2,61,45,444 रूपए के वसूली योग्य आयकर में से 1,37,33,202 रूपए की राशि आयकर वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व के आकलन वर्षों से संबंधित है।

6. वृत्ति/चिह्नित निधियों के निवेशों में 5,82,49,920 रूपए के उद्धृत निवेश और 23,86,30,989 रूपए के अनुद्धृत निवेशशामिल हैं। उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य रूपए 6,35,03,671 है।

अन्य निधियों में 26,67,82,815 रूपए की राशि का निवेश अनुद्धृत निवेश है।

7. वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त परिभाषित अंशदायी योजना का विवरण निम्नानुसार है:

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान रु.76,29,658 (पिछले वर्ष रु. 65,27,159)

पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान रु.9,35,000 (पिछले वर्ष रु. 10,15,999)

एक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है। देनदारी के वर्तमान मूल्य का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के रूप में स्वीकृत किया गया है और अंतिम देनदारी निर्मित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा गया है। छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी को इसी तरीके से ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत किया गया है।

तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मूल बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नानुसार हैः

क) आर्थिक अनुमान

मूल पूर्वानुमान इस प्रकार हैं (1) छूट की दर (2) वेतन वृद्धि। छूट वृद्धि लेखाकरण तिथि को सरकारी बंधपत्रों पर उपलब्ध बाजार अर्जन पर उस शर्त पर आधारित है जो देयताओं की शर्तों से मिलती हों और वेतन वृद्धि में मूल्यवृद्धि, वरिष्ठता, प्रोन्नति और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, अक्षमता के लिए कोई सुस्पष्ट भत्ते का उपयोग नहीं किया गया है।

	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
i)	छूट की दर	6.75%	7.75%
ii)	भावी वेतन वृद्धि	8.00%	9.50%
iii)	ग्रैचुइटी के लिए योजना परिसम्पत्तियों की प्रत्याशित प्रतिफल दर (वित्त पोषित)	6.75%	7.75%
ख)	जन सांख्यिकी अनुमान	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
i)	सेवा निवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
ii)	मृत्यु सारणी	आई ए एल एम 2012-14	आई ए एल एम 2006-08
			अल्टीमेट
iii)	निकासी दर (प्रतिवर्ष)	2.00%	6.50%

8. गत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी इन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक हो, पुनर्निर्मित, पुनप्रतिशत समूहबद्ध, पुनः व्यवस्थित और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

कृते राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(बी.एस.रावत)	(अलका माट्टा)	(डॉ पिनाकी चक्रबर्ती)	(डॉ उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	सचिव	निदेशक	अध्यक्ष

समान तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अनीश आशीष एंड कं०

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 002535एन

(आशीष गुप्ता)

सदस्य

सदस्यता सं.503829

यूडीआईएन: 20503829AAAABL3105

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 18 नवंबर 2020

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली

(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान)

18/2, सत्संग विहार मार्ग,

स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया (निकट जेएनयू)

नई दिल्ली 110067

दूरभाष : 011 26569303, 26569780, 26569784

फैक्स : 91-11-26852548

ईमेल : nipfp@nipfp.org.in

वेबसाइट: www.nipfp.org.in